599
9.6.64

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

3rd

LOK SABHA DEBATES

[सातवां सत्र
Seventh Session]

Preservation Unit.
Fumigated
On 21-5-92
Parliament Library

[खंड २६ में अंक ११ से २० तक हैं
Vol. XXVI contains Nos. 11—20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वादविवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिय गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची

अंक १७—मंगलवार, ३ मार्च, १९६४/१३ फाल्गुन, १८८५ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

	विषय	पृष्ठ
***तारांकित प्रश्न संख्या**		
३९४	श्री वालकॉट का भाग निकलना	१२७५–७६
४१३	वालकॉट की गिरफ्तारी	१२७६—७८
३९५	नेपाल के साथ हवाई समझौता .	१२७९—८१
३९६	टेलीफोन एक्सचेंज	१२८१—८३
३९७	हल्दिया पत्तन	१२८३—८६
३९८	कृषि उत्पादन . .	१२८६–८७
४००	राज्य द्वारा खाद्यान्न का व्यापार	१२८८—९१
४०१	"करोड़ों व्यक्तियों के लिये भोजन"	१२९१—९५
४०२	खाद्यान्नों का प्रति एकड़ उत्पादन .	१२९५—९८
४०३	किसानों को ऋण .	१२९८—१३००
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
४	नई दिल्ली में टेलीफोन लाइनें लगाना .	१३००—०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या		
३९९	पोर्ट ब्लेयर में संचार प्रणाली . . .	१३०४
४०४	माल-डिब्बे का विस्फोट .	१३०४–०५
४०५	भुज में भूकम्प वेधशाला	१३०५
४०६	रेलवे वर्कशाप	१३०५–०६
४०७	पर्यटन केन्द्रों के लिए विमान सेवायें	१३०६
४०८	नौवहन सेवा	१३०६–०७

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

CONTENTS

No. 17—*Tuesday, March* 3, 1964/*Phalguna* 13, 1885 (*Saka*).

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS—

*Starred Question Nos.	Subject	Pages
394	Escape of Mr. Walcott	1275-76
413	Arrest of Walcott	1276—78
395	Air Pact with Nepal	1279—81
396	Telephone Exchanges	1281—83
397	Haldia Port	1283—86
398	Agricultural Production	1286-87
400	State Trading in Foodgrains	1288—91
401	" Food for Millions "	1291—95
402	Per Acre Yield of Foodgrains	1295—98
403	Credit to Farmers	1298—1300

Short Notice Question No.		
4	Installation of Telephone Lines in New Delhi	1300—04

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—

Starred Question Nos.		
399	Communication System in Port Blair	1304
404	Explosion of a wagon	1304-05
405	Earthquake Observatory at Bhuj	1305
406	Railway Workshops	1305—06
407	Air Services to Tourist Centre	1306
408	Shipping Service	1306-07

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

	विषय	पृष्ठ
***तारांकित प्रश्न संख्या**		
४०६	गेहूं का उत्पादन	१३०७
४१०	सहकारी आन्दोलन	१३०७–०८
४११	कलकत्ता कोयला गोदी . . .	१३०८–०६
४१२	डाक तथा तार कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त समय कार्य योजना	१३०६
४१४	तटीय नौवहन सेवा .	१३०६
४१५	राष्ट्रीय रक्षा कोष के लिए मनीआर्डर . .	१३१०
४१६	एयर इंडिया के लिये अमरीकी "सुपरसोनिक" विमान	१३१०
अतारांकित प्रश्न संख्या		
७५२	बिना टिकट यात्रा . .	१३११
७५३	उत्तरी अन्दमान के वन . .	१३११–१२
७५४	वाणिज्यिक नौवहन अधिनियम के अन्तर्गत छूट	१३१२
७५५	आन्ध्र में राष्ट्रीय राजपथ — .	१३१२–१३
७५६	आन्ध्र प्रदेश में टेलीफोन	१३१३
७५७	तम्बाकू की खेती	१३१३–१४
७५८	कोचीन बन्दरगाह	१३१४
७५६	कालीकट–मद्रास ट्रंक सर्किट	१३१४
७६०	खाद्य उद्योग . .	१३१५
७६१	दिल्ली में चीनी और गुड़ का वितरण	१३१५
७६२	रेलवे लाइन का मोड़ा जाना . .	१३१५–१६
७६३	वनों का विकास	१३१६
७६४	सवारी भत्ता	१३१६
७६५	सहकारी क्षेत्र में कमी . . .	१३१७
७६६	पर्यटक मार्ग-दर्शक	१३१७
७६७	लाल किला . . .	१३१७
७६८	दिल्ली स्टेशन तक शटल रेलगाड़ियां .	१३१७–१८
७६६	रेलवे ट्रकों की विद्युतीकरण लागत .	१३१८
७७०	आसाम में स्वचालित टेलीफोन पद्धति .	१३१८–१६
७७१	बिजली से चलने वाली रेलगाड़ियां .	१३१६

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*contd.*

	Subject	Pages
Starred Question Nos.		
409	Production of wheat	1307
410	Cooperative Movement .	1307-08
411	Calcutta Coal Docks	1308-09
412	Overtime Scheme for P. & T. Employees .	1309
414	Coastal Shipping Service . . .	1309
415	Money Orders for National Defence Fund	1310
416	U. S. Supersonics for Air India . .	1310
Unstarred Question Nos.		
752	Ticketless Travel	1311
753	North Andamans Forests	1311-12
754	Exemptions under Merchant Shipping Act .	1312
755	National Highways in Andhra	1312-13
756	Telephones in Andhra Pradesh .	1313
757	Cultivation of Tobacco . .	1313-14
758	Cochin Harbour	1314
759	Calicut-Madras Trunk Circuits .	1314
760	Food Industries	1315
761	Distribution of Sugar and Gur in Delhi . .	1315
762	Dislocation of Railway Line . .	1315-16
763	Development of Forests	1316
764	Conveyance Allowance	1316
765	Shortfall in Cooperative Sector	1317
766	Tourist Guides . .	1317
767	Red Fort . . .	1317
768	Shuttle Trains upto Delhi Station	1317-18
769	Electrification Cost of Railway Tracks .	1318
770	Automatic Telephone System in Asaam .	1318-19
771	Electric Trains	1319

प्रश्नों के लिखित उत्तर--क्रमशः

विषय-सूची

*तारांकित प्रश्न संख्या		पृष्ठ
७७२	सफेद मिर्च	१३१९–२०
७७३	काजू का उत्पादन	१३२०
७७४	रेलवे कर्मचारियों को मकान बनाने के लिए ऋण	१३२०–२१
७७५	आमों को डिब्बों में बन्द करने के केन्द्र	१३२१
७७६	गोधरा के निकट रेल पटरियों को फिश प्लेटें	१३२१
७७७	कृष्णा नदी पर पुल	१३२२
७७८	अमरीका से गेहूं की खरीद	१३२२
७७९	आगरा में राष्ट्रीय राजपथ संख्या २ पर उपमार्ग के लिये भमि का अर्जन	१३२२
७८०	मालाबार क्षेत्र में हवाई-अड्डा	१३२२–२३
७८१	भारतीय वन अधिनियम का संशोधन	१३२३
७८२	चावल के बोरों की चोरी	१३२३–२४
७८३	मंडीकोटला के समीप गाड़ी का पटरी से उतर जाना	१३२४
७८४	सियालदह से रानाघाट तक बिजली से चलने वाली रेलगाड़ियां	१३२४
७८५	उत्तर प्रदेश में चीनी मिलें	१३२४–२५
७८६	सूरत में हवाई क्षेत्र	१३२५
७८७	उत्तर रेलवे पर हाल्ट स्टेशन	१३२५
७८८	रोपड़–नंगल बांध लाइन	१३२५–२६
७८९	डेरी परियोजना	१३२६
७९०	रतलाम से गोधरा तक रेलवे लाइन	१३२६–२७
७९१	उर्वरक प्रदर्शन कार्यक्रम	१३२७
७९२	तूतीकोरिन विकास योजना	१३२७–२८
७९३	प्रति एकड़ उर्वरकों का उपयोग	१३२८
७९४	गुब्बारे नुमा खाद्यान्न स्टोर	१३२८
७९५	उर्वरक के रूप में गोबर	१३२९
७९६	रेलवे के पुर्जों का निर्माण	१३२९
७९७	आसाम सरकार का ज्ञापन	१३२९–३०
७९८	अन्तर्राज्य परिवहन कर	१३३०
७९९	गाजियाबाद–दिल्ली मार्ग पर रेलगाड़ियां	१३३१

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*contd.*

Unstarred Question Nos.	Subject	Pages
772	White Pepper . .	1319-20
773	Cashewnut Production . .	1320
774	House Building Loans to Railway Employees	1320-21
775	Mango Canning Centre . . .	1321
776	Fish Plates on Railway Track Near Godhra	1321
777	Bridge Across Krishna .	1322
778	Purchase of Wheat from U. S. A. . . .	1322
779	Acquisition of land for Byepass at Agra on National Highway No. 2.	1322
780	Aerodrome in Malabar Area .	1322-23
781	Amendment of Indian Forest Act	1323
782	Theft of rice bags . .	1323-24
783	Derailment of Train near Mundikotla	1324
784	Electric Trains from Sealdah to Ranaghat .	1324
785	Sugar Mills in U. P.	1324-25
786	Airfield at Surat . . .	1325
787	Halt Stations on Northern Railway .	1325
788	Rupar-Nangal Dam Line .	1325-26
789	Dairy Project .	1326
790	Railway Line from Ratlam to Godhra .	1326-27
791	Fertiliser Demonstration Programmes .	1327
792	Tuticorin Development Scheme .	1327-28
793	Utilisation of Fertilizers per acre .	1328
794	Balloon Grain Store.	1328
795	Cowdung as Fertiliser . .	1329
796	Manufacture of Railway Components	1329
797	Asaam Government Memorandum . .	1329-30
798	Inter-State Transport Taxes	1330
799	Trains on Ghaziabad—Delhi Route	1331

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

	विषय-सूची	पृष्ठ
*तारांकित प्रश्न संख्या		
८००	मुर्गीपालन फार्म कार्यक्रम	१३३१
८०१	रेलों में सोने के लिये स्थान	१३३२
८०२	सस्ते रेडियों सेटों के लाइसेंस	१३३२
८०४	मद्रास में 'कैरेवल' विमान को न उड़ाना	१३३२–३३
८०५	रेलगाड़ियों में रेडियो लगाना	१३३३
८०६	दिल्ली से मद्रास को गाड़ियां	१३३३
८०७	नई रेलवे लाइनें	१३३४
८०८	अस्पृश्यता	१३३४
८०९	पंजाब में डाकघरों का दरजा बढ़ाया जाना	१३३४
८१०	प्रगतिशील किसान की—तालिका	१३३४–३५
८११	बूचड़खाने	१३३५
८१२	गुजरात में नलकूपों की खुदाई	१३३५–३६
८१३	गाड़ी में लगी वस्तुओं की चोरी	१३३६
८१४	बीकानेर स्टेशन पर ऊपरी पुल	१३३६
८१५	उपभोक्ता सहकारी भंडार	१३३६
८१६	तीरा	१३३७
८१७	मिलों को गन्ने का सम्भरण	१३३७
८१८	बिना टिकट यात्रा	१३३७
८१९	भविष्य निधि का भुगतान	१३३८
८२०	पाकिस्तान को भेजे गये रेलवे बैगन	१३३८–३९
८२१	स्मृति टिकट	१३३९
८२२	'कैरेवल' सेवायें	१३३९
८२३	चीनी	१३३९
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना		
	श्री टैलबॉट की भारत–यात्रा	१३४०
	श्री यशपाल सिंह	१३४०
	श्री लाल बहादुर शास्त्री	१३४०
सभा पटल पर रखा गया पत्र		१३४०

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*contd.*

Unstarred Question Nos.	Subject	Pages
800	Poultry Farm Programme	1331
801	Sleeping Berths	1332
802	Licence for Cheap Radio Sets	1332
804	Grounding of Caravelle Plane at Madras	1332-33
805	Installation of Radio Sets in Trains	1333
806	Trains from Delhi to Madras	1333
807	New Railway Line	1334
808	Untouchability	1334
809	Upgrading of Post Offices in Punjab	1334
810	Panel of Progressive Farmers	1334-35
811	Slaughter Houses	1335
812	Drilling of Tubewells in Gujarat	1335-36
813	Thefts of Coach Fittings	1336
814	Over-bridge at Bikaner Station	1336
815	Consumers Cooperative Stores	1336
816	Neera	1337
817	Supply of Sugarcane to Mills	1337
818	Ticketless Travelling	1337
819	Payment of Provident Fund	1338
820	Railway Wagons sent to Pakistan	1338-39
821	Commemoration Stamps	1339
822	Caravelle Services	1339
823	Sugar	1339

Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance

Mr. Talbot's visit	1340
Shri Yashpal Singh	1340
Shri Lal Bahadur Shastri	1340

Paper laid on the Table 1340

विषय-सूची

	पृष्ठ
लोक लेखा समिति	१३४०
बीसवां प्रतिवेदन	१३४०
सभापति तालिका	१३४१
दिल्ली राज्य केन्द्रीय सहकारी स्टोर द्वारा किये गये गुड़ के सौदे के बारे में वक्तव्य	१३४
श्री अ० कु० सेन	१३४२–४३
बोनस आयोग के प्रतिवेदन के बारे में वक्तव्य	१३४३
श्री चे० रा० पट्टाभिरामन	१३४३
विनियोग (रेलवे) विधेयक, १९६४—पारित	१३४३–४५
सामान्य आय व्ययक—सामान्य चर्चा	१३४५—६२
श्री अ० क० गोपालन	१३४५—४८
श्री रवीन्द्र वर्मा	१३४८–४९
श्री भी० रु० मलानी	१३४९—५४
श्री खाडिल्कर	१३५४–५५
श्री उ० मू०त्रिवेदी	१३५६–५७
श्री रघुनाथ सिंह	१३५७–५८
श्री याज्ञिक	१३५८–५९
श्री अब्दुल वहीद	१३५९–६०
श्री रामनाथन चट्टियार	१३६०–६१
श्री पाराशर	१३६१–६२
श्री स० मो० बनर्जी	१३६२

Subject	Pages
Public Accounts Committee	1340
Twentieth Report	1340
Panel of Chairmen .	1341
Statement *re* : Delhi State Central Co-operative Stores' dealings in gur	1341
Shri A. K. Sen	1342-43
Statement *re* : Report of Bonus Commission	1343
Shri C. R. Pattabhi Raman	1343
ppropriation (Railways) Bill, 1964—Passed	1343-45
General Budget—General Discussion	1345—62
Shri A. K. Gopalan . . .	1345-48
Shri Ravindra Varma . . .	1348-49
Shri M. R. Masani	1349-54
Shri Khadilkar	1354-55
Shri U. M. Trivedi	1356-57
Shri Raghunath Singh .	1357-58
Shri Yajnik .	1358-59
Shri T. Abdul Wahid .	1359-60
Shri Ramanathan Chettiar	1360-61
Shri Prashar	1361-62
Shri S. M. Banerjee .	1362

लोक-सभा

LOK SABHA

मंगलवार, ३ मार्च, १९६४/१३ फाल्गुन, १८८५ (शक)

Tuesday, March 3, 1964/Phalguna 13, 1885 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

The Lok Sabha met at Eleven of the clock

{अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए}
{Mr. Speaker *in the Chair*}

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अध्यक्ष महोदय: श्री यशपाल सिंह :

श्री यशपाल सिंह: प्रश्न संख्या ३९४।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या ४१३ को भी इस प्रश्न के साथ में ही ले लिया जाये।

श्री वाल्काट का भाग निकलना

+

*३९४. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री म० ला० द्विवेदी:
श्री प्र० चं० बरूआ:

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २६ सितम्बर, १९६३ को सफदर जंग हवाई अड्डे से श्री वाल्कट के भाग निकलने के कारणों की जांच करने के लिए नियुक्त किये गये अधिकारियों ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

2492(Ai) LS—1.

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य उपपत्तियां क्या हैं? और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन): (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

वाल्कॉट की गिरफ्तारी

+
*४१३. श्री हरि विष्णु कामत :
श्री यशपाल सिंह:
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री नाथपाई:

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचारपत्रों के इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि श्री डेनियल बाल्काट पेरिस में गिरफ्तार कर लिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्यर्पण[1] द्वारा अथवा अन्यथा उन्हें भारत में उपस्थित कराने के लिए क्या क़दम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन): (क) श्री डेनियल एच० बाल्कट को पेरिस में गिरफ्तारी के सम्बन्ध में दिनांक १६ फरवरी, १९६४ के "टाइम्स आफ इन्डिया" में एक समाचार निकला था। पेरिस स्थित भारतीय दूतावास को मामले के सम्बन्ध में तार द्वारा संदेश भेजा गया था और उस ने इस बात की पुष्टि की है कि डेनियल एच० बाल्काट ११ फरवरी, १९६४ को फ्रांसीसी अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार कर लिये गये थे।

(ख) प्रत्यर्पण द्वारा उन्हें भारत में उपस्थित कराने के प्रश्न पर जांच हो रही है ।

Shri Yashpal Singh : Is it a fact that when Mr. Walcott went to Karachi, Pakistan Government gave him facilities for getting his statements against India published in newspapers ?

Shri Mohiuddin: I have read the statement given by him against India, but I do not know whether Pakistan Government assisted him in any way.

Shri Yashpal Singh : Do Government propose to ask for extradition in this case ?

Mr. Speaker : It has been answered.

Shri Mohiuddin : What is under consideration.

Shri Yashpal Singh : Mr. Speaker, Sir my name has also been included in the next question. Therefore, I may be permitted to ask further question.

Mr. Speaker : Shri Kamath.

[1]Extradition.

श्री हरि विष्णु कामत : मैं मंत्री महोदय का ध्यान तीन सप्ताह पहले पूछे गये उस प्रश्न की ओर दिलाना चाहता हूं जिस में मैंने यह पूछा था कि क्या सरकार ने इस बारे में जांच की है कि एयर इन्डिया दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट मेनेजर को, श्री बालकाट ने अपने विमान सहित भारत से भाग जाने के थोड़ा पहले ही दावत दी थी, और, यदि हां, तो जांच से क्या पता चला ।

श्री मुहीउद्दीन : मैंने इस बारे में कोई जांच नहीं की है । परन्तु सारा मामला जांच के लिये सरकार के एक वरिष्ट अधिकारी को सौंप दिया गया है और मैं आशा करता हूं कि अन्य बातों के साथ इस प्रश्न पर भी विचार किया जायेगा।

श्री हरि विष्णु कामत : प्रतिवेदन आयेगा कब ?

श्री मुहीउद्दीन : प्रतिवेदन सरकार को अभी तक नहीं दिया गया है । मैं नहीं कह सकता इस में कितना समय लगेगा, परन्तु मुझे आशा है कि इसमें अधिक समय नहीं लगेगा ।

श्री हरि विष्णु कामत : श्री बाल्काट के भाग निकलने के पश्चात् क्या सफदरजंग हवाई अड्डा और उसके आस पास सुरक्षा प्रबन्ध कड़े कर दिये गये हैं और यदि हां, तो किस प्रकार से?

श्री मुहीउद्दीन : जी, हां, प्रबन्ध कड़े कर दिये गये हैं, परन्तु यह बताना कठिन है कि किस प्रकार से कड़े कर दिये गये हैं। क्षेत्रों के संरक्षण के लिये पुलिस और अन्य अभिकरणों द्वारा प्रबन्ध किये गये हैं।

श्री रंगा : मेरे माननीय मित्र श्री कामत ने जब कि सभा में एक सुझाव दिया तो क्या सरकार का यह कर्त्तव्य नहीं है कि मामले में जांच करने के लिये नियुक्त किये गये अधिकारी को इसकी सूचना दे और जांच के समय ये बातें उनकी जानकारी में लाएं ?

श्री मुहीउद्दीन : वह प्रश्न और उत्तर संबंधित अधिकारी को जानकारी और आवश्यक कार्यवाही के लिये भेज दिये गये हैं।

श्री कपूर सिंह : क्या इस अफवाह में कोई सचाई है कि श्री बाल्काट के भारत से भागने के पश्चात् उन्होंने यह बताने के लिये कि हमारी सतर्कता कितनी कमजोर है एक बार फिर भारत का लम्बा दौरा किया ?

श्री मुहीउद्दीन : मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। हवाई अड्डे के अधिकारियों और पारपत्र अधिकारियों आदि से बचे बिना वह कोई दौरा नहीं कर सकते थे।

श्री कपूर सिंह : वह इस से इन्कार करने की स्थिति में नहीं है ।

परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): मेरा विचार है कि इसका गलत असर पड़ेगा । हमारे पास कोई जानकारी नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय: तो मंत्री महोदय साफ साफ मना क्यों नहीं करते कि यह सच नहीं है । एक ओर तो सरकार डरती है कि इसका गलत असर पड़ेगा . . .

श्री राज बहादुर: यह सच नहीं है ।

श्री हेम बरुआ : इस बात को ध्यान मे रखते हुए कि श्री बाल्काट ने पाकिस्तान में हमारे सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाये हैं —उसने उन्हें भ्रष्टाचारी भी बताया है —क्या मैं जान सकता हूं कि भारत सरकार के उच्च अधिकारी को, जिसे कि मामले की जांच करने के लिये कहा गया है, श्री बाल्काट द्वारा लगाये गये विशेष आरोप की जांच करने के लिये हिदायत दे दी गई है ?

श्री मुहीउद्दीन : उससे सारे मामले मैं जांच करने के लिए कहा गया है, और मुझे विश्वास है कि यदि इस बारे में कोई शक या संदेह होगा तो वह उसकी जांच करेंगे ।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : श्री बाल्काट के प्रत्यर्पण के प्रश्न पर किस स्तर पर विचार हो रहा है ? पेरिस से श्री डेनियल बाल्काट के प्रत्यर्पण के प्रश्न को अंतिम रूप देने में इतनी देर क्यों हो रही है ? क्या प्रत्यर्पण तब दिया जायेगा जब वह पेरिस से चले जायेंगे ?

श्री मुहीउद्दीन : प्रत्यर्पण संधियां अलग अलग देश के साथ अलग अलग होती हैं।

श्री बाल्काट का कहीं कोई पता नहीं लगता था पहले हम ने अमरीकी सरकार से बातचीत की थी, और मैं सभा को पहले ही सूचना दे चुका हूं कि अमरीकी सरकार ने सहायता का बचन दिया था, और अब यह पता लगा है कि वह अब फ्रांस में हैं। अतः फ्रांस के साथ संधि अलग प्रकार की है और, जैसा कि मैंने बताया इस पर जांच हो रही है ।

श्री शिव नारायण : श्री बाल्काट के भागने के पश्चात, सफदर जंग हवाई अड्डे पर क्या विशेष प्रबन्ध किये गये हैं ?

श्री मुहीउद्दीन : मैं सभा को बता चुका हूं ।

श्री बी० चं० शर्मा : क्या श्री बाल्काट का अमरीका को प्रत्यर्पण किया जायेगा और फिर हम इस प्रश्न पर अमरीका सरकार से बात चीत करेंगे अथवा क्या उसका यदि संभव हुआ ,सीधे ही भारत में प्रत्यर्पण किया जायेगा । और क्या उसे पेरिस में हमारी शिकायत पर गिरफ्तार किया गया अथवा अन्य किसी शिकायत पर ?

श्री मुहीउद्दीन : जहां तक मुझे ज्ञात है पेरिस में उन्हें किसी अन्य शिकायत पर गिरफ्तार किया गया है । प्रत्यर्पण का अर्थ यह है कि उस देश को प्रत्यर्पण किया जाय जिस मे अपराध किया गया है।

श्री महेश्वर नायक: श्री बाल्काट के हवाई अड्डे पर आने और वहां से उड़ान करने के समय में काफी अन्तर था । क्या जांच अधिकारी के लिये जिम्मेदारी निर्धारित करने से पूर्व इसकी जांच करना आवश्यक नहीं था ? इस बात का पता क्यों नहीं लगा कि क्या कुछ व्यक्ति जो इस काम पर थे बाल्काट के विमान में बैठने के लिये जिम्मेदार थे ?

श्री मुहीउद्दीन : यही तो जांच का विषय है।

Shri Yashpal Singh : Pakistan Government has helped fugitive from Indian Justice. What action our Government has taken against that Government ?

Mr. Speaker : Next question.

नैपाल के साथ हवाई समझौते

\+

*३९५. श्री यशपाल सिंह :
श्री धवन:
श्री बिशनचंद्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव:
श्री श्रीनारायण दास:
श्री प्र० चं० बरुआ:
श्री दी० चं० शर्मा:
श्री श्यामलाल सर्राफ:

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नैपाल के विदेश मंत्री ने भारत से एक हवाई समझौता करना चाहा है;

(ख) यदि हां, तो उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) समझौते पर कब हस्ताक्षर किये जाने की संभावना है ?

परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन): (क) नैपाल सरकार से भारत और नैपाल के बीच एक हवाई यातायात करार करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ख) तथा (ग). भारत सरकार ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया है। करार के विस्तृत विवरण की जांच हो रही है।

Shri Yashpal Singh : What are the main terms of the agreement which we are going to conclude with Nepal ?

Shri Mohiuddin : It is not possible to describe the main terms at this time. It depends upon the negotiations. We shall negotiate about the matter with them and then decide.

Shri Yashpal Singh : Is Government aware that Nepal has concluded a similar agreement with Pakistan as well and how these two things can go together ?

Shri Mohiuddin : It is understood that the agreement has been concluded.

श्री श्यामलाल सर्राफ : दोनों देशों के बीच जिस करार पर हस्ताक्षर किये जा रहे हैं क्या उसमें केवल सवारी और मालवाहक सेवाएं ही होंगी अथवा कुछ अन्य बातें भी होंगी ?

श्री मुहीउद्दीन: यह एक असैनिक उड्डयन करार है, और असैनिक उड्डयन करार में मुख्यत: सवारी सेवा होती है और यदि आवश्यक हो तो मालवाहक सेवा भी होती है।

श्री दी० चं० शर्मा: जहां तक मैं जानता हूं नैपाल का चीन के साथ भी एक हवाई समझौता है। क्या नैपाल के साथ हवाई समझौता करने से हम कुछ कठिनाइयों में नहीं पड़ जायेंगे और क्या उनके लिये हमारे देश में चीनी राष्ट्रजनों और चीनी माल को भेजन असम्भव नहीं हो जायेगा ?

श्री मुहीउद्दीन : मैं चीन के साथ किसी करार से अवगत नहीं हूं । परन्तु, हां, कुछ ऐसे देश भी हैं जिनके चीन जैसे और अन्य देशों के साथ करार हैं, और हम उनके साथ करार करने के लिये इनकार नहीं करते । जहां तक चीनी राष्ट्रजनों और अन्य व्यक्तियों के आने का सम्बन्ध है, इस पर अन्य नियमों द्वारा नियंत्रण किया जाता है ।

श्री रामनाथन चेट्टियार : क्या नेपाल ने हाल ही में पाकिस्तान के साथ कोई करार किया है और क्या काठमांडू और ढाका के बीच एक हवाई सेवा चालू की जायेगी ?

श्री मुहीउद्दीन : मेरा विचार है समझौता हुआ है, मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता । मैं विस्तृत विवरण से पूर्णतया अवगत नहीं हूं क्योंकि दो देशों के बीच करार की प्रतियां देर से प्राप्त होती हैं । अभी मेरे पास करार का विस्तृत विवरण नहीं आया है ।

श्री विश्वनाथ राय : प्रस्ताव के सम्बन्ध में अब तक जो सरकार को जानकारी प्राप्त हुई है उसको ध्यान में रखते हुए क्या नेपाल–भारत विमान सेवा इन्डियन एयर लाइन्स के विस्तार के रूप में होगी अथवा इसे दोनों देशों के सहयोग से चलाया जायेगा ?

श्री मुहीउद्दीन : इस समय सहयोग का कोई प्रश्न नहीं है । इस समय अस्थायी पर्मिट पद्धति के अन्तर्गत रायल नेपाल एयरलाइन्स अपने विमान चला रही है और हम भी नेपाल होकर अपने विमान चला रहे हैं । इस अस्थायी पर्मिट पद्धति को बदलने के लिये अब एक करार करने का प्रस्ताव है ।

श्री कपूर सिंह : प्रस्तावित करार की भावनाओं के संदर्भ में, क्या अब नेपाल भारत के साथ अपने पुराने भौगोलिक-राजनैतिक सम्बन्धों को पूर्णतया निभाने के लिये इच्छुक है ? मंत्री इसकी हंसी उड़ा रहे हैं । यह एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन अपनी-अपनी राय है ।

श्री कपूर सिंह : जी, नहीं; यह सरकार के द्वारा इस समझौते के मूल्यांकन का मामला है और सरकार के मूल्यांकन के बारे में सभा जानना चाहती है ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस में संदेह नहीं है । श्री हरिश्चन्द्र माथुर ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : उपमंत्री महोदय ने बताया कि पाकिस्तान और नेपाल के बीच करार की शर्तों के बारे में उन्हें पता नहीं है और दो विदेशों के बीच करार की शर्तें कुछ बाद में ही मिलती हैं । क्या इस मामले में भारत का सीधा सम्बन्ध नहीं है क्योंकि ढाका और काठमांडू के बीच उड़ान हमारे देश पर से होकर होगी ? यदि ऐसा है, तो क्या यह प्रथा नहीं है कि संबंधित देश के साथ बातचीत की जाये ? इस बारे में हमारी सरकार का क्या रवैया है ?

श्री मुहीउद्दीन : मैं नहीं समझता कि इस प्रश्न का क्या अर्थ निकलता है । यदि माननीय सदस्य का यह तात्पर्य है कि चीन के साथ वायु समझौते का मतलब . . . .

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मैं नेपाल–पाकिस्तान करार के बारे में पूछ रहा हूं । ढाका और काठमांडू के बीच जो भी उड़ान होगी वह हमारे प्रदेश के ऊपर से होगी ।

श्री मुहीउद्दीन: जैसा कि मैं बता चुका हूं, मुझे करार के ब्योरे का पता नहीं है । परन्तु जहां तक नियमित, अनुसूचित सेवाओं का सम्बन्ध है, वे सामान्यतः अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक उड्डयन

संगठन के नियमों पर होती हैं, चाहे वे पाकिस्तान की सेवा हो या नेपाल की। इस समय नेपाल एयर लाइन्स के विमान भारत आते हैं और हमारे विमान नेपाल जाते हैं। जहां तक तीसरे देश के विमानों का सम्बन्ध है, मुझे पूरा पता नहीं है। यदि ये किसी देश की, जो कि अन्तर्राष्ट्रीय उड्डयन संघ का सदस्य भी है, अनुसूचित सेवाएं हैं तो उन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।

परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): नेपाल, पाकिस्तान और भारत सभी अन्तर्राष्ट्रीय उड्डयन संघ के सदस्य हैं और प्रथम तथा द्वितीय वायु सेवा स्वतंत्रता इसके सदस्यों को दी जाती है। दो देशों के बीच हुए करारों को सामान्यतः अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक उड्डयन संघ को भेजा जाता है। और फिर वहां से हमें प्रतियां मिलती हैं। इस आधार पर ये उड़ानें की जाती हैं और वायु करार किये जाते हैं।

श्री हरि विष्णु कामत: मेरा एक औचित्य प्रश्न है। प्रश्न काल के लिये सभा में आने से पूर्व मंत्री महोदय एक साथ बैठ कर यह निश्चय नहीं कर पाते कि सभा में प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार दिया जायेगा। यदि ऐसा किया जाये तो समय की भी बचत होगी और उत्तर भी आपस में विरोधी नहीं होंगे। क्या आप उन्हें इस बारे में परामर्श देंगे?

अध्यक्ष महोदय: इस में कोई औचित्य प्रश्न नहीं है। उन्होंने यह कह कर बाधा डाली कि वह एक औचित्य प्रश्न उठाना चाहते हैं।

श्री हरि विष्णु कामत: यह एक प्रक्रिया का मामला है। एक मंत्री एक प्रकार से उत्तर देता है और दूसरा मंत्री किसी और प्रकार से। कल भी ऐसा ही हुआ था।

अध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं।

टेलीफोन एक्सचेंज

+

*३९९. { **श्री विश्राम प्रसाद:**
श्री राम हरख यादव: }

क्या डाक और तार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विभिन्न नगरों में कुछ और टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का निर्णय किया है;

(ख) क्या विभिन्न नगरों में "ट्रंक डायलिंग" (सीधा टेलीफोन सम्पर्क) प्रणाली चालू करने की भी कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो कितने एक्सचेंज खोले जायेंगे तथा किन-किन नगरों को सीधे टेलीफोन सम्पर्क (ट्रंक डायलिंग) द्वारा मिलाया जायेगा?

डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती): (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) धीरे-धीरे देश के सभी बड़े-बड़े स्वचालित एक्सचेंजों के बीच अभिदाता सीधा टेली-

फोन सम्पर्क चालू करने का उद्देश्य है । इस समय यह सुविधा—

१. दिल्ली—आगरा
२. कानपुर—लखनऊ

के बीच है ।

Shri Vishram Prasad : There are other big cities also in India besides Lucknow and Kanpur. How much time will it take to link them ?

When would other cities be connected with direct dial system like Kanpur and Lucknow ?

श्री भगवती : हम कुछेक चुने हुए मार्गों के बीच एक अन्तरिम योजना चलाने का प्रयास कर रहे हैं जैसे कि दिल्ली-कानपुर, दिल्ली-लखनऊ, आगरा -कानपुर, आगरा -लखनऊ, कानपुर-वाराणसी, दिल्ली-जयपुर, और दिल्ली-मेरठ । आई० टी० आई० को कुछ उपकरणों के लिये आदेश दे दिया गया है । कुछ मिल चुके हैं । सारा उपकरण मिलने पर इस काम को पूरा किया जायेगा । दीर्घकालीन उपाय के रूप में हम दिल्ली-बम्बई, दिल्ली-जालन्धर, बम्बई-मद्रास, मद्रास-कायम्बटूर, बम्बई-नागपुर और बम्बई-इन्दौर जैसे प्रमुख मार्गों पर अब हम समाक्ष केबल्स लगा रहे हैं । कलकत्ता-आसाम खंड तथा शिमला की तरफ और श्रीनगर के रास्तों पर भी हम सूक्ष्म तरंग सम्पर्क स्थापित कर रहे हैं । इन सब के पूरा होने पर हमारे पास सहायक सर्कट काफी हो जायेंगे । तब उन मार्गों पर हमारा अभिदाता डायलिंग आरम्भ करने का विचार है । उसके लिये हमारे पास मद्रास, बम्बई, दिल्ली और कानपुर में स्वचालित ट्रंक एक्सचेंज है उसमें कुछ समय लगेगा । काम के लिये टेंडर हम मंगवा रहे हैं ।

Shri Vishram Prasad : How much time will it take to introduce this scheme ?

The Minister of Law ((Shri A. K. Sen) : At least three or four years.

Shri Sarjoo Pandey : In view of the fact that there is a great demand for telephone in the cuntry and all the applications keep pending in the offices, would Government expedite the matter so that people may get telephones early ?

Shri A. K. Sen : We are trying to expedite.

Shri Prakash Vir Shastri : Is there any provision for having direct telephone link between Delhi and the adjoining township likes Faridabad and Gurgaon as has been done between Delhi and Ghaziabad ?

Shri A. K. Sen : We hope so.

Shri Tulshidas Jadav : It is profitable to give telepphone connections and they are in great demand in the country. Why is this demand not being met ?

श्री भगवती : संसाधनों की कमी है । हमें पूरे उपकरण नहीं मिलते । बंगलौर में अपने कारखाने में हम अब उपकरण नहीं बना रहे हैं । विश्व बैंक से सहायता ले कर हम कुछ उपकरणों का आयात भी कर रहे हैं । मांग को पूरा करने का हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं ।

Shri Vishwanath Pandey : What would be the total expenditure on this scheme ?

Mr. Speaker : He has given that.

Shri Braj Bihari Mehrotra : It was stated two years ago that Delhi would be linked with Kanpur and Lucknow with dial system. May I know how long it will take ?

श्री भगवती : ठीक समय तो मैं नहीं बता सकता; मैं तो इतना ही वह सकता हूं कि बहुत थोड़े समय में इसे पूरा कर दिया जायेगा ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : माननीय मंत्री ने उन नगरों के नाम बताये हैं जहां से सीधा टेलीफोन किया जा सकता है । क्या मैं जान सकता हूं कि हैदराबाद उस सूची में क्यों नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : वह तर्क कर रहे हैं ।

श्री दाजी : इस बात को देखते हुए कि कारखानों की अधिक उपकरण बनाने की क्षमता सीमित है तथा हमारी विदेशी मुद्रा की स्थिति सन्तोषजनक नहीं है, क्या हम इन उपकरणों के निर्माण के लिये एक और कारखाना स्थापित करने का विचार कर रहे हैं ?

श्री अ० कु० सेन : जी हां । सरकार एक और कारखाना खोलने का फैसला कर चुकी है ।

श्री कपूर सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या स्वचालित डायलिंग प्रणाली की स्थापना करके चंडीगढ़ को व्यक्तियों द्वारा चलाये जाने वाले टेलीफोन एक्सचेंजों के अत्याचार से मुक्त कराने का कोई प्रस्ताव है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । मैं न देशों की मुक्ति के बारे में तो सुना है परन्तु नगरों की मुक्ति के बारे में नहीं ।

श्री कपूर सिंह : चंडीगढ़ को व्यक्तियों द्वारा चलाये जाने वाले एक्सचेंजों से बहुत कष्ट हो रहा है ।

श्री हेम बरुआ : इन एक्सचेंजों में पुरुष नहीं महिलायें काम करती हैं ।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार इसके स्थान पर स्वचालित डायलिंग प्रणाली चालू करेगी ?

श्री अ० कु० सेन : श्री कपूर सिंह को इस बात पर कोई ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है । लगभग प्रत्येक नगर में स्वचालित एक्सचेंज स्थापित करने की आशा है ।

हल्दिया पत्तन

\+

*३९७. **श्री महेश्वर नायक:**
श्री दी० चं० शर्मा:
श्री रामेश्वर टांटिया:
श्री दीनेन भट्टाचार्य:
डा० उ० मिश्र:
डा० रानेन सेन :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वह दिसम्बर, १९६३ के अन्त में हल्दिया पत्तन के स्थान को देखने गये थे;

(ख) क्या पत्तन तक जाने वाली रेलवे लाइन को शीघ्रता से बनाने के लिए रेलवे मंत्रालय के साथ कोई बातचीत तय हुई है; और

(ग) पत्तन की स्थापना में अब तक क्या प्रगति हुई है तथा उस पर कितना व्यय हुआ है ?

परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी हां, ४ जनवरी, १९६४ को दौरा किया गया था ।

(ख) हल्दिया पत्तन तक एक नई रेलवे लाइन का निर्माण तीसरी योजना कार्यक्रम में सम्मिलित है । हावड़ा-खड़गपुर खंड पर पन्सपुरा नामक स्टेशन से हल्दिया पत्तन तक एक बड़ी लाइन के लिये प्रारम्भिक इंजीनियरिंग तथा अन्तिम स्थान सर्वेक्षण पूरे हो गये हैं तथा सर्वेक्षण प्रतिवेदनों की प्रतीक्षा की जा रही है । इस बीच रेलवे मंत्रालय ने ३१ जनवरी, १९६३ को लाइन के निर्माण की मंजूरी दे दी है । भूमि अर्जन का काम हो रहा है । अनुमान है कि परियोजना पर ८१४ लाख रुपये की लागत आयेगी जिसमें विद्युतीकरण की लागत की भी टेंडर सम्मिलित हैं । मार्च, १९६४ को काम पूरा होने की लक्षित तिथि निर्धारित किया गया है ।

(ग) हल्दिया पत्तन के विकास के प्रथम चरण में दी जाने वाली विविध सुविधाओं के विस्तृत आयोजन तथा विशिष्ट विवरण और दस्तावेजों की तैयारी में काफी प्रगति की गई है । विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये विश्व बैंक के पास ऋण का प्रार्थनापत्र भेज दिया गया है । प्रारम्भिक तथा अस्थायी कार्यों के लिये और निर्माण सम्बन्धी उपकरण के लिये टेंडर मंगवाये गये हैं ।

हल्दिया की पत्तन बस्ती तथा अन्त में वहां विकसित होने वाले उपनगर के साथ उसके समुचित एकीकरण की एक विस्तृत विन्यास योजना तैयार करने के लिये तथा हल्दिया में बनाई जाने वाली विभिन्न श्रेणियों की आवासी तथा गैर-आवासी इमारतों के विस्तृत डिजाइन तैयार करने के लिये भी वास्तुशास्त्रियों तथा नगर योजनाओं की एक तालिका नियुक्त की गई है । पत्तन बस्ती का खाका तैयार हो गया है जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह से इस उपनगर से दिलाया जाएगा जिसके हल्दिया में विकसित होने की संभावना है । हल्दिया में बनाई जाने वाली, विभिन्न श्रेणियों की इमारतों के डिजाइन तैयार करने में पर्याप्त प्रगति हुई है ।

हल्दिया में अनेक स्थानों पर जहां भारी बोझ उठाने वाले गहरे ढ़ांचे बनाये जाने हैं मिट्टी के गुणों को सुनिश्चित करने के लिये वहां भूछिद्रण का काम किया गया है । विभिन्न स्थानों पर धरती की शक्ति तथा अन्य गुणों के बारे में रिपोर्ट मिल गई हैं और इस तरह मिली जानकारी भारी असैनिक इंजीनियरिंग ढ़ांचों के लिये टेंडर दस्तावेजों में समाविष्ट कर दिया जायेगा । तेल जेटी के लिये नदी में छिद्रण कार्य हो रहा है ।

२९ फरवरी, १९६४ तक परियोजना पर भूमि अर्जन सहित, ६५ लाख रुपया खर्च हुआ है ।

श्री महेश्वर नायक : क्या मैं जान सकता हूं कि जब यह नया पत्तन बन जायेगा उससे कलकत्ता पत्तन के जमाव में कहां तक कमी हो जायेगी और ऐसा होने से कलकत्ता पत्तन का महत्व कहां तक कम हो जायेगा ?

श्री राज बहादुर : मैं नहीं समझता कि इस से कलकत्ता पत्तन का महत्व कम हो जायेगा। यह तो कलकत्ता पत्तन का सहायक पत्तन होगा। यह कोयले, लौह अयस्क तथा ऐसी अन्य वस्तुओं जैसे यातायात का काम करेगा।

श्रीमहेश्वर नायक : मुझे बताया गया है कि जब मंत्री महोदय हल्दिया पत्तन गये थे उन्होंने कहा था कि अधिक प्रतिकर दिया जाएगा। क्या मैं जान सकता हूं कि भूमि के अर्जन के लिये प्रतिकर के भुगतान के हेतु जो राशि बढ़ाई गई है क्या उसका ५० प्रतिशत केन्द्रीय सरकार दे रही है ?

श्री राज बहादुर : मैं समझ नहीं पाया कि प्रश्न क्या है। जहां तक प्रतिकर का संबध है, उसे पश्चिम बंगाल सरकार के सम्बन्धित प्राधिकारों द्वारा विधि के अनुसार निश्चित किया जाता है। जो भी प्रतिकर उन्हों ने तय किया है दिया जा रहा है और दिया जाएगा।

श्री वी० चं० शर्मा: विवरण में कहा गया है कि विश्व बैंक से ऋण मांगा गया है और प्रार्थना पत्र भेज दिया है। कितना ऋण मांगा गया है तथा प्रार्थना पत्र अब किस प्रावस्था में है।

श्री राज बहादुर : ऋण के लिए एक प्रार्थनापत्र विश्व बैंक में भारत के कार्यपालक निदेशक द्वारा हाल ही में विश्व बैंक को दिया गया है। हमें यह जानकारी जनवरी, १९६४ में मिली थी। जहां तक ऋण की राशि का सम्बन्ध है, यह आवश्यक रूप से पत्तन परियोजना की कुल लागत के विदेशी मुद्रा के भाग को पूरा करने के लिये है। यह लगभग १४ करोड़ रुपये हो सकती है।

श्री स० चं० सामन्त : पत्तन के लिये कितनी विदेशी मुद्रा आवश्यक होगी और रेलवे के निर्माण के लिये कितनी ?

श्री राज बहादुर : जहां तक पत्तन परियोजना का सम्बन्ध है, जैसाकि मैंने कहा, विदेशी मुद्रा १४ करोड़ रुपया होगी। रेल सम्पर्क की कुल लागत ८.१४ करोड़ रुपया है। मैं नहीं जानता कि रेल सम्पर्क के लिये कितनी विदेशी मुद्रा आवश्यक है ?

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या मैं जान सकता हूं कि परियोजना के लिये जिन लोगों की भूमि अर्जित कर ली गई है क्या उन्हें हल्दिया में बनाए जाने वाले उपनगर में आवास के बारे में वरीयता दी जायेगी ?

श्री राज बहादुर : ऐसे लोगों के दावों पर हम समुचित विचार करेंगे जो परियोजना के फलस्वरूप विस्थापित हो गए हैं। सच तो यह है कि रोजगार तथा अन्य बातों के रूप में अनेक आर्थिक लाभ विस्थापित होने वाले ऐसे लोगों को मिलेंगे।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या कांडला को निर्बाध पत्तन बनाने के प्रश्न के साथ हल्दिया को निर्बाध पत्तन बनाने का प्रश्न लिया जायेगा ? इस बात का निर्णय किस आधार पर होगा ?

श्री राज बहादुर : हम ने कांडला में एक निर्बाध व्यापार जोन बनाने का फैसला किया है जो निर्बाध पत्तन से अलग है । अन्य किसी पत्तन के बारे में ऐसा करने से पहले हमें देखना है कि यहां यह कैसा काम करता है ।

कृषि उत्पादन

\+

*३९८. **श्री महेश्वर नायक :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २६ नवम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या १८४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिन्न-भिन्न राज्यों को कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये किस तरीके से अतिरिक्त सहायता दी गई है और किस आधार पर इस का वितरण किया गया है;

(ख) क्या यह सहायता विशिष्ट प्रकार की परियोजनाओं के लिये दी गई है, और यदि हां, तो विभिन्न वर्गों की परियोजनाओं में इस का वितरण किस प्रकार किया गया है; और

(ग) विशेष कृषि सहायता के आवंटन के प्रयोजन के लिये चाय उत्पादक राज्यों का यदि कोई विशेष ध्यान रखा गया है, तो क्या ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा-सचिव (श्री शिन्दे): (क) और (ख). कृषि कार्यक्रमों के लिये आयव्ययक में सम्मिलित तथा स्वीकृत अतिरिक्त व्यय, राज्यों की सम्पूर्ण संसाधन स्थिति तथा केन्द्र द्वारा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता को देखने के बाद विभिन्न राज्यों को अतिरिक्त सहायता दी गई है ।

अतिरिक्त सहायता विशिष्ट कार्यक्रमों के लिये दी गई है, अर्थात् :

	(करोड़ रुपये)
(१) कृषि उत्पादन	०.९८
(२) लघु सिंचाई	१२.११
(३) भूसंरक्षण	२.३१
कुल	१५.४०

(ग) चाय उत्पादक राज्यों का कोई विशेष ध्यान नहीं रखा गया है ।

श्री महेश्वर नायक : केन्द्रीय सरकार राज्यों के उन पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये क्या विशेष उपाय कर रही है जहां बहुत विकास हो सकता है परन्तु अभी तक हुआ नहीं है ?

श्री शिन्दे : तीसरी पंचवर्षीय योजना बनाते समय विभिन्न राज्यों को वित्तीय आवंटन देने के लिये उन के पिछड़ेपन का ध्यान रखा गया है ।

श्री महेश्वर नायक : मेरा प्रश्न उन क्षेत्रों के बारे में था जो बहुत पिछड़े हुए हैं परन्तु जिनका विकास हो सकता है। लगता है कि इन क्षेत्रों के विकास के लिये अभी तक कुछ नहीं किया गया है। उन के विकास के लिये केन्द्र द्वारा या सम्बन्धित राज्यों द्वारा क्या विशेष कदम उठाये गये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : अतिरिक्त सहायता इस बात पर निर्भर करेगी कि विभिन्न राज्य सरकारें पहले ही इसके लिये रखी गई राशि का कहां तक इस्तेमाल कर पाती हैं। जहां तक कृषि उत्पादन का सम्बन्ध है योजना में १०० करोड़ रुपये की कुल राशि रखी गयी थी। बाद में पता चला कि कुछ राज्य सरकारें अधिक व्यय कर सकेंगी। इसलिये २७.५५ करोड़ रुपया और दिया गया है जो मुख्यतः लघु सिंचाइ और भूसंरक्षण के लिये है। अतिरिक्त सहायता १५.४० करोड़ रुपये होती है।

अध्यक्ष महोदय : लगभग ४० माननीय सदस्य प्रश्न करने के लिये खड़े हो रहे हैं। अभी कल ही हम ने कृषि पर चर्चा की थी। फिर हम सामान्य आयव्ययक पर भी चर्चा कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इसे ध्यान में रखेंगे।

Shri Bibhuti Mishra : It has just been stated by the hon. Minister that a sum of about Rs. 16 crores has been allocated for soil conservation and minor irrigation. I want to know whether the Government has prepared any scheme in collaboration with the State Governments as to how the amount should be spent for the benefit of the farmers.

श्री शिन्दे : मैं समझता हूं कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये किये जाने वाले सभी उपाय कृषिकों की सहायता करते हैं। लघु सिंचाई तथा भू-संरक्षण के उपबन्धों से भी कृषकों को ही सहायता पहुंचती है। इसलिये मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य क्यों अनुमान लगाते हैं कि इन योजनाओं से किसानों को लाभ होने की संभावना नहीं है।

श्री हरि विष्णु कामत : कागजी काम से लाभ नहीं होगा।

कई माननीय सदस्य उठे--

अध्यक्ष महोदय : मैं देखता हूं कि खड़े होने वाले माननीय सदस्यों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसलिये मैं अगले प्रश्न को लेता हूं।

श्री त्यागी : भाग्य आजमाने दीजिये।

एक माननीय सदस्य : यह गंभीर विषय है।

अध्यक्ष महोदय : विषय निश्चय ही गंभीर है। इसलिये मैं अगले प्रश्न को लेता हूं।

राज्य द्वारा खाद्यान्न का व्यापार

\+

*४००. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
डा० रानेन सेन :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का यह विचार है कि खाद्यान्नों का व्यापार राज्य द्वारा किया जाय ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Shri Bibhuti Mishra: Has the Government not considered so far to take any steps in connection with the State Trading of foodgrains in view of their present shortage ?

श्री अ० म० थामस : कल वाद-विवाद का उत्तर देते समय मेरे वरिष्ठ सहयोगी ने इसका उल्लेख किया था। अब अपनाये गये तरीके निम्नलिखित हैं :—

(क) खाद्यान्नों का रक्षित भंडार बनाना और उस का संचालन करना। ५० लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का रक्षित भंडार बनाने के पहले के निर्णय के स्थान पर अब ६० लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का रक्षित भंडार बनाने का निर्णय किया गया है जिसमें ४० लाख मीट्रिक टन गेहूं और २० लाख मीट्रिक टन चावल होगा ;

(ख) उचित मूल्य वाली दुकानों द्वारा सरकारी वितरण के क्षेत्र को विस्तृत करने तथा, यदि संभव हो, रक्षित भंडार में वृद्धि करने के लिए एक प्रकृष्ट प्राप्ति कार्यक्रम चलाना ताकि बाजार को अनुचित रूप से अव्यवस्थित किये बिना चावल तथा धान की यथासंभव अधिक से अधिक विपण्य फालतू मात्रा इकट्ठी हो सके ;

(ग) उचित मूल्य वाली दुकानों की संख्या बढ़ाना तथा अधिकाधिक उपभोक्ता सहकारी स्टोर चलाना ; और

(घ) खाद्यान्न व्यापारी लाइसेंसिंग आदेशों द्वारा खाद्यान्नों के थोक व्यापारियों तथा चावल मिलों और रोलर आटा मिलों पर अधिक कड़ा नियंत्रण रखना ।

खाद्य तथा कृषि मंत्री ने इन सब का विस्तार में उल्लेख किया था।

Shri Bibhuti Mishra : Yesterday's discussion has made it fully clear to the Government that people have hoarded foodgrains and the farmers have with them only a small quantity. In view of this fact has the hon. Minister decided, as it seems to resort to State trading in future so that they may have foodgrains ?

श्री अ० म० थामस : गल्ला अवैध रूप से इकट्ठा करने के प्रश्न का भी खाद्यान्न लाइसेंसिंग आदेश द्वारा समाधान किया जाना है। प्राप्ति के आंकड़ों की जांच पड़ताल से यदि सरकार को पता चला कि कोई विशेष व्यापारी किसी विशेष वस्तु को जमा कर रहा है तो या तो सरकार स्टाक पर कब्जा कर सकती है या स्टाक करने वालों को एक निश्चित मूल्य पर उसे बेचने या स्टाक को बाजार में ले आने का आदेश दे सकती है। ये सभी हिदायतें प्राप्ति के आंकड़ों की पड़ताल के बाद दी जा सकती हैं। इसलिये ज्यादा जरूरत इस बात की है कि खाद्यान्न लाइसेंसिंग आदेश के कुशल प्रशासन द्वारा थोक व्यापार पर अधिक कड़ा नियंत्रण रखा जाय।

श्रीमती सावित्री निगम : उन विविध उपायों के बावजूद जिन्हें इस सदन में कई बार बताया गया है सरकार चोरबाजारी करने वालों और बिचौलियों तथा खाद्यान्न के व्यापारियों के कुकर्मों पर नियंत्रण करने में सफल नहीं हो सकी है। क्या मैं जान सकती हूं कि सरकार इन बिचौलियों को बीच में से निकालने के लिये क्या कदम उठाने जा रही है ?

श्री अ० म० थामस: चोरबाजारी का कोई सवाल नहीं है क्योंकि कुछेक ऐसे राज्यों के इलावा जहां मुख्यत: प्राप्ति के प्रयोजनों के लिये अधिकतम नियंत्रण मूल्य निश्चित कर दिये गये हैं चावल तथा गेहूं के मूल्यों पर कोई नियंत्रण नहीं है। इसके अतिरिक्त कोई नियंत्रण मूल्य नहीं है ; इसलिये चोरबाजारी का प्रश्न ही नहीं उठता। हां, मुनाफाखोरी का सवाल जरूर उठता है और उस के लिये जो विभिन्न उपाय हम कर रहे हैं वे कल बता दिये गये थे। एक बहुगर्भित प्रश्न के उत्तर में यह सब कुछ बताना संभव नहीं है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : इस बात को देखते हुए कि सरकार राज्यों द्वारा खाद्यान्न के व्यापार को तत्काल ही प्रवर्तित करने का विचार नहीं रखती, मूल्यों को स्थिर रखने तथा उत्पादकों को मुनासिब मूल्यों का आश्वासन देने के लिए सरकार क्या ठोस कदम उठाना चाहती है ?

श्री अ० म० थामस : अनेक उपायों का मैंने उल्लेख किया है। सरकार न्यूनतम तथा अधिकतम मूल्य भी निर्धारित करना चाहती है तथा अधिकतम मूल्य भी प्रवर्तित करने का उस का विचार है।

Shri Vishram Prasad : The hon. Minister has stated that Government does not propose to have State trading yet. I want to know whether Government has decided about the minimum price the farmer will get for his crop and the percentage of profit which the traders will get.

Mr. Speaker : All this has been mentioned yesterday.

Shri Vishram Prasad : But its reply was not given yesterday.

Mr. Speaker : At least I got the reply and had it in full details. The reply given yesterday by Sardar Swaran Singh. . . . . .

Suri Vishram Prasad : No reply was given yesterday to this question as to what minimum price the farmer would get and what more profit the traders can earn on it.

Mr Speaker : He stated that the floor price has been fixed and as far the variation in the maximum prices, the decision would be announced as early as possible. Is this the reply or not ?

Shri Rameshwaranand: May I know whether the foodgrains dealers would not be thrown out of employment like the goldsmiths if the Government procures foodgrains directly from the farmers and enters into trade ? What effort would Government make in this regard ?

The Minister of Food and Agriculture (Shri Swaran Singh): I present Swamiji's opinion to other hon. Members.

Shri Rameshwaranand : I have asked what the opinion is.

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : किसान को न्यूनतम मूल्य मिले तथा उपभोक्ता को अधिकतम मूल्य देना पड़े इसे सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की है या करने जा रही है ?

श्री अ० म० थामस : इस समय ऐसा कोई खतरा नहीं कि किसान को न्यूनतम मूल्य से कम मिलेगा ; सच तो यह है कि जो न्यूनतम मूल्य तय किया गया है खुले बाजार के भाव उससे बहुत ज्यादा हैं। परन्तु यदि वह कम होते हैं तो हम स्वयं बाजार में आ कर खरीद लेंगे। अब भी कुछ राज्य सरकारों ने सहकारी समितियों को खुले बाजार भावों पर भी खरीदने का अधिकार दे दिया है इसलिये न्यूनतम मूल्य प्रवर्तित करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। कठिनाई तो अधिकतम मूल्य प्रवर्तित करने में आयेगी। न्यूनतम मूल्य में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि कृषक को न्यूनतम मूल्य मिले।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : अधिकतम मूल्य के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री अ० म० थामस : अधिकतम मूल्य के बारे में तथ्य यह है कि उसे खाद्यान्न लाइसेंसिंग आदेश प्रवर्तित कर के मुख्यत: प्रशासनिक व्यवस्था द्वारा ही लागू किया जायेगा। सच तो यह है कि खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन में इस बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा हुई थी। हम ने राज्य सरकारों पर जोर दिया है कि वे खाद्य विभाग में अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनायें। कुछ वर्ष पहले आरम्भ किये गये विनियंत्रण से विभिन्न राज्यों में जो व्यवस्था थी वह लगभग समाप्त हो गई है। अत: विभिन्न राज्यों में क्षीण सी व्यवस्था ही रह गई है। परन्तु हम ने राज्य सरकारों से प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए कहा है और यह भी कहा है कि केन्द्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय बोझ के बांटे जाने पर भी सोचा जा सकता है। अत:, इस बारे में हम गंभीर हैं।

Shri R. S. Pandey : May I know whether may target has been fixed under the Foodgrain Procurement scheme and if so, whether all the States have been asked to reach this target; if so, the reaction thereof ?

श्री अ० म० थामस : निस्सन्देह, कुछ लक्ष्य निर्धारित किया गया है। चालू वर्ष में हम विभिन्न राज्यों से लगभग दस लाख टन प्राप्त करना चाहते हैं।

Shri A. P. Sharma : Yesterday the hon. Minister enumerated the measures for the distribution of foodgrains etc. I want to know whether the State Governments are being directed to provide irrigation facilities at those places where they do not exist but where such facilities, if provided, can result in the production of huge quantity of foodgrains.

श्री स्वर्ण सिंह : यह कार्यवाही के लिए सुझाव है।

Shri Sarjoo Pandey: The hon. Minister gave a statement yesterday wherein he stated that even the smallest dealers of foodgrains will have to present an account and in some states it has been decided that a dealer who sells even two quintals of foodgrains will have to give an account of it. Would it not increase corruption and the small. . . . . .

Mr. Speaker: Every Member gives a long statement before asking a question. You should ask the question.

Shri Sarjoo Pandey: Is Govt. considering to fix a limit of the sale of foodgrains upto which the dealers will not be required to present accounts?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं समझता हूं कि इसे तो कल ही साफ साफ बता दिया गया था कि थोक व्यापारी को लाइसेंस देने का इरादा है फुटकर व्यापारी को नहीं। यह सच है कि जब हम अधिकतम मूल्य तय करते हैं तो उन्हें फुटकर व्यापारियों के विरुद्ध भी प्रवर्तित किया जा सकता है और किया जाना चाहिये। परन्तु जहां तक लाइसेंस देने का सम्बन्ध है, कम से कम इस समय तो केवल थोक व्यापारियों को ही लाइसेंस देने का इरादा है।

"करोड़ों व्यक्तियों के लिए भोजन"

*४०१. **श्री जेधे** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "करोड़ों व्यक्तियों के लिए भोजन" योजना को लोकप्रिय बनाने में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) कारखानों द्वारा तैयार किये जाने वाले बहुप्रयोजनीय भोजन के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा-सचिव (श्री शिन्दे) : (क) शायद माननीय सदस्य का आशय उस प्रोटीनयुक्त भारतीय बहु प्रयोजनीय भोजन से है जोकि केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय गवेषणा संस्था, मैसूर ने तैयार किया है। इसे चलते फिरते आहारपोषण प्रसार एककों, भोजन व्यवस्था प्रौद्योगिकी तथा व्यावहारिक आहारपोषण सम्बन्धी संस्थाओं, स्कूल लंच कार्यक्रमों, अस्पतालों, कल्याण केन्द्रों, अनाथालयों द्वारा तथा स्वंच्छिक अभिकरणों को सहायक अनुदान दे कर लोकप्रिय बनाया जा रहा है।

(ख) कोयम्बटूर में एक गैरसरकारी उद्योग द्वारा एक कारखाना खोला गया है जिस की क्षमता इस समय ४ टन बहुप्रयोजनीय भोजन प्रतिदिन है। केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय गवेषणा संस्था, मैसूर में भी एक अग्रिम एकक है जिस की क्षमता लगभग १ टन प्रतिदिन है। बहुप्रयोजनीय खाद्य के उत्पादन में और वृद्धि तब हो सकेगी जबकि नये एकक, जिन्हें स्थापित किया जा रहा है, नियमित रूप से कार्य करना प्रारम्भ कर देंगे तथा मांग बढ़ जायेगी।

श्री जेधे : श्रीमान जी, क्या मैं जान सकता हूं कि राज्यों ने इस योजना में कहां तक सहयोग तथा सहायता प्रदान की है ?

श्री शिन्दे : वे राज्य जिन्हें इस योजना के कार्यकरण का कार्य सौंपा गया है इसमें पर्याप्त रुचि ले रहे हैं तथा वे उन व्यक्तियों को जिन्होंने इस बहुप्रयोजनीय खाद्य को तैयार करने का कार्य चालू किया है आवश्यक सहयोग प्रदान कर रहे हैं।

श्री जेधे : क्या यह योजना तथा सरकार द्वारा चलाया गया पैकेज कार्यक्रम एक समान ही है तथा यदि हां, तो कहां तक ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस) : पैकेज कार्यक्रम से इस का कोई सम्बन्ध नहीं है। पैकेज कार्यक्रम तो कृषि का सघन विकास करने के लिए है। यह बहु प्रयोजनीय भोजन को लोकप्रिय बनाने के लिये है।

Shri Tulshidas Jadhav : What are the different constituents with their proportion from which this multipurpose food is prepared ?

श्री शिन्दे : यह मुख्यता खान योग्य मूंगफली के आटे से, जिस की मात्रा ७५ प्रतिशत होती है, बनाया जाता है। इस में २५ प्रतिशत बंगाल के चने का आटा मिलाया जाता है तथा इस में पर्याप्त मात्रा में विटामिन तथा खनिजों को मिलाया जाता है।

डा० सरोजिनी महिषी : क्या हाल में ही टेपियोका के बारे में किये गये अनुसंधान की भांति ही खाद्य प्रौद्योगिकीय गवेषणा संस्था, मैसूर में हाल ही में कोई अन्य अनुसंधान किये गये हैं ?

श्री अ० म० थामस : मैसूर की संस्था में तैयार किया गया था। वस्तुतः, मैसूर की संस्था ने अन्य प्रकार के भी बहुत से भोज तैयार किये हैं। हमारे देश के लोग भी भोजन खाते हैं उस में मुख्य दोष यह होता है कि वह पोषक नहीं होता क्योंकि उस में प्रोटीन की कमी होती है। इस प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए ही मैसूर की खाद्य प्रौद्योगिकीय गवेषणा संस्था द्वारा इस भोजन को तैयार किया गया है।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या व्यक्तियों के लिये इस बहुप्रयोजनीय भोजन को बड़े पैमाने पर तैयार करने का कोई लाभ है यदि इसके साथ साथ निर्धनता के जाल में बुरी तरह से फंसे हुए व्यक्तियों की क्रय शक्ति को बढ़ाने के लिये कोई प्रयत्न न किये जायें ?

श्री अ० म० थामस : जैसा कि मेरे साथी ने बताया है, इस भोजन में ७५ प्रतिशत खाने योग्य मूंगफली का आटा तथा २५ प्रतिशत बंगाल के चने का आटा है तथा इसका मूल्य भी अधिक नहीं है। पोलीथीन के थैले में बन्द १ किलोग्राम भोजन का मूल्य लगभग १ रुपया ५० नया पैसा है। अधिक मात्रा में, १६ किलोग्राम २४ रु० का मिलता है।

श्री त्यागी : क्या करोड़ों व्यक्ति इसके खरीदने की क्षमता रखते हैं ?

श्री अ० म० थामस : यह मुख्य आहार के अतिरिक्त है। इससे कुपोषण को दूर करने में निश्चित रूप से सहायता प्राप्त होगी यही मुख्य उद्देश्य है। वस्तुतः, यह एक सस्ता भोजन है जो कि यदि लोकप्रिय हो जाय तो काफी सीमा तक कुपोषण को दूर कर सकेगा।

श्री हरि विष्णु कामत : इसको खरीदने के लिये लोगों के पास पैसा कहां है ?

श्री अ० प्र० जैन : इस सभा के भ्रम को दूर करने के लिये तथा यह बताने के लिये कि यह करोड़ों व्यक्तियों का भोजन है नहीं, क्या मैं जान सकता हूं कि इस भोजन का दैनिक अथवा वार्षिक कुल उत्पादन कितना है तथा कितने व्यक्ति इसको खाते हैं ?

श्री अ० म० थामस : इस भोजन का मैसूर संस्था में उत्पादन १ टन प्रति दिन है। कोयमबटूर मिल में ४ टन प्रति दिन है। अब हमने इस बहुप्रयोजनीय भोजन को तैयार करने के लिए अर्थात

खाने योग्य मूंगफली के आटे के उत्पादन के लिये दो कारखाने, एक बम्बई में तथा दूसरा कोयबम्टूर में, स्थापित किये हैं। इनकी क्षमता २० टन प्रति दिन होगी प्रश्न उपलब्धता का नहीं है अपितु खपत का है ।

श्री त्यागी : प्रति खुराक इसकी क्या मात्रा है ?

श्री अ० म० थामस : कोयम्बटूर में जो निर्माता है उसने भी यह शिकायत की है कि जितना उत्पादन है, उतनी खपत नहीं हो रही है। अतः प्रश्न इस भोजन को लोकप्रिय बनाने तथा विभिन्न राज्यों में अनेक एकक स्थापित करने का है .....

श्री अ० प्र० जैन : तो फिर यह करोड़ों व्यक्तियों का भोजन कैसे है ?

श्री अ० म० थामस : कुछ राज्यों ने यह कहा है कि हम इसको तैयार करने के लिये उद्यत हैं।

श्री हो० ना० मुकर्जी : क्या सरकार की कोई ऐसी योजना है कि इस भोजन को इतना अधिक लोकप्रिय बना दिया जाय कि इसका पर्याप्त उत्पादन होने लगे तथा कम से कम स्कूल के बच्चों को तो यह निःशुल्क प्राप्त होने लगे ?

श्री अ० म० थामस : यह चीज हमारे कार्यक्रम में शामिल है तथा इस भोजन को स्कूल लंच कार्यक्रम के द्वारा भी लोकप्रिय बनाया जाता है। जो सुझाव माननीय सदस्य ने दिया है, वह एक अच्छा सुझाव है ।

श्री रंगा : क्या सरकार के कार्यक्रम में यह बात भी शामिल है कि छोटे उपक्रमों अथवा छोटे कारखाने भी इसका उत्पादन कर सकें ताकि सीमित साधनों वाले व्यक्ति विभिन्न राज्यों में इस प्रकार के कारखाने चालू कर सकें जिससे लोगों को और अधिक रोजगार मिल सकेगा ?

श्री अ० म० थामस : हमारा विचार यह है कि प्रत्येक राज्य में एक एकक स्थापित हो जाय। इसके बाद मांग के अनुसार और एकक चालू कर देना कठिन नहीं होगा। यदि गैरसरकारी व्यक्ति आगे आने के लिये तथा इस कार्य में सहयोग देने के लिये तैयार हैं, तो हमारा मंत्रालय एककों की स्थापना करने के लिये तैयार है ।

श्री मान सिंह पृ० पटेल : सरकार ने इस भोजन सम्बन्धी साहित्य को प्रकाशित करने तथा इसके उत्पादन तथा प्रयोग को लोकप्रिय बनाने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

श्री अ० म० थामस : हमने कुछ पुस्तिकायें तैयार की हैं तथा मेरा विचार है कि ये पुस्तिकायें संसद सदस्यों को दी गई थीं। यदि कोई सदस्य इच्छुक हों, तो मैं उन्हें आवश्यक साहित्य देने के लिये तैयार हूं ।

श्री मान सिंह पृ० पटेल : मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने इसको लोकप्रिय बनाने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

डा० सरोजिनी महिषी : प्रचार अपर्याप्त है।

श्री त्यागी : इस भोजन की एक पूरी खूराक का औसत मूल्य क्या होगा ?

श्री अ० म० थामस : यह भोजन किसी व्यक्ति का पूरा भोजन नहीं है।

श्री त्यागी : क्या यह भोजन गोलियों के रूप में है ?

श्री अ० म० थामस : सामान्य मुख्य भोजन के अतिरिक्त, जैसा मैंने बताया, यह कुछ मात्रा में प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिये प्रयोग में लाया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : श्री चतुर्वेदी।

डा० मा० श्री० अणे : तब फिर हम इसको भोजन क्यों कहते हैं ?

श्री श० ना० चतुर्वेदी : लोगों द्वारा सामान्यतया खाये जाने वाले भोजन की इतनी ही मात्रा के मुकाबले इस १ किलोग्राम भोजन से कितनी अतिरिक्त कैलोरीज प्राप्त होती हैं ?

श्री अ० म० थामस : वह मैं नहीं बता सकता। यह बताया गया है कि इसमें प्रोटीनयुक्त ७५ प्रतिशत खाने योग्य मूंगफली का आटा तथा २५ प्रतिशत बंगाली चने का आटा है .....

श्री श० ना० चतुर्वेदी : मैं इसका स्पष्टीकरण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या वह स्पष्टीकरण पहले चाहते हैं और उत्तर बाद में ?

श्री अ० म० थामस : यह विटामिन तथा खनिजों से युक्त है।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : इसको "करोड़ों व्यक्तियों का भोजन" कहा जाता है। यदि इसका उपयोग गरीब लोग करते हैं, तो उनको इससे क्या पोषक तत्व प्राप्त होते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : वह एक दूसरा प्रश्न है। डा० अणे।

डा० मा० श्री० अणे : मैंने एक प्रश्न पूछा था। उन्होंने उसका उत्तर नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें उस समय प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी गई थी।

डा० मा० श्री० अणे : हम इसको "करोड़ों व्यक्तियों का भोजन" क्यों कहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि इसका उद्देश्य करोड़ों व्यक्तियों के लिये भोजन की व्यवस्था करना है। इस योजना से क्या कुछ सफलता प्राप्त होगी उसके बारे में विचार नहीं किया जाना चाहिये।

Shri Vishram Prasad: According to Nanda ji, the average per capita income of 27 crores of people of this country is seven annas while in the opinion of Dr. Lohia it is only three and a half annas. May I know the number of people for whom this food would suffice and to what extent this would meet the food shortage ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): मेरा विचार है कि हम सही स्थिति नहीं बता सके हैं। मैं इस बात को समझाने के लिये सभा से अनुमति चाहता हूं। "करोड़ों व्यक्तियों के लिये भोजन" शब्दों का प्रयोग सरकार ने नहीं किया है अपितु प्रश्नकर्ता ने अपने प्रश्न में किया है। हमने इन शब्दों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया है। **(अन्तर्व धायें)** परन्तु मैं कहना चाहता

श्री मान सिंह पू० पटेल : तो फिर सरकार ने इस प्रश्न को कैसा समझा ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। सरकार को उत्तर में यह कहना चाहिये था कि इसका अभिप्राय इस से नहीं है

श्री स्वर्ण सिंह : हमने वह स्पष्ट कर दिया है। हमारा यह अनुमान है कि वे हमसे इस प्रोटीनयुक्त भोजन के बारे में पूछ रहे हैं। तथ्य यह है कि हमारे देश में अनाज भोजन का मुख्य भाग होने के कारण, प्रोटीन कम मात्रा मे प्राप्त होता है। उस कमी को पूरा करने के लिये यह कदम उठाया गया है ताकि खाये जाने वाले अनाजयुक्त भोजन के साथ साथ इसको लेने से, विशेषतया निरामिष व्यक्तियों के लिये, प्रोटीन की कमी को पूरा किया जा सके। इसको करोड़ों व्यक्तियों के मुख्य भोजन के रूप में नहीं, इस प्रकार से समझना चाहिये।

श्री हरि विष्णु कामत : मेरा एक औचित्य प्रश्न है। माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि सरकार ने "करोड़ों व्यक्तियों के लिये भोजन" सम्बन्धी कोई योजना चालू नहीं की है। मुझे इस बात का निश्चित रूप से पता है कि सरकार की एक योजना है जिसे "करोड़ों व्यक्तियों के लिये आहार" अथवा "करोड़ों व्यक्तियों के लिये भोजन" सम्बन्धी योजना कहते हैं। बाहर एक बोर्ड भी लगा हुआ है तथा इस आन्दोलन के लिये एक विशेष अधिकारी भी नियुक्त है। इसका खंडन करने में मंत्री जी का क्या अभिप्राय है ?

श्री अ० म० थामस : वह एक गैर-सरकारी संगठन है।

अध्यक्ष महोदय : क्या इस प्रकार का कोई विज्ञापन अथवा प्रकाशन है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं इसके बारे में पता लगाऊंगा। परन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि करोड़ों व्यक्ति इस भोजन को खाते हैं ताकि प्रोटीन की कमी पूरी हो सके।

खाद्यान्नों का प्रति एकड़ उत्पादन

\+

*४०२. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्यान्नों का प्रति एकड़ उत्पादन काफी नहीं बढ़ा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा सचिव (श्री शिन्दे) : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख). उपज की प्रवृत्तियों के अध्ययन के लिये सम्पूर्ण उपज के आंकड़ों के स्थान पर उत्पादकता (उपज) के सूचकांकों को ध्यान में रखा जाना चाहिये क्योंकि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद प्राक्कलन तैयार करने की विधि में हुए परिवर्तनों के कारण उन आंकड़ों की अन्य वर्षों से तुलना नहीं की जा सकी क्योंकि किसी वर्ष की उपज मौसम सम्बन्धी बातों से काफी प्रभावित होती है, अतः

उपज में हुई प्रति एकड़ वृद्धि अथवा कमी का अध्ययन पिछले कम से कम तीन वर्षों का औसत निकाल कर किया जाता है। १९५१–५२ को समाप्त होने वाले तीन वर्षों तथा १९६१–६२ को समाप्त होने वाले तीन वर्ष के दौरान खाद्यान्नों की औसत उपज में लगभग २१ प्रतिशत वृद्धि हुई।

(ग) चुने गये ४० जिलों में चावल की तथा १०० जिलों में मोटे अनाज तथा दालों की सघन खेती के लिये व्यापक कार्यक्रम कार्यान्वित किये जा रहे हैं। २० जिलों में गेहूं के सघन खेती करने का भी इरादा है। ये कार्यक्रम चुने गये १५ जिलों में पहिले चालू किये गये पैकेज कार्यक्रमों के अतिरिक्त है।

श्री सुबोध हंसदा : भाग (क) तथा (ख) का उत्तर बिल्कुल भी सन्तोषजनक नहीं है। मैं तो प्रति एकड़ उपज जानना चाहता था। उत्तर में गत १० वर्षों की औसत उपज बताई गई है। गत १० वर्षों के दौरान प्रति एकड़ उपज में कितनी वृद्धि हुई है ? यदि प्रति एकड़ उपज में कुछ भी वृद्धि नहीं हुई है, तो उसके लिये कौन उत्तरदायी है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : प्रति एकड़ उपज में वृद्धि हुई है। हमने बताया है कि उपज का हिसाब अनेक वर्षों के आधार पर लगाया जाता है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण गत २ वर्षों में उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसका यह अर्थ नहीं है कि प्रति एकड़ उपज में कोई वृद्धि नहीं हुई है। यही कारण है कि हमने बताया है कि परिमाणों को लम्बे काल के आधार पर आंका जाता है। यदि गत १० वर्षों को देखा जाय, तो पता चलेगा कि औसत उपज में २१ प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

श्री सुबोध हंसदा : विवरण में यह बताया गया है कि देश में खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिये ४० जिलों में सघन खेती सम्बन्धी कुछ व्यापक कार्यक्रम चालू किये गये हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने उन जिलों में जो कि पिछड़े हुए हैं तथा जहां सिंचाई सम्बधी सुविधाओं का नितांत अभाव है। उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

श्री अ० म० थामस : यह भली भांति विदित है तथा सभा में भी यह बात अनेक बार बतायी गई है कि सघन खेती सम्बन्धी एक कार्यक्रम चालू है जिसे पैकेज जिला कार्यक्रम कहते हैं। चावल की सघन खेती के लिये भी ४० जिलों में, जहां चावल मुख्य अनाज के रूप में पैदा होता है, एक कार्यक्रम चालू है। ज्वार, बाजरा आदि के लिये एक शुष्क खेती कार्यक्रम तथा गेंहू की सघन खेती के लिये भी एक कार्यक्रम है। अतः यदि माननीय सदस्य किसी विशेष क्षेत्र के बारे में प्रश्न पूछें, तो मैं उठाये गये निश्चित कदम बता सकता हूं।

Shri M. L. Dwivedi : From the day the community development programme has commenced, we have started using various new kinds of manures. May I know to what extent the production has increased as a result of the use of these new manures and if the use of these manures has not led to any increase in production, what steps Government are taking in this regard ?

श्री अ० म० थामस : उर्वरकों के संभरण के अनेक कार्यक्रम हैं, फिर पौधों की रक्षा का कार्यक्रम है, सामान्य रूप से कृषि की सुधरी हुई प्रणालियों हैं, अच्छे बीजों का संभरण आदि है। अतः अनेक कार्यक्रम आरम्भ किये गये हैं और यह नहीं कहा जा सकता कि वृद्धि किसी एक कारण से हुई है। हां, अधिकतर वृद्धि उर्वरको के अधिक प्रयोग करने से हुई है।

श्री म० ला० द्विवेदी : मेरा प्रश्न निश्चित था, इन तरीकों से कितनी वृद्धि हुई है ।

अध्यक्ष महोदय : वह उन्होने बता दिया है ।

श्री म० ला० द्विवेदी : वह कहते हैं कि यह किसी एक कारण से नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : अनेक बातों से वृद्धि हुई है । अलग से एक मद की वृद्धि बताना संभव नहीं है । यही उत्तर है ।

श्री म० ला० द्विवेदी : परन्तु मेरा प्रश्न था कि उर्वरकों से कोई लाभ हुआ है ।

श्री अ० म० थामस : मैंने बताया है कि अधिकतर वृद्धि उर्वरकों के इस्तेमाल से हुई है ।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : गैर सरकारी यंत्रीकृत फार्मों की तुलना में ऐसे सरकारी फार्मों में औसत उपज कितनी है ?

श्री अ० म० थामस : इसके लिये अलग प्रश्न होना चाहिये ।

डा० सरोजिनी महिषी : कम से कम उन स्थानों पर जहां परियोजनायें पूरी हो चुकी हैं बड़ी सिंचाई परियोजनाओं की पूर्ति तथा उनके वास्तविक उपयोग में होने वाली देरी को कम करने के लिये सरकार ने किसानों को अच्छी सुविधायें देने के लिये कौन से विशिष्ट उपाय किये हैं ?

श्री अ० म० थामस : इस बारे में अनेक अवसरों पर चर्चा हो चुकी है । तथ्य यह है कि इतनी बड़ी लागत पर एकत्रित किये गये पानी के उपयोग में दूरी होने का सभी वाद-विवादों में उल्लेख किया गया है । अब नालियां खोदी जा रही हैं और राज्य सरकारों से बातचीत हो रही है तथा अब उपयुक्त उपाय किये जा रहे हैं । सच तो यह है कि सिंचाई और विद्युत मंत्रालय इसकी जांच कर रहा है । और खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभापतित्व में केन्द्रीय कृषि खाद्य उत्पादन बोर्ड भी इसे देख रहा है ।

श्री शशि रंजन : प्रति एकड़ उपज का निर्धारण करते समय क्या सरकार उत्पादन लागत सुनिश्चत कर सकती है तथा किसानों को आश्वासन दे सकती है कि उनका लगाया हुआ धन रक्षित और लाभदायक होगा ?

श्री अ० म० थामस : यह बहुत बड़ा प्रश्न है । उत्पादन लागत का निर्धारण करने के लिए नमूना सर्वेक्षण किये गये हैं । इसके अलावा कोई और प्रकृष्ट प्रयास नहीं हुआ है ।

श्री हिम्मत सिंहजी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या किसानों को अजैव खाद के प्रयोग की सलाह देने से पहले भारत के अधिकतम भागों में उचित भूविश्लेषण किया जाता है ।

श्री अ० म० थामस : यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है । इसका हम विशेष ध्यान रखते हैं कि किसी विशेष खेत के लिये कोई विशेष उर्वरक निर्धारित करने से पहले उचित भू विश्लेषण होना चाहिये । इस प्रयोजन के लिये हमने सभी खंड केन्द्रों में भू परीक्षण केन्द्र खोले हैं । भू परीक्षण प्रयोगशालायें भी हैं ।

श्री जसवन्त मेहता : विवरण में कहा गया है कि पिछले दस वर्षों में २१ प्रतिशत वृद्धि हुई है । खाद्यान्न की कमी को देखते हुये क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने विभिन्न राज्य तथा विभि क्षेत्रों में अलग अलग वस्तुओं को चुनने के लिये क्या कसौटी तय की है ?

श्री अ० म० थामस : उत्पादन में वृद्धि कृषि के क्षेत्र को बढ़ा कर या सघन खेती से हो सकती है। औसत उपज में वृद्धि उर्वरकों के प्रकृष्ट प्रयोग, पौधों की रक्षा के उपायों तथा अन्य कारणों से हुई है। मैं पहले ही बता चुका हुं कि प्रति एकड़ उपज में पिछले दस वर्षों में २१ प्रतिशत की वृद्धि हुई है।]

श्री जसवन्त मेहता : मेरा प्रश्न कसौटी के बारे में था।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय के लिये इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है क्योंकि इसमें बड़े व्यापक विषय आ जाते हैं, इसलिये उत्तर नहीं दिया गया है ?

श्री त्यागी: सारे देश में खाद्यान्नों की औसत उत्पादिता को बढ़ाने की दृष्टि से क्या सरकार ने खेत-वार कृषि क्षमताओं तथा सिचाई सुविधाओ, कृषि औजारों, वित्त, बीज, उर्वरकों आदि के सम्बन्ध में कृषकों की आवश्यकताओं का कोई सर्वेक्षण करने का ध्यान रखा है ?

श्री अ० म० थामस : यही विचार है। पैकेज जिला कार्यक्रमों में तथा सघन खेती कार्यक्रम में भी चावल के लिये १४ जिलों में और गेंहू के लिए २० जिलों में इसे किया जा रहा है।

किसानों को ऋण

***४०३. श्री अ० क० गोपालन :** क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों में किसानों को ऋण देने की व्यवस्था करने में संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि ऋण के लिए कितनी रकम निश्चित की गई थी तथा अब तक कितनी राशि का उपयोग किया गया है ; और

(घ) कृषि ऋण के लिये आवंटित धनराशि को तुरन्त तथा शीघ्र उपयोग में लाने का निश्चय करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

राज्य सरकारों ने योजना के अन्तिम वर्ष के दौरान अल्प तथा मध्यम कालीन ऋण देने के लिये ५१२ करोड़ रुपये का जो लक्ष्य सामने रखा था उसमें से सहकारी समितियों ने १९६१–६२ में २२८ करोड़ रुपये दिये। १९६२–६३ के लिये अस्थायी आंकड़े २५६ करोड़ रुपये हैं और १९६३–६४ के लिये ३१८ करोड़ रुपये। प्रगति आशा के अनुसार नहीं है। कारण ये हैं : (क) ऋण ढांचे की कमजोरी, विशेषत: प्रारंभिक स्तर पर, (ख) संगठनात्मक त्रुटियां, (ग) ऋण की राशि को समय से अधिक रखे रखने की मनोवृति का बढ़ाना, (घ) ऋण देने की दोषपूर्ण नीतियां, इत्यादि। इन त्रुटियों को दूर रखने के लिये एक विस्तृत कार्यवाही कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है और शीघ्र ही राज्य सरकारों को भेज दिया जाएगा।

दीर्घकालीन ऋण के बारे में योजना के अन्तिम वर्ष के लिये १५० करोड़ रुपये (अप्राप्त) का लक्ष्य रखा गया था जबकि १९६१–६२ में लगभग ४६ करोड़ रुपये दिये गये और १९६२–६३ और १९६३–६४ के लिये प्राक्कलन क्रमशः ६३ करोड़ रुपये तथा ८३ करोड़ रु० हैं। यदि भूमि बन्धक बैंकों के ऋणपत्रों को सरकार तथा सस्थाओं की ओर से पर्याप्त समर्थन उपलब्ध हो तो इस लक्ष्य को लगभग पूरा करना संभव हो सकता है।

सहकारी समितियों द्वारा दिये गये ऋण के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को २४.३ करोड़ तथा २९.०१ करोड़ रुपये की राशियां दी हैं ताकि वे किसानों को उर्वरकों तथा बीजों के लिये नकदी जिन्स में अल्पकालिक ऋण दे सकें। १९६३–६४ में इसके ३० करोड़ रुपये हो जाने की संभावना है।

श्री अ० क० गोपालन : विवरण में कहा गया है कि आशा के अनुसार प्रगति नही हुई है। इसके कारण भी दिए गए हैं। जहां तक पहले कारण का सम्बध है, अर्थात ऋण के ढांचे का कमजोर होना, विशेषत: प्रारम्भिक स्तर पर, इस कमजोरी को दूर करने के लिए सरकार क्या कदम उठाना चाहती है ?

श्री श्यामधर मिश्र : प्रारम्भिक स्तर पर ऋण समितियां कमजोर हैं क्योंकि उन में से कुछ आत्मनिर्भर नहीं हैं। उनके संसाधन क्षीण हैं ; उनकी जमा राशि की स्थिति तथा देखरेख भी कमजोर है। सरकार कदम उठा रही है। खाद्य तथा कृषि मंत्री की अध्यक्षता में प्रादेशिक सम्मेलन हुए थे। योजना आयोग से हमने बातचीत की है तथा इन त्रुटियों को दूर करने के लिये हम राज्य सरकारो से भी बातचीत कर रहे हैं।

श्री अ० क० गोपालन : क्या यह सच है कि जिस काश्तकार को किसी ऋण की आवश्यकता होती है उसे ऋण पाने में कठिनाई होती है और यदि हां, तो नकदी। जिन्स में ऋण देने के अतिरिक्त जिसका विवरण में उल्लेख किया गया है, सरकार इसका उपचार करने के लिये क्या उपाय करना चाहती है ?

श्री श्यामधर मिश्र : हमें जो कठिनाइयां हैं यह उनमें से एक है। राज्य सरकारों के साथ हमने बातचीत की। दो वर्ष पहले निर्णय हुआ था कि न केवल ऋण-योग्य व्यक्ति को ही बल्कि ऋण-योग्य प्रयोजन के लिये भी ऋण दिया जायेगा ताकि खेती करने वाले काश्तकार ऋण ले सकें। दुर्भाग्यवश कुछ राज्यों में इसे कार्यान्वित नहीं किया गया है। और हम इस विषय का अनुसरण कर रहे हैं।

श्री वासुदेवन नायर : विवरण में कहा गया है कि २५६ क ोड़ रुपये आवंटित किये गये थे तथा प्रगति आशा के अनुसार नहीं है। इन २५६ करोड़ रुपयों में से वास्तव में कितना खर्च किया गया है ?

श्री श्यामधर मिश्र : वास्तव में समितियों द्वारा यह कृषकों को दिया गया था। मेरे विचार में लक्ष्य २८० करोड़ रु० था।

Shri Yashpal Singh : Is it a fact that the issue of this credit is delayed by the Govt. for more than a year even but when it comes to the realisation of the credit, Govt. wants to realise it overnight and thousands of cultivators have to go to jail ?

Shri S. D. Misra : Govt. does not give the loan ; it is given by the society. The loan is generally given in two months and is realised at the time of harvest. Realisation is essential in the post-harvest period.

Shri Yaspal Singh : What action has been taken to see that farmers are not arrested ?

Shri Sarjoo Pandey: Has the attention of the Govt. been drawn to the fact that farmers who take loan from the co-operative societies are compelled to take mannure money for which is deducted from the loan ?

Shri S. D. Misra: There was a complaint from somewhere that mannure was given under compulsion. It was known after enquiry that it was not so. In fact, it has been deemed good to give mannure. So, fertilisers can be purchased and given, to a certain percentage, to those farmers who want them.

Shri Rameshwaranand : I want to make one submission.....

Shri Sheo Narain : Which are the States where these Co-operative societies are running in deficit, or experiencing a shortfall ?

Mr. Speaker : Swamiji, please wait a little.

Shri S. D. Misra : The hon. Member is presumably referring to the shortfall. If that be so, shortfall is expected in Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Gujarat, Jammu and Kashmir, Maharashtra, Mysore, Orissa, West Bengal etc. and targets are expected to be achieved in five States—Kerala, Madhya Pradesh, Madras, Punjab and U. P.

Shri Rameshwaranand : The hon. Minister has stated hat a complaint was received from some place that mannure is forcibly given but on enquiry it was known that this was not correct. I want to know through whom this enquiry is instituted, whether you handle it yourself or it is handled over to those against whom the complaint has been received. I am sure it is not proper to hold the enquiry like this.

Mr. Speaker : If you are sure, it is all right.

अल्पसूचना प्रश्न और उत्तर

SHORT NOTICE QUESTION AND ANSWERS

नई दिल्ली में टेलीफोन लाइनें लगाना

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४. श्री दाजी :
श्री वारियर :

क्या डाक और तार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नई दिल्ली में टेलीफोन लाइनें लगाने का ठेका बेल टेलीफोन मैन्युफेक्चरिंग कम्पनी को देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि उक्त कम्पनी अमेरिकन इण्टरनेशनल टेलीग्राफ्स एण्ड टेलीफोन्स की एक सहायक कम्पनी है;

(ग) क्या सरकार को यह भी मालूम है कि अमेरिकन इण्टरनेशनल टेलीग्राफ्स एण्ड टेलीफोन्स कम्पनी ने ही ट्यूनीशिया में तार बिछाये थे, जो त्रुटिपूर्ण पाये गये थे और जिन्हें फिर से बिछाना पड़ा था;

(घ) क्या गृह-कार्य मंत्रालय के गुप्तचर विभाग से इस विषय में परामर्श कर लिया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट क्या है ?

विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : (क) जी हां। विस्तृत शर्तों पर सन्तोषजनक समझौता होने पर बेल टेलीफोन मैन्युफेक्चरिंग कम्पनी के साथ क्रासबार किस्म के टेलीफोन स्विचिंग उपकरणों की खरीद तथा इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर में उसके निर्माण के लिये भी ठेका करने का निर्णय किया गया है। इसमें से कुछ उपकरण दिल्ली में लगाया जायेगा।

(ख) जी हां। एन्टवर्प, बेल्जियम, की बेल टेलीफोन मैन्युफेक्चरिंग कम्पनी अमेरिकन इण्टरनेशनल टेलीफोन एण्ड टेलीग्राफ कारपोरेशन की सहायक कम्पनी है।

(ग) ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

(घ) और (ङ). गृह-कार्य मंत्रालय के केन्द्रीय गुप्तचर विभाग के साथ यदि कोई परामर्श हुआ है तो उसे प्रकट करना लोकहित में नहीं है।

श्री दाजी : क्या सरकार को ज्ञात है, जैसा कि प्रश्न के भाग (ग) से पता चलता है, कि ट्यूनीशिया में बिछाये गये तार वहां फ्रांसीसी दूतावास से जुड़े हुए थे और उस तार का बहुत बड़ा भाग फिर से बिछाना पड़ा था तथा ट्यूनीशिया में इस कम्पनी के विरुद्ध और ट्यूनीशिया सरकार के उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की गई थी ?

श्री अ० कु० सेन : सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

श्री दाजी : क्या यह सच है कि जापानी तथा स्वीडन की फर्मों की तुलना में इस कम्पनी द्वारा तार के बिछाने तथा निर्माण दोनों की बताई गई लागत सब से ज्यादा थी और यदि हां, तो इसी विशेष कम्पनी के भाव को क्यों स्वीकार किया गया जब कि वह सब से अधिक था ?

श्री अ० कु० सेन : जी नहीं। जहां तक उपकरण के संभरण का सम्बन्ध था, उसका भाव दूसरे स्थान पर था। जहां तक पूंजी उपकरण के संभरण का सम्बन्ध था, इसका भाव सबसे कम था।

श्री वारियर : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने इस कम्पनी के बारे में पूछताछ की थी और क्या इसे इस क्षेत्र में सबसे कम अनुभवी पाया गया था ?

श्री अ० कु० सेन : सरकार ने सभी तरह की पूछताछ की थी। तथ्य यह है कि एक सहायक कम्पनी के साथ, जो ब्रिटिश कम्पनी है, रूपनारायणपुर में हिन्दुस्तान केबल्स लि० द्वारा तारों के लगाये जाने और निर्माण के लिये हम साथ मिल कर काम कर रहे हैं।

श्री ही० ना० मुकर्जी : मंत्री महोदय के कथनानुसार सरकार को क्योंकि श्री दाजी द्वारा उल्लिखित संदिग्ध परिस्थितियों का ज्ञान नहीं है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार सारी स्थिति की पड़ताल करने से पहले इस ठेके को अन्तिम रूप देने में और आगे कदम नहीं उठायेगी ?

श्री अ० कु० सेन : इस कम्पनी द्वारा तारें बिछाने के बारे में सरकार को जो शिकायतें भेजी गई थीं, जिन में से कुछ गुमनाम थीं, हमने उनकी जांच की है। जैसा कि मैंने कहा है, जहां तक तारें बिछाने का सम्बन्ध है, यह ठेके का भाग नहीं है। सच तो यह है कि हिन्दुस्तान

केबल्स फैक्टरी, रूपनारायणपुर, में, जो कई वर्ष पहले खोली गई थी, तारों के निर्माण का काम इस कम्पनी की ब्रिटिश सहायक कम्पनी के सहयोग से किया गया था तथा उनके आचरण के बारे में शिकायत का हमें कोई कारण नहीं मिला ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि श्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक टिप्पण लिखा था कि जब तक इस पर गृह-कार्य मंत्रालय तथा गुप्तचर विभाग द्वारा विचार न किया जाये कोई अन्तिम कार्यवाही नहीं करनी चाहिये और क्या यह सच है कि यह निर्णय डाक और तार विभाग ने किया था जबकि शास्त्री जी २६ फरवरी, १९६४ को जम्मू में थे ?

श्री अ० कु० सेन : मंत्रिमंडल ने इस सम्बन्ध में सारे टिप्पणों को देखा था और यह कहने का कोई लाभ नहीं कि शास्त्री जी की सिफ़ारिशों पर विचार नहीं किया गया । परन्तु उन्होंने ऐसी कोई सिफ़ारिश नहीं की थी जिसका कि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है ।

श्री हरिविष्णु कामत : मंत्री महोदय ने यह कह कर शायद बात को टाल दिया है कि एक मद का भाव तो सबसे ज्यादा था और दूसरी का सब से कम । क्या मैं एक सीधा प्रश्न पूछ सकता हूं कि यदि जापानी टेंडर स्वीकार कर लिया जाता तो ६ करोड़ रु० की बचत होती और यदि स्वीडन का टेंडर मान लिया जाता तो कुल उत्पादन लागत तथा उपकरण के आयात के लिये विदेशी मुद्रा की आवश्यकता में ८ करोड़ रु० की बचत होती ?

श्री अ० कु० सेन : जी नहीं ।

श्री हरि विष्णु कामत : आंकड़े क्या हैं ?

श्री अ० कु० सेन : पूंजी उपकरण तथा उपकरण की खरीद लगभग ४।। करोड़ रु० के होते हैं । जहां तक उपकरण के संभरण का सम्बन्ध है, एन० ई० सी० का टेंडर ३०२ लाख रुपये का था, बी० टी० एम० का ३४८ लाख रु० और एल० एम० ई० का ३९६ लाख रुपये । जहां तक पूंजी उपकरण और जानकारी का सम्बन्ध है, एन० ई० सी० का टेंडर १३५ लाख रु० का था, बी० टी० एम० का ११५ लाख रु० और एल० एम० ई० का १६२ लाख रुपये । प्रत्येक चीज को मिला कर यदि कुल लागत को लिया जाये तो आंकड़े इस प्रकार हैं : एन० ई० सी० ४४६ लाख रु०, बी० टी० एम० ४६४ लाख रु० और एल० एम० ई० ५७९ लाख रु० ।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वे इन आंकड़ों को सभा-पटल पर रख दें ताकि हम आराम से उन्हें देख सकें । यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है ।

अध्यक्ष महोदय : इसे अब रिकार्ड कर लिया गया है और वाद-विवाद में आ जायेगा ।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : क्या सरकार ने ट्यूनीशिया में इस कम्पनी द्वारा तार बिछाने के सम्बन्ध में आरोप की सत्यता सुनिश्चित कर ली है ?

श्री अ० कु० सेन : पहली बात तो यह है कि आरोपों में तारों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है । आरोप ये थे कि ट्यूनीशिया में टेलीफोन एक्सचेंजों के संचालन में लगे कुछ फ्रांसीसी तकनीशनों पर जासूसी करने का सन्देह था । **(अन्तर्बाधा)**

इन आरोपों की छानबीन करवाई गई थी और यह पुष्ट नहीं हो सका कि इस आरोप में कोई सार है कि तारें बिछाने के सम्बन्ध में इस कम्पनी का किन्हीं सन्देहात्मक कार्यों से सम्बन्ध था । कुछ भी हो, यहां पर वह कम्पनी तारें नहीं बिछा रही है ।

श्री दाजी : श्रीमान्, एक औचित्य प्रश्न है । पहले उत्तर यह था : "जी नहीं; सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है" । जब मैंने अनुपूरक प्रश्न पूछा तो उन्होंने कहा कि उनके ध्यान में यह बात नहीं आई है । अब कहा गया है कि सरकार इसे जानती है और उसे पता है कि कुछ गड़बड़ हुई थी । गड़बड़ इस कम्पनी द्वारा नियुक्त फ्रांसीसी तकनीशनों ने की थी या नहीं यह एक अलग विषय है । परन्तु यहां दो मंत्रियों ने नहीं बल्कि एक ही मंत्री ने देश की सुरक्षा से सम्बन्ध रखने वाले एक प्रश्न के दो अलग अलग उत्तर दिये हैं ।

श्री अ० कु० सेन : यदि माननीय सदस्य मेरे उत्तरों को देखने का कष्ट करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि मैंने कोई आपत्तिजनक बात नहीं कही है । माननीय सदस्य ने कहा था, "क्या सरकार जानती है कि क्या तारें बिछाने में उन पर किन्हीं कार्यवाहियों का सन्देह था ?" मैं ने कहा था कि ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है । पिछला उत्तर मैंने यह दिया था कि सरकार के पास ये आरोप पहुंचे हैं कि वहां एक्सचेंजों का संचालन करने में जो फ्रांसीसी तकनीशन लगे हुए हैं उनमें से कुछ पर जासूसी करने का सन्देह था । तारें बिछाने का प्रश्न कहां है ?

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या मैं जान सकता हूं कि कौन से तकनीकी विशेषज्ञ सरकार को निर्णय करते समय सलाह देते हैं तथा क्या सरकार का निर्णय इसे दिये गये तकनीकी परामर्श के अनुरूप है ?

श्री अ० कु० सेन : सरकार के सभी तकनीकी विशेषज्ञों ने, जिन में दूरसंचार अनुसन्धान के प्रधान श्री वासुदेवन भी सम्मिलित हैं, सभी टेंडरों की जांच की थी ।

श्री स० मो० बनर्जी : वही व्यक्ति है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या मैं जान सकती हूं कि गुमनाम स्रोतों से सरकार के ध्यान में आरोपों के आने के बाद जो जानकारी एकत्रित की गई थी क्या वह सीधे ट्यूनीशिया सरकार से प्राप्त की गई थी और उस सरकार का, जो भारत सरकार की मित्र है, क्या उत्तर था ?

श्री अ० कु० सेन : हम ने किस तरह उन आरोपों का सत्यापन किया यह प्रकट करना सरकार के हित में नहीं है ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : श्रीमान्, मेरा एक औचित्य प्रश्न है । मंत्री महोदय यह नहीं कह सकते कि "यह सरकार के हित में नहीं है", उन्हें कहना चाहिये कि "यह लोक हित में नहीं है।"

कुछ माननीय सदस्य उठे—

अध्यक्ष महोदय : श्री यू० एम० त्रिवेदी ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : क्या मैं जान सकता हूं कि स्वीडन की कम्पनी ने जो टेंडर दिया था, और वास्तव में उस कम्पनी को इन चीजों का सब से ज्यादा ज्ञान है और अनुभव है, उससे दस वर्षों की अवधि में हमें लगभग ८ करोड़ रुपये की कुल शुद्ध बचत होती ?

श्री अ० कु० सेन : उपकरण के संभरण के लिये कुल ठेका ही केवल ४ करोड़ रुपये का है ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : जो उत्तर . . .

अध्यक्ष महोदय : जब कुल ठेका ४ करोड़ रुपये का है तो ८ करोड़ रु० की बचत कैसे हो सकती है ?

श्री उ० मू० त्रिवेदी : आवर्ती व्यय किया जाना है और इसीलिए मैं ने कहा था कि दस वर्षों में कुल ८ करोड़ रुपये की बचत होती ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम आगे चलें ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

पोर्ट ब्लेयर में संचार प्रणाली

*३९९. **श्री भागवत झा आजाद :** क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पोर्ट ब्लेयर को शेष देश के साथ मिलने के लिये संचार व्यवस्था को सुधारने की दिशा में हाल ही में क्या मुख्य कदम उठाये गये हैं ?

डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : जहां तक दूर संचार सुविधायों का संबंध है कलकत्ता और पोर्ट ब्लेयर के बीच वायरलेस सुविधायें पहले से ही विद्यमान थी । कलकत्ता और पोर्ट ब्लेयर के बीच रेडियो टेलीफोन सेवा नवम्बर, १९६२ से शुरू की गई हैं । कलकत्ता और पोर्ट ब्लयर के बीच रडियों टलीप्रिंटर सरकिट के लिये कदम उठाये गये हैं । पोर्ट ब्लेयर तथा शेष भारत के बीच सभी उपलब्ध समुद्री तथा हवाई सेवायें डाक लाने लेजाने के लिये इस्तेमाल लाई जा रही हैं ।

माल-डिब्बे का विस्फोट

*४०४. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री प्र० कु० घोष :
श्री यशपाल सिंह :
श्री कपूर सिंह :
श्री कछवाय :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री ओंकार लाल बेरव :
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ७ जनवरी, १९६४ को विस्फोटक पदार्थों से भरे हुए एक माल डिब्बे का देहरादून रेलवे स्टेशन पर विस्फोट हो गया जिसके फलस्वरूप कई व्यक्ति हताहत हुए ;

(ख) क्या इस की जांच की गई है कि दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी उपपत्तियां क्या हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) जी हां। विभागीय रूप से नियुक्ति चार आकस्मिक मजदूर बहुत जल गये तथा एक आकस्मिक मजदूर को गंभीर 'शाक' लगा। इनमें से तीन बाद में अस्पताल में मर गये।

(ख) और (ग). प्रशासनिक वर्ग के रेलवे अधिकारियों तथा विस्फोटक पदार्थ निरीक्षक की एक जांच समिति ने दुर्घटना की जांच की। समिति ने अपना प्रतिवेदन उत्तर रेलवे को पेश कर दिया था। समिति की उपपत्तियां यह हैं कि विस्फोट दो बक्सों में बन्द बारूद के फट जाने से हुआ परन्तु विस्फोट के वास्तविक कारण का पता नहीं लग सकता।

भुज में भूकम्प वेधशाला

*४०५. **श्री भी० प्र० यादव :**
श्री घवन :
श्री विशनचंद्र सेठ :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार एक भूकम्प वेधशाला भुज में तथा १४ अन्य दूसरे स्थानों पर स्थापित करने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो ये वेधशालायें कब तक तथा कहां कहां स्थापित की जायेंगी ; और

(ग) प्रत्येक वेधशाला पर कुल कितना धन व्यय होने का अनुमान है ?

परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन): (क) और (ख). भुज, मैसालोटन, मारवाड़, अजमेर, डिब्रूगढ़, इम्फाल, श्रीनगर तथा इलाहाबाद में तीसरी योजना में आठ नई वेधशालाएं स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ग) इन वेधशालाओं की स्थापना का व्यय भूमि की लागत, उपकरण आदि के आधार पर अलग अलग होगा। औसतन प्रत्येक वेधशाला पर भवन तथा उपकरण का व्यय लगभग १.५ लाख रुपये तथा १५ हजार रुपये वार्षिक कर्मचारी व्यय होगा।

रेलवे वर्कशाप

*४०६. **श्री नम्बियार**: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आपात काल में बिना कोई अतिरिक्त भुगतान किए सभी रेलवे वर्कशापों के काम के घंट बढ़ा दिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो बढ़े हुए काम के घंटे के लिये मजूरी बढ़ाने की कर्मचारियों की मांग को पूरा करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) आपात काल होने पर जब रेलवे वर्कशापों के उत्पादन की जांच की गई थी तब पता लगा कि कुछ रेलवे वर्कशापों में यांत्रिक विभाग (वर्कशाप) के लिये भारतीय रेलवे संहिता में रखे गये ४८ काम के घंटों से कम समय काम किया जाता है। उत्पादन बढ़ाने के लिये तथा समानता लाने के लिये रेलवे ने रिकनाइज्ड यूनियन के परामर्श से इन वर्कशापों में ४८ काम के घंटे कर दिये गये।

(ख) कारखाना अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार रेलवे वर्कशापों में वह कर्मचारी जो ४८ घंटे प्रति घंटों से अधिक काम करते हैं, उनको मजूरी की साधारण दरों से दुगना धन दिया जाता है ।

पर्यटन केन्द्रों के लिए विमान सेवायें

*४०७. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार प्रमुख पर्यटन केन्द्रों के लिये विमान सेवा चालू करने की योजना की जांच कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो कितने पर्यटन केन्द्रों को वायुमार्गों द्वारा मिलाया जायेगा ; और

(ग) योजना कब आरम्भ होगी ?

परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). निम्नलिखित पर्यटन केन्द्रों को विमान अभी भी जाते हैं :—

औरंगाबाद, भुवनेश्वर, आगरा, बनारस, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कुलु, श्रीनगर, पन्ना, तिरुचिरापल्ली, मदुरै तथा त्रिवेंद्रम ।

विमान सेवाओं को जल्दी जल्दी चलाने के लिये तथा पर्यटन रुचि को और स्थानों को विमान द्वारा मिलने का प्रश्न विचाराधीन है ।

नौवहन सेवा

*४०८. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६४–६५ में उनके मंत्रालय का "चार्टर विंग" सरकारी खाते में कितने माल की ढुलाई की व्यवस्था करेगा ;

(ख) इस माल में से कितना भारतीय जहाजों द्वारा ढोया जाने की आशा है ;

(ग) पिछले वर्ष के इस सम्बन्ध में क्या आंकड़े हैं ; और

(घ) चालू वर्ष में सरकारी माल के लिये विदेशी शिपिंग कान्फ्रेंस लाइन्स से बातचीत के द्वारा भाड़े में छूट के रूप में कितनी रियायत प्राप्त की गई है ?

परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) और (ख). १९६४–६५ में 'चार्टर विंग' द्वारा ढोने वाली माल की मात्रा बताना संभव नहीं है क्योंकि यह वर्ष में भारत सरकार तथा विदेशी खरीदार और बेचने वालों के बीच क्रय और विक्रय के ठेकों को अंतिम रूप देने पर निर्भर करता है ।

(ग) अप्रैल, १९६३ से फरवरी, १९६४ (जब तक के आंकड़े उपलब्ध हैं) तक ढोये गये विदेशी माल की मात्रा ५,६१,१०० टन है जिसमें से भारतीय जहाजों ने १,८७,८०० टन तथा विदेशी जहाजों ने ३,७३,३०० टन माल ढोया था ।

(घ) १९६३–६४ में अमरीका से सरकारी खाते में ढोये गये माल पर ३० प्रतिशत तक अमरीका-भारत-पाकिस्तान-बर्मा-लंका सम्मेलन में एक व्यापार के बारे में बातचीत हुई थी ।

गेहूं का उत्पादन

*४०१. **श्री प० कुन्हन :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में देश में गेहूं का उत्पादन बढ़ाने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ख) क्या इन कदमों के परिणामस्वरूप तीसरी योजना के पहले तीन वर्षों में गेहूं का उत्पादन कुछ बढ़ा है ; और

(ग) यदि हां, तो कितना ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) तीसरी योजना के अधीन खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिये ये कदम उठाये गये हैं । जैसे सिंचाई सुविधाओं का बढ़ाना, उर्वरक तथा खाद की खपत बढ़ाना, अच्छे किस्म के बीज का अधिक उपयोग तथा गहूं का उत्पादन बढ़ाने के लिये पौदा संरक्षण । इसके अतिरिक्त १९६४–६५ से पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा बिहार राज्यों में २० चुने गए जिलों में गेहूं की सफल खेती की योजना लागू करने का विचार है ।

(ख) और (ग) गत तीन वर्षों में देश में गेहूं का उत्पादन नीचे लिखे अनुसार था :—

	हजार टन
१९६०–६१	१०,८१८
१९६१–६२	११,८४९
१९६२–६३	१०,९५६

१९६३–६४ में उत्पादन के प्राक्कलन उपलब्ध नहीं हैं । १९६२–६३ में गेहूं का उत्पादन बोने के समय अपर्याप्त कमी तथा उत्तर प्रदेश और राजस्थान में जनवरी, १९६३ में शीत ऋतु में वर्षा न होने के कारण कम हुआ था ।

सहकारी आन्दोलन

*४१०. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी आन्दोलन के गैर-सरकारी कर्मचारियों की सदस्य शिक्षा तथा नेतृत्व प्रशिक्षण की पुनरीक्षित योजना अन्तिम रूप से स्वीकार कर ली गई है ;

(ख) पुनरीक्षित कार्यक्रम किन श्रेणियों के व्यक्तियों पर लागू होगा ;

(ग) क्या पुनरीक्षित कार्यक्रम को बनाने में खण्ड कर्मचारियों की सहायता तथा सहयोग सुनिश्चित कर लिया गया है ; और

2492 (Ai) LSD—3.

(घ) पहले कार्यक्रम की क्रियान्विति में अनुभव की गई कमियों को दूर करने के लिये इस कार्यक्रम में किस सीमा तक परिवर्तन किया गया है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) (१) सहकारी समितियों के कार्यालय कर्मचारी तथा प्रबन्ध समिति के सदस्य ।

(२) सहकारी समितियों के मानदेय/अंश कालिक सचिव तथा प्रबन्धक ।

(ग) जी हां ।

(घ) ग्रामीण स्तर के कर्मचारियों समेत खण्ड विस्तार कर्मचारियों के सहयोग से प्रशिक्षण खुलासा तथा प्रभावोत्पादक होगा ।

कलकत्ता कोयला गोदी

*४११. **श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खानों से कोयले का नियमित संभरण करकेतथा उसके बाद जहाजों में समय पर लदान करके कलकत्ता कोयला गोदी की स्थापित क्षमता का पूरा उपयोग किया जा रहा है ;

(ख) इस बन्दरगाह में "मकेनिकल बर्थ" कितनी है तथा क्या सभी में "ट्रिपलर" लगे हुए हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इन बर्थों को कब यंत्रीकृत कर दिया जायेगा ?

परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) कलक बन्दरगाह से कोयले को जहाजों में लादने के लिये तीन नियमित बर्थ हैं । इसके अतिरिक्त मांग होने पर कोयले को जहाजों में लादने के लिये दो और बर्थ एक डाक नं० २ फिदरपुर तक तथा दूसरी किंगजार्ज डाक में उपलब्ध कर दी जाती है । वेगनों के आने के बारे में कोई शिकायत नहीं है । कोयला डाक की वर्तमान क्षमता प्रतिमास २ लाख टन का लदान कर सकती है परन्तु इसका पूर्ण उपयोग नहीं किया जा रहा है क्योंकि खान मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार तट पर कोयले का लाना लेजाना लदान से २० लाख टन कम हो गया है । जनवरी १९६४ में ९०५२८ टन कोयला जहाजों में लादा गया जब कि अगस्त, १९६३ में २,०१,५८० टन लादा गया था । १९६३ में लदान २० लाख टन के थे परन्तु इस वर्ष हमें बताया गया है कि इसमें कमी आ जायेगी और इस सम्बन्ध में मंत्रालय से बातचीत की जा रही है ।

(ख) और (ग) कोयला डाक की एक बर्थ में ४ लाख रुपये की लागत पर यांत्रिक कोयला ढोने का संयंत्र लगाया जा रहा है और ट्रिपलर की भी व्यवस्था की जा रही है जिसका डिजाइन ऐसा है कि वह कोयले से भरे चार पहियों वाले खुले वेग को उठाकर लौट दे । रेलवे के खुले वेगनों में कोयला इतना नहीं आपाता है जो इस संयंत्र की क्षमता को पूरा पूरा उपयोग में ला सके इस लिये इसका पूरा पूरा प्रयोग नहीं किया जा रहा है ।

कलकत्ता बन्दरगाह पर कोयले को अन्य बर्थों में यंत्र लगाने का प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि जिस बर्थ में यंत्र लगा हुआ है उसका ही पूरा उपयोग नहीं किया जा पा रहा है । इसके अतिरिक्त विचार है कि कोयले तथा लौहअयस्क के समान माल को हल्दिया बन्दरगाह में भेज दिया जाये ।

डाक तथा तार कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त समय कार्य योजना

*४१२. **श्री बी० चं० शर्मा :** क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में ही डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये नई अतिरिक्त समय कार्य योजना बनाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २४३७/६४]**

तटीय नौवहन सभा

*४१४ **श्री महेश्वर नायक :**
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
डा० उ० मिश्र :
डा० रानेन सेन :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के तट पर जहाजों के आने जाने में बहुत रुकावट आई है क्योंकि उनका 'अपर्याप्त चार्टिंग' होता है तथा तट की लम्बी पट्टी का जल विज्ञान सम्बन्धी सर्वेक्षण नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उपचारात्मक उपाय करने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) अपर्याप्त चार्टिंग के कारण में भारतीय समुद्र में जहाजों के आने जाने में कोई रुकावट नहीं आई है । इनके कई चार्ट ब्रिटिश एडमिरेलेट में बनाने को तथा इनमें किये गये परिवर्तनों को मरीनर्स को बता दिया जाता है जिससे वह इनको नवीनतम रखें । नेवल हाइड्रोग्राफिक आफिस, देहरादून ने भी कुछ चार्ट प्रकाशित किये हैं जिन में बन्दरगाहों आदि को जाने वाले रास्ते बनाए गये हैं । इन चार्टों की मदद से जहाज हमारे बन्दरगाहों में आ सकते हैं तथा यहां से जा सकते हैं ।

परन्तु देश के पूरे तट का जल विज्ञान सर्वेक्षण करने के संबंध में सरकार विचार कर रही है । इसके अधीन उन तटों का सर्वेक्षण किया जायगा जिनका अभी नहीं हुआ है तथा जिन तटों का सर्वेक्षण पहले भी हो चुका था परन्तु पुनः करना आवश्यक समझा गया है ।

Money Orders for National Defence Fund.

*415. **Shri Bhagwat Jha Azad :**
Shri D. C. Sharma :
Shri Subodh Hansda :
Shri S. C. Samanta :
Shri N. R. Laskar :
Shri Maheswar Naik :
Shri Bibhuti Mishra :
Shri D. D. Mantri :

Will the Minister of **Posts and Telegraphs** be pleased to state :

(a) whether certain persons have been apprehended who indulged in the act of misappropriating money orders sent to the National Defence Fund from the various parts of the country ; and

(b) if so, the amount thus misappropriated so far ?

The Deputy Minister in the Department of Posts and Telegraphs (Shri Bhagavat) : (a) Two persons were arrested including a Postal official of New Delhi G.P.O. for erasing the original entries of three money orders, increasing the amount to Rs. 600/- and making these payable to an accomplice. Only one money order was paid before the forgery was detected. It cannot be said whether the money orders tampered with were N.D.F. money orders.

(b) Rs. 600/- only.

एयर इंडिया के लिये अमरीकी 'सुपरसोनिक' विमान

*४१६. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री अंजनप्पा :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया का अमरीकी 'सुपरसोनिक' (आवाज की रफ्तार से भी अधिक तेज चलने वाले) विमान खरीदने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने तथा किन शर्तों पर ?

परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति से एयर इंडिया ने अमरीका सरकार की फ़ेडेरल एविएशन एजेन्सी के पास ३००,००० डालर जमा कर दिए हैं जिससे ३ अमरीकी सुपरसानिक परिवहन विमान मिल जाना रिजर्व हो जायें। यदि नवम्बर १९६५ से पहले एयर इंडिया इन विमानों को न लेने का निर्णय करे तो जमा धन बिना किसी जुर्माने के वापस हो सकता है।

बिना टिकट यात्रा

७५२. **श्री इ० मधुसूदन राव :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६३-६४ में विभिन्न रेलों में बिना टिकट यात्रा करने पर कितने व्यक्ति पकड़े गये ;

(ख) उन से जुर्माने के तौर पर कुल कितनी रकम वसूल की गई ;

(ग) इस के फलस्वरूप सरकार को यदि कोई हानि हुई, तो कितनी ; और

(घ) बिना टिकट यात्रा के फलस्वरूप सरकार को हर वर्ष अनुमानित औसतन कितनी हानि होती है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) १ अप्रैल से ३१ दिसम्बर, १९६३ तक की अवधि में बिना टिकट यात्रा करने पर लगभग ५७ लाख व्यक्ति पकड़े गये ।

(ख) इन यात्रियों से रेलवे किराया और सामान-शुल्क के रूप में वसूल की गई ११८ लाख रुपये की रकम के अतिरिक्त जुर्माने के रूप में ३८ लाख रुपये वसूल किये गये ।

(ग) और (घ). यह अनुमान है कि कुल बिना टिकट यात्रा प्रति वर्ष ५ करोड़ रुपये की जाती है; यह अनुमान सभी रेलों में एक वृहद जांच के आधार पर लगाया गया है । इसमें से रेलवे सामान्य टिकट चैक करने की व्यवस्था के जरिये किराया और अतिरिक्त शुल्क के रूप में लगभग २ करोड़ रुपये वसूल कर लेती हैं ।

उत्तरी अन्दमान के वन

७५३. **श्री अ० सिं० सहगल :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री ५ मार्च, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४८१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तरी अन्दमान के वनों के पट्टेधारियों से वर्ष १९५७-५८ के बाद से वार्षिक रूप में कुल कितनी इमारती लकड़ी निकालने की अपेक्षा की जाती है ;

(ख) पट्टेधारियों ने वास्तव में कितनी मात्रा निकाली ;

(ग) निर्यात की गई इमारती लकड़ी पर कितनी रायल्टी लगाई गई ;

(घ) वार्षिक निर्यात की क्या मात्रा है ; और

(ङ) शुल्क की रकम के विरुद्ध हर वर्ष कितनी रायल्टी वसूल की गई ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) यह जानकारी ५-३-६३ को लोक-सभा में दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या ४८१ के उत्तर में दी गई है ।

(ख) से (ङ). वर्ष १९६०–६१ तक के लिये जानकारी ५–३–१९६३ को लोक सभा में दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या ४८१ के उत्तर में दी गई है। बाकी वर्षों की जानकारी निम्न प्रकार है :

वर्ष	पट्टेधारी द्वारा वास्तव में निकाली गयी मात्रा	मिल में चोरी गई मात्रा समेत निर्यात की गयी इमारती लकड़ी पर लगायी गयी रायल्टी	निर्यात की गयी मात्रा	लगाये गये शुल्क के विरुद्ध हर वर्ष वसूल की गयी रायल्टी
	टनों में	रुपयों में	टनों में	रुपयों में
१९६१–६२ .	११,२५२	४,५७,८१५.०६	६,७०,१२०.९१	४,५७,८१५.०६
१९६२–६३ .	६,५९९	४,०१,३७७.२५	५,०७४,१५.०३	४,०१,३७७.२५
१९६३–६४ .	पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि अभी वर्ष समाप्त नहीं हुआ है।			

वाणिज्यक नौवहन अधिनियम के अन्तर्गत छूट

७५४. श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा: क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६०–६१, १९६१–६२ और १९६२–६३ में भारतीय वाणिज्यिक नौवहन अधिनियम की धारा ४५६ (१) के अन्तर्गत कितने मामलों में छूट दी गई है ;

(ख) यह छूट किस आधार पर दी गई है ; और

(ग) वर्ष १९६०–६१, १९६१–६२ और १९६२–६३ में इस अधिनियम की धारा ४५५ (२) के उल्लंघन किये जाने की क्या संख्या है ?

परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है जिस में आवश्यक जानकारी दी हुई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २४३८/६४]**

(ग) शून्य।

आन्ध्र में राष्ट्रीय राजपथ

७५५. श्री इ० मधुसूदन राव : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ दिसम्बर, १९६३ को आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजपथों का कुल मीलयोग कितना था ;

(ख) इन राजपथों के क्या नाम हैं ; और

(ग) क्या इस योजना के अन्तर्गत अन्य सड़कों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव है ?

परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) १४१२ मील।

(ख) इन राजपथों के नाम और प्रत्येक के मीलयोग निम्नलिखित तालिका में दिये गये हैं।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या	राष्ट्रीय राजपथ का नाम	मील योग
४	बम्बई-पूना-बंगलौर-मद्रास	५३
५	कलकत्ता-कटक-विशाखापटनम-मद्रास . .	६००
७	बनारस-नागपुर-हैदराबाद-बंगलौर-कन्याकुमारी .	४६४
९	पूना-हैदराबाद-बैजवाड़ा	२४१
४३	रायपुर-विजयनगरम	५४
		१४१२

(ग) जी, नहीं।

आन्ध्र प्रदेश में टेलीफोन

७५६. **श्री इ० मधुसूदन राव :** क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ दिसम्बर, १९६३ को आन्ध्र प्रदेश में (जिलावार) टेलीफोन एक्सचेंजों और टेलीफोनों की क्या संख्या है ;

(ख) क्या निकट भविष्य में इस संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया (देखिये संख्या एल० टी० २४३९।६४]**

(ख) जी, हां।

(ग) ब्योरा विवरण के कालम ५ में दिया गया है।

तम्बाकू की खेती

७५७. **श्री इ० मधुसूदन राव :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६३ में आन्ध्र प्रदेश में तम्बाकू की कुल कितनी खेती हुई ;

(ख) उसी अवधि में अन्य देशों को इसके निर्यात से कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी ;

(ग) वर्ष १९६३ में जिन देशों को इसका निर्यात किया गया, उनके नाम क्या हैं, प्रत्येक देश को तम्बाकू की कितनी मात्रा का निर्यात किया गया और प्रत्येक से कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई ; और

(घ) उसी अवधि में आन्ध्र प्रदेश से भारत के विभिन्न राज्यों को कुल कितने मूल्य का तम्बाकू भेजा गया ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) वर्ष १९६२-६३ में १३६२ लाख किलोग्राम ।

(ख) वर्ष १९६२-६३ में लगभग १७.६ करोड़ रुपये ।

(ग) एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २४४०/६७]**

(घ) अब तक केवल वर्ष १९६१-६२ के लिए मात्रा सम्बन्धी आंकड़े ही उपलब्ध हैं और ये आंकड़े २३८.८ लाख किलोग्राम हैं ।

कोचीन बन्दरगाह

७५८. **श्री ग्रं० व० राघवन :**
श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री केप्पन :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन बन्दरगाह टर्मिनस पर डीज़ल रेल इंजनों को वापस मुड़ने (टर्न-राउन्ड) सुविधायें देने की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) इस परियोजना की अनुमानित लागत क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी, हां ।

(ख) अनुमानित लागत ५०,००० रुपये है ।

कालीकट-मद्रास ट्रंक सर्किट

७५९. **श्री ग्र० व० राघवन :**
श्री केप्पन :
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कालीकट और मद्रास के बीच एक अतिरिक्त टेलीफोन ट्रंक सर्विस सर्किट की व्यवस्था करने के लिये क्या प्रगति की गयी है ; और

(ख) इसके कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) मद्रास ट्रंक एक्सचेंज अपनी कालों को मल्टी लिंक आपरेटर डायलिंग पद्धति द्वारा कालीकट सीधे डायल कर रहा है । मद्रास-कोयम्बटूर मार्ग पर एक अतिरिक्त केरियर पद्धति स्थापित करने के लिये प्रस्ताव है ताकि कालीकट ट्रंक एक्सचेंज भी मद्रास को सीधे टेलीफोन कर सके ।

(ख) इसके छः महीने के भीतर पूरा होने की आशा है।

खाद्य उद्योग

७६०. **श्री राम हरख यादव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार अक्तूबर, १९६३ में रोम में हुई खाद्य उद्योग के साथ खाद्य तथा कृषि संगठन/संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि की संयुक्त बैठक में की गयी सिफारिशों को क्रियान्वित करना चाहती है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस) : सरकार को अक्तूबर, १९६३ में रोम में हुई खाद्य उद्योग के साथ खाद्य तथा कृषि संगठन/संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि की संयुक्त बैठक की रिपोर्ट मिल गयी है। रिपोर्ट में निहित जो सुझाव भारत पर लागू होते हैं, उनका देश में अपने विकास कार्यक्रम बनाने में उचित उपयोग किया जायेगा।

दिल्ली में चीनी और गुड़ का वितरण

७६१. **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में चीनी और गुड़ के सही वितरण के बारे में देखभाल करने के लिये अचानक चैकिंग करने के लिये कुछ मजिस्ट्रेट लगाये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रणाली कैसे चल रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) और (ख). जी, हां। कुछ सब-डिविज़नल मजिस्ट्रेट अचानक निरीक्षण करते हैं और इसके अच्छे परिणाम निकले हैं।

रेलवे लाइन का मोड़ा जाना

७६२. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **रेलवे** मंत्री २१ अप्रैल, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ५४ के उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यास बांध परियोजना की कार्यान्विति के सम्बन्ध में रेलवे लाइन के मोड़े जाने के बारे में सर्वेक्षण, इस बीच पूरा हो गया है, यदि हां, तो कब और सर्वेक्षण पर कुल कितना व्यय होगा ;

(ख) इस परिवर्तन योजना के अन्तर्गत कितनी लम्बी रेलवे लाइन बदली जायेगी ; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत कितने रेलवे पुल बनाने होंगे और ये किन स्थानों पर बनाये जायेंगे और क्या वे संयक्त रेल-एंव-सड़क पुल होंगे ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) सर्वेक्षण के लिये क्षेत्र-कार्य १५-११-१९६३ को पूरा हो गया था परन्तु अभी परियोजना रिपोर्ट और प्राक्कलन तैयार करने का काम चल रहा है। प्राक्कलन समेत परियोजना रिपोर्ट के मार्च, १९६४ के अन्त तक तैयार हो जाने की आशा है। सर्वेक्षण पर कुल व्यय लगभग २,०३,५४१ रुपये बैठने का अनुमान है ।

(ख) वर्तमान लाइन की लम्बाई, जिसे मोड़ा जायेगा, १५.८४ मील है, लेकिन नयी लाइन की यही लम्बाई २१.३७ मील होगी।

(ग) इस नयी लाइन पर १७० रेलवे पुल बनेंगे। इनका ब्योरा सलग्न सूची में दिया गया है [**पुस्तकालय में रखा गयी। देखिये संख्या एल० टी० २४४१/६४**]। इनमें से कोई भी संयुक्त रेल-एव-सड़क पुल नहीं होगा।

वनों का विकास

७६३. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत में वनों का विकास करने के लिये कुछ और विदेशी विशेषज्ञों को बुलाना चाहती है ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). इस समय भारत सरकार की "वन संसाधनों का विनियोजन-पूर्व सर्वेक्षण" नामक एक परियोजना चालू है जिस पर अंशतः संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि से धन लगाया जायेगा। सर्वेक्षण और अन्य सम्बन्धित कार्यों के अपने वर्तमान वन संसाधनों के सुनियोजित उपयोग और चुने हुए औप उपयुक्त स्थानों में नये संसाधन बनाने में, जिनकी सुनियोजित आर्थिक विकास के लिये बड़ी आवश्यकता है, सहायक होने की आशा है। उपरोक्त परियोजना के लिये संचालन योजना के प्रारूप को अन्तिम रूप देने के सम्बन्ध में दो विदेशी विशेषज्ञों ने, एक खाद्य तथा कृषि संगठन से और दूसरे संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि से, हाल में भारत का दौरा किया। इस परियोजना की क्रियान्विति के लिये चार विदेशी विशेषज्ञों और कुछ परामर्शदाताओं की सेवाओं का लाभ उठाने का प्रस्ताव है। यह परियोजना वर्ष १९६४ में किसी समय चालू की जायेगी और यह लगभग ३ $^{1}/_{2}$ वर्ष तक चलेगी।

सवारी भत्ता

७६४. **श्री भी० प्र० यादव :**
श्री घवन :
श्री विशन चन्द्र सेठ :

क्या **डाक और तार** मंत्री १९ नवम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न सख्या १३५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्किल और प्रशासनिक कार्यालयों में गजेटेड पदों को गैर--गजेटेड लिपिक कर्मचारियों के लिये रक्षित करने और बड़े नगरों में सवारी भत्ता देने के प्रश्न सम्बन्धी अभ्यावेदनों पर तब से विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने क्या फैसला लिया है ?

डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) और (ख). मामला अभी विचाराधीन है।

सहकारी क्षेत्र में कमी

७६५. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन राज्यों के क्या नाम हैं जहां वर्ष १९६२–६३ में सहकारी क्षेत्रों में कमी रही ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): महाराष्ट्र, गुजरात और मद्रास को छोड़ कर सभी राज्यों में सहकारिता निधि के प्रयोग में कमी हुई है। उत्तर प्रदेश में यह कमी बहुत मामूली रही।

पर्यटक–मार्ग दर्शक

७६६. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटक मार्ग-दर्शकों की आवश्यकता के बारे में कोई मूल्यांकन किया गया है ; और

(ख) वर्ष १९६३–६४ में कितने पर्यटक मार्ग-दर्शकों को प्रशिक्षित किया गया ?

परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्रों में पर्यटक मार्ग-दर्शकों की आवश्यकता का प्रत्येक पर्यटन केन्द्र के सम्बन्ध में समय समय पर मूल्यांकन किया जाता है ।

(ख) वर्ष १९६३–६४ में औरगाबाद में चौदह पर्यटक मार्ग-दर्शकों को प्रशिक्षित किया गया ।

लाल किला

७६७. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली के लाल किले में ध्वनि और प्रकाश की सहायता से इतिहास के दृश्य प्रदर्शित करने के लिये प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो प्रथम प्रदर्शन कब होगा ?

परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां। सरकार ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है।

(ख) यह आशा है कि वर्ष १९६५ के आरम्भ में प्रदर्शन होगा और दर्शक लोग उसे देख सकेंगे।

दिल्ली में स्टेशन तक शटल रेलगाड़ियां

७६८. **श्री महेश्वर नायक** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उन लोगों की संख्या में असामान्य रूप से वृद्धि हो रही है जिन्हें दैनिक कार्य और व्यापार के मामले में रोज दिल्ली आना पड़ता है और रेलवे ने जितनी शटल सेवाओं की व्यवस्था की है, वह अपर्याप्त है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बढ़ते हुए यातायात के हल के लिये क्या व्यवस्था की जायेगी ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). हाल के वर्षों में नई दिल्ली/दिल्ली स्टेशनों पर स्थानीय यातायात में कुछ वृद्धि हुई है। इस यातायात का सामना करने के लिये पिछले तीन वर्षों में दस नयी गाड़ियां चलायी गयी हैं और वर्तमान नौ गाड़ियों की दूरी बढ़ा दी गयी है। स्थानीय यातायात के लिये कई गाड़ियों के भार में भी यथासंभव वृद्धि की गयी है।

रिवाड़ी-सदर बाजार सेक्शन पर यात्रियों के लिये अधिक आवास की व्यवस्था करने के लिये, इनके बीच चलने वाली डीजल कार सर्विस के स्थान पर अप्रैल, १९६४ से भाप से चलने वाली सेवा चालू करने का प्रस्ताव है। इसी तिथि से इस डीजल कार को सदर बाजार और गढ़ी हरसरू के बीच एक अतिरिक्त सवा के रूप में चलाया जायेगा ।

रेलवे ट्रैकों की विद्युतीकरण लागत

७६९. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रास, रूस और अमरीका में प्रति ट्रैक किलोमीटर के विद्युतीकरण की क्या लागत बैठती है ;

(ख) हमारे देश में यह लागत असामान्यत: अधिक है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) विदेशों में प्रति ट्रैक किलोमीटर के विद्युतीकरण की लागत के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

आसाम में स्वचालित टेलीफोन पद्धति

७७०. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या डाक और तार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम के उन कस्बों के क्या नाम हैं जहां अब तक स्वचालित टेलीफोन पद्धति लागू की जा चुकी है ;

(ख) आसाम में अन्य कस्बों में यह पद्धति लागू करने में अब तक कितनी प्रगति की गयी है ; और

(ग) आसाम के मुख्य कस्बों में अतिरिक्त टेलीफोनों की मांग और उपलब्धता में क्या अन्तर है ?

डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) बोरझर, हुग्रीजन, कांजीखोआ, मोहनबाड़ी, नजीरा, सेपोन और राबा ।

(ख) गोहाटी में २८०० मुख्य लाइनों के स्वचालित एक्सचेंज और शिलांग में २००० मुख्य लाइनों के स्वचालित एक्सचेंज के प्राक्कलन मंजूर कर दिये गये हैं। गोहाटी में इमारत बन कर तैयार होने वाली है और उपकरण प्राप्त किये जा रहे हैं। शिलांग में भवन-निर्माण कार्य आरम्भ हो गया है ।

बिजनी, डूमडोमा, धर्मनगर, गोलाघाट और कोहिमा में छोटे स्वचालित एक्सचेंजों के प्राक्कलन भी मंजूर किये गये हैं ।

(ग) आसाम के मुख्य कस्बों के सम्बन्ध में एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २४४२/६४]

बिजली से चलने वाली रेल गाड़ियां

७७१. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६२–६३ और १९६३–६४ में अब तक बिजली से चलने वाली कितनी रेलगाड़ियां चलाई गई हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): संभवत: निदेश विद्युत उपनगरीय सेवाओं के बारे में है। वर्ष १९६२–६३ में और १९६३–६४ में अब तक इस प्रकार चलायी गयी सेवाओं की संख्या और इस अवधि में वर्तमान गाड़ियों की बढ़ायी गयी सीमा की संख्या निम्न प्रकार है :

वर्ष	चलायी गयी विद्युत उपनगरीय विद्युत गाड़ियों की संख्या		
	सप्ताह के दिनों में	रविवार को	बढ़ाये गए सप्ताह के दिनों में
१९६२–६३ .	४८	५६	१०
१९६३–६४ .	*९९	१३	१७

*इसमें पूर्व रेलवे पर चलायी गई बिजली से चलने वाली वे ७६ गाड़ियां भी शामिल हैं जो प से चलने वाली ग ड़ियो के बदलें चलायी गयी ।

सफेद मिर्च

७७२. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने केरल में सफेद मिर्च पैदा करने की एक योजना का अनुमोदन कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) और (ख). सफेद मिर्च उगाने के लिये काली मिर्च के बीज को साफ किया जाएगा। वर्ष १९६१ में केरल राज्य में तालीपारम्बा में काली मिर्च अनुसंधान केन्द्र में सफेद मिर्च तैयार करने के बारे में एक कुछ प्राथमिक कार्य किए गए और सफेद मिर्च तैयार करने के लिए एक तरीका निकाला गया।

इस प्रकार के तरीके को मितव्ययतापूर्वक वाणिज्यिक स्तर पर अपनाने के लिए, भारतीय केन्द्रीय मसाला और काजू समिति ने केरल में तालीपारम्बा केन्द्र में किए जाने वाले कार्य के लिए एक अनुदान मंजूर किया है।

काजू का उत्पादन

७७३. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में काजू साफ करने वाल उद्योग को कितनी मात्रा में कच्चे काजू की आवश्यकता होती है ;

(ख) अब इसमें से कितनी मात्रा देश में पैदा होती है ;

(ग) कच्चे काजू में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ; और

(घ) केन्द्र द्वारा इस प्रयोजन के लिए अब तक कितनी रकम खर्च की गयी है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) चालू निर्यात के आधार पर भारत में काजू साफ करने के उद्योग की वार्षिक औसत आवश्यकता लगभग ३ लाख टन कच्चे काजू की है।

(ख) वर्ष १९६१-६२ (जिसके नवीनतम आंकड़े उपलब्ध हैं) में अनुमानतः १.२५ लाख टन कच्चे काजू का उत्पादन हुआ।

(ग) तीसरी योजनावधि में ८ लाख एकड़ अतिरिक्त क्षेत्र में काजू की खेती करने के लिये १.९० करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है। इस बारे में काजू उत्पादक राज्यों में विकास योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। इन योजनाओं में उत्पादकों को फसल ऋण, पट्टे पर भूमि देना और उगाने की सामग्री के रूप में प्रोत्साहन देने की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त मसालों और काजू के चतुर्मुखी विकास के लिए देखभाल करने के लिए भारतीय केन्द्रीय मसाला और काजू समिति नामक एक समिति स्थापित की गयी है।

(घ) राज्यों को केन्द्रीय सहायता दिए जाने की पुनरीक्षित प्रक्रिया के अन्तर्गत उनको उनकी वार्षिक योजनाओं में सम्मिलित कृषि उत्पादन योजनाओं के लिए वार्षिक रूप से इकट्ठा आवंटन किया जाता है।

House Building Loans to Railway Employees

774. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Railway employees who are governed by Payment of Wages Act are not given House building loans whereas Central Government employees are entitled for the same; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Shah Nawaz Khan): (a) No. The fact is that all Central Government employees, including Railway employees, who are governed by the Payment of Wages Act, are not given House building loan.

(b) This restriction has been imposed by the Ministry of Works, Housing and Rehabilitation, who are the Ministry concerned for controlling these loans, because under the provisions of the Payment of Wages Act, as they stand recoveries of such loans from the wages of the employees are prohibited.

Mango Canning Centre

775. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government are making arrangements for the opening of mango canning centres ;

(b) if so, the expenditure to be incurred on this scheme; and

(c) the places where such centres will be opened ?

The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Shri A. M. Thomas) : (a) The Department of Food has no proposals for opening of a Mango Canning Centre. However, the Department has a programme for starting four Demonstration-cum-community Canning and Preservation Centres where mangoes can also be processed and canned.

(b) The expenditure involved for each centres is as follows :—

Capital expenditure of Rs. 40,000 for equipment, machinery etc.

Recurring expenditure of Rs. 30,000 for staff, fuel, chemicals, contingencies etc.

(c) The centre at Delhi has already been started. Other three centres will be opened at Madras, Calcutta and Bombay shortly.

Fish plates on railway track near Godhra

776. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that fish plates on railway track near Godhra were removed during the first week of January, 1964 ;

(b) if so, whether investigations were made to find out as to who removed them ; and

(c) if so, the number of persons arrested in this connection ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) Yes.

(b) Yes.

(c) Three.

कृष्णा नदी पर पुल

७७७. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या **रेलवे** मंत्री १७ दिसम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७४८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृष्णा नदी पर दूसरा पुल बनाने के लिये प्रयोग स्पैन बनाने का कार्य आरम्भ कर दिया गया है ; और

(ख) क्या उक्त पुल के लिए अपेक्षित उच्च किस्म का सभी इस्पात प्राप्त हो गया है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, हां ।

(ख) पुल के गर्डरों के लिये अपेक्षित उच्च किस्म के इस्पात में से लगभग ८५ प्रतिशत कलकत्ता में प्राप्त हो गया है और बाकी मात्रा भी ब्रिटेन से भेज दी गयी है।

अमरीका से गेहूं की खरीद

७७८. **श्री बी० चं० शर्मा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में अमरीका से कुछ सख्त और सफेद गेहूं खरीदा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) और (ख). अमरीका से गेहूं पी० एल० ४८० करार के अन्तर्गत खरीदा जाता है। यह एक सतत कार्य है। हम कड़ा और सफेद दोनों प्रकार का गेहूं खरीद रहे हैं। जो किस्में खरीदी जा रही हैं वे हैं "हाड विन्टर", "वेस्टर्न व्हाइट" और "सोफ्ट व्हाइट" ।

आगरा में राष्ट्रीय राजपथ संख्या २ पर उपमार्ग के लिये भूमि का अर्जन

७७९. **श्री श० ना० चतुर्वेदी :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन किसानों को कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी गयी है जिनकी भूमि आगरा में राष्ट्रीय राजपथ सख्या २ पर एक उपमार्ग के निर्माण के लिए अर्जित की गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और कितनी रकम दी जानी है ?

परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी जय पथ सरकार से मांगी गयी है और सभा पटल पर रख दी जावेगी ।

मालाबार क्षेत्र में हवाई-अड्डा

७८०. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री अ० ब० राघवन :
श्री केप्पन :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने केरल के मालाबार क्षेत्र में प्रस्तावित हवाई अड्डे के लिए शिरुवन्नूर स्थान का चयन करने का फैसला किया है ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी भूमि अर्जित की जाएगी ;

(ग) क्या सरकार को शिरुवन्नूर में हवाई अड्डा बनाने के निर्णय के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन मिला है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमुहीउद्दीन) : (क) से (घ). कोजिकोड में प्रस्तावित हवाई अड्डे के लिए एक उपयुक्त स्थान का चयन करने के लिये कुछ स्थानों का सर्वेक्षण किया गया। शिरुवन्नूर का भी सर्वेक्षण किया गया और शिरुवन्नूर में प्रस्तावित हवाई अड्डे के निर्माण के विरुद्ध अभ्यावेदन भी हुए हैं। स्थान का अन्तिम रूप से चयन करने से पूर्व और सर्वेक्षण करने का निर्णय किया गया है।

भारतीय वन अधिनियम का संशोधन

७८१. **श्री हेम राज** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ३ दिसम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९९७ के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय वन बोर्ड ने भारतीय वन अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करने के लिए अपनी उपसमिति के प्रतिवेदन पर अपने निष्कर्षों को अन्तिम रूप दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इससे निकाले गए निष्कर्षों की एक प्रति सभा पटल पर रखी जावेगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय वन बोर्ड ने उपसमिति के प्रतिवेदन का अनुमोदन कर दिया है और सिफारिश की है कि उसको राज्य सरकारों को भेज दिया जाए जो अपने वन अधिनियमो में संशोधन करने के लिए कार्यवाही करेंगी। उपसमिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० २४४३ / ६४]**

Theft of Rice Bags

782. Shri Prakash Vir Shastri: Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in May, 1963 a goods train was stopped near Umri Railway Station's signal on Kacheguda-Manmad section and some bags of rice were dropped therefrom ;

(b) whether the Railway Board has conducted any enquiry into the matter ; and

(c) if so, the result thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Shah Nawaz Khan): (a) Yes.

(b) No, since the rice bags were not entrusted to the Railways for carriage. The Inspector, Government Railway Police, Aurangabad, conducted enquiries

and submitted the report to the Supdt. of Police, Nagpur fixing responsibility on the train crew and Head Constable, G.R.P. Umri.

(c) Departmental action against the G.R.P. Head Constable is pending finalization with the Supdt. of Police, Nagpur. No action against the train crew has been taken as there is no evidence against them, as ascertained on subsequent enquiry.

मंडीकोटला के समीप गाड़ी का पटरी से उतर जाना

७८३. **श्री विश्व नाथ पाण्डेय :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, १९६४ में दक्षिण-पूर्व रेलवे के नागपुर-कलकत्ता सेक्शन पर नागपुर से ८० किलोमीटर दूर मंडी कोटला के समीप एक माल गाड़ी का इंजन और ३ डिब्बे पटरी से उतर गए ;

(ख) यदि हां, तो गाड़ी के पटरी से उतरने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस दुर्घटना के कारण रेलवे को कितनी हानि ई ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) ७-१-६४ को मंडीकोटला और तुमसर रोड स्टेशनों के बीच देवहाडा खुर्द ब्लाक हट पर एक मालगाड़ी का इंजन और ६ डिब्बे पटरी से उतर गए ।

(ख) कारणों की जांच हो रही है ।

(ग) लगभग ५२,५०० रु० ।

Electric trains from Sealdah to Ranaghat.

784. **Shri Vishwa Nath Pandey** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to run four more electric trains between Sealdah and Ranaghat ; and

(b) if so, when these trains would start functioning ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) No.

(b) Does not arise.

Sugar Mills in U. P.

785. **Shri Ram Sewak Yadav :**
Shri Bagri :
Shri Vishwa Nath Pandey :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that sugar mills in the western districts of U. P. will be closed down earlier this year due to shortage of sugarcane ;

(b) whether Government are aware that the sugar mills have offered to pay to the cane producers at the rate of Rs. 2·50 nP. per maund for getting more sugarcane ; and

(c) if so, the reaction of Government in this respect ?

The Minister of state in the Ministry of Food and agriculture (Shri A. M. Thomas) : (a) No Sir, not as compared with the previous year.

(b) Yes, Sir.

(c) The Government of U. P. have already decided to remit cane cess to the extent of half the cane price paid by sugar factories in U. P. in excess of Rs. 21/- per maund. The question of how to compensate sugar factories for the balance half of the increased cane price paid by sugar factories is under the consideration of the Central Government.

सूरत में हवाई क्षेत्र

७८६. **श्री दे० जी० नायक :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के विभिन्न वाणिज्यिक संस्थानों ने सूरत में हवाई क्षेत्रों के लिए मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) और (ख) सूरत में एक हवाई क्षेत्र के निर्माण के लिए कुछ वाणिज्यिक सस्थानों ने मांग की थी। असैनिक उड्डयन के विकास क लिए उपलब्ध सीमित निधियों को ध्यान में रखते हुए सरकार की सामान्य नीति यह है कि उन स्थानों पर हवाई अड्डों का निर्माण किया जाए जो कि अखिल भारतीय असैनिक उड्डयन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं अथवा जिनके ऊपर से इन्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन की नियमित रूप से विमान चलाने की योजनाए हैं। कारपोरेशन की सूरत पर से निकट भविष्य में विमान चलाने की कोई योजना नहीं है। इस लिए निकट भविष्य में सूरत में हवाई अड्डे के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

उत्तर रेलवे पर हाल्ट स्टेशन

७८७. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे पर कितने हाल्ट स्टेशन हैं ; और

(ख) इन हाल्ट स्टेशनों पर प्रति मास कितनी राशि व्यय की जाती है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) २ ।

(ख) ५०,६६० रु० ।

रोपड़–नंगल बांध लाईन

७८८. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री १९ मार्च, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९६३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मामले में क्या अन्तिम निर्णय किया गया है ;

(ख) क्या करार के बारे में पंजाब सरकार से कोई बातचीत हुई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसका कब निर्णय होगा ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) से (ग) यद्यपि पंजाब सरकार लागत के अपने भाग को सहन करने के लिए राजी नहीं हुई है, रेलवे प्रशासन इस की बात जांच कर रहा है कि क्या रोपड़-नंगल सेक्शन पर रेलवे के खर्चे पर आवश्यक सवारी सुविधाओं की व्यवस्था हो सकती है ।

डेरी परियोजना

७८९. **श्री केप्पन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में भारत-स्विटज़रलैण्ड डेरी परियोजना में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या चारा पैदा करने के लिए भूमि के उपजाऊपन का अनुसंधान सन्तोषजनक रहा है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) परियोजना ने सितम्बर, १९६३ से काम करना आरम्भ कर दिया है। परियोजना के तीन भागों, अर्थात् इंजीनियरिंग, पशु पालन और कृषि के बारे में स्थिति निम्न है :—

इंजीनियरिंग :—इमारतों का निर्माण, सड़कें बनाना और अन्य इंजीनियरिंग कार्य सभी सन्तोषजनक रूप से चल रहे हैं। कर्मशाला, सांड केन्द्र, पशुचिकित्सा केन्द्र, पशु बाड़ा आदि के निर्माण का कार्य तेजी पर है।

पशु पालन :—लगभग सौ स्थानीय ढोर खरीदे जा चुके हैं और ये पशु "स्विस ब्राउन स्पर्म्स" का इस्तेमाल कर के नस्ल सुधार संबंधी अनुसंधान के लिए आधार स्वरूप होंगे। 'स्विस ब्राउन स्पर्म्स' बहुत अधिक ठंडी अवस्था में तरल नाइट्रोजन डिब्बों में शीघ्र ही परियोजना में पहुंचने आरम्भ हो जायेंगे।

कृषि :—लगभग ३०० एकड़ भूमि साफ कर दी गई है और चारा उत्पादन के लिये ठीक बना दी गई है। परियोजना के लगभग १० एकड़ प्रतिनिधि क्षेत्र का एक चारा अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया जा रहा है। क्षेत्र में सभी मिट्टियों का विश्लेषण किया जा चुका है। पशुओं की चराई में प्रयुक्त 'क्लोवर' और 'राई' सदृश स्विटजरलैण्ड की घास का उपज संबंधी परीक्षण चारा गवेषणा केन्द्र में किया जाएगा।

(ख) चारे के विकास के लिये भूमि के उपजाऊपन के संबंध में किए गए प्रारम्भिक कार्य के सन्तोषजनक परिणाम निकले हैं।

रतलाम से गोधरा तक रेलवे लाइन

७९०. **श्री दे० जी० नायक** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे के रतलाम और गोधरा स्टेशनों के बीच दोहरी रेलवे लाइन के निर्माण के लिये अर्जित की गई भूमि के मुआवजे अभी भी कुछ भूमि के मालिकों को नहीं दिए गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख) सभी मामलों में मुआवजे भूमि के मालिकों को मध्य प्रदेश और गुजरात की राज्य सरकारों द्वारा दे दिये गये हैं, जिन्होंने कि गोधरा-रतलाम दोहरी लाइन परियोजना के लिये रेलवे की ओर से भूमि अर्जित की है। गुजरात की राज्य सरकार द्वारा अर्जित की गई भूमि के भाड़े संबंधी मुआवजे कुछ जमींदारों को रेलवे अधिकारियों द्वारा अभी तक इस लिए नहीं दिये जा सके क्योंकि उनको जमींदारों का पता लगाने, उनको पहचानने और भुगतान करने में अनेक कठिनाइयां थीं। तथापि इस बात की व्यवस्था कर ली गई है कि ३,०५३ रु० की बकाया राशि राज्य राजस्व अधिकारियों को दे दी जाये जो कि इसका जमींदारों को शीघ्र भुगतान करने के लिये राजी हो गए हैं। कुल किराये की देय रकम ७,५५५ रु० थी जिसमें से ४,५०२ रु० रेलवे कर्मचारियों द्वारा दे दी गई थी।

उर्वरक प्रदर्शन कार्यक्रम

७९१. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामुदायिक विकास की राष्ट्रीय संस्था ने हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में उर्वरक प्रदर्शन कार्यक्रमों के काम का अध्ययन पूरा किया है।

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य उपपत्तियां क्या हैं ; और

(ग) प्रदर्शन कार्यक्रमों की त्रुटियों के उन्मूलन के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) राज्य सरकारों के मार्ग प्रदर्शन के लिये खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के विस्तार निदेशालय द्वारा एक "प्रभावशाली और उद्देश्यपूर्ण प्रदर्शन" नाम की पुस्तिका तैयार की गई है, जिस में प्रदर्शनों की उचित योजना और खाके बनाने के तरीके दिये गये हैं। राज्यों के क्षेत्रीय दौरों, सम्मेलनों तथा केन्द्रीय दलों द्वारा कृषि कार्यक्रमों की समीक्षा के दौरान प्रदर्शन कार्यक्रम के महत्व पर समय समय पर जोर दिया गया है।

तूतीकोरिन विकास योजना

७९२. श्री उमा नाथ : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वीकृत परियोजना प्रतिवेदन (पत्तन विकास योजना) में तूतीकोरिन नगर को तूतीकोरिन पत्तन से मिलाने वाली (पहली लाइन, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन समुद्र तट) प्रस्तावित सड़क के निर्माण में परिवर्तन के लिये कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या ब्योरे हैं ;

(ग) क्या सरकार को मूल परियोजना के किसी भी परिवर्तन के विरुद्ध तूतीकोरिन के किसी भाग से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो परिवर्तन के विरोध पर सरकार की क्या प्रतिक्रियाएं हैं?

परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) से (घ). क्योंकि तूतीकोरिन में प्रस्तावित पत्तन नगर से दूर बनाया जायेगा, इस लिये नगर और पत्तन के बीच उपयुक्त सड़कें बनानी पड़ेंगी। तटीय सड़कों का प्रस्तावित रेखाकरण, जो कि अनन्तिम है, के विरुद्ध कुछ नमक निर्माताओं से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। कुछ अभ्यावेदन रेखाकरण के पक्ष में भी प्राप्त हुए हे ये सब अभ्यावेदन सरकार के विचाराधीन हैं।

प्रति एकड़ उर्वरकों का उपयोग

७९३. **श्री शशि रंजन**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय हमारे देश में प्रति एकड़ कितना उर्वरक उपयोग में लाया जाता है?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): १९६२-६३ में फसल उगाये जाने वाले क्षेत्र में प्रति एकड़ विभिन्न उर्वरकों के उपयोग की मात्रा निम्न थी:—

नाइट्रोजन (एन)	फासफोरिक एसिड (पी० २०५)	पोटाश (के० २०)	कुल संयंत्र न्यूट्रियेंट
किलोग्राम	किलोग्राम	किलोग्राम	किलोग्राम
०.९३	०.२९	०.१०	१.३२

गुब्बारे नुमा खाद्यान्न स्टोर

७९४ { **श्री रामहरख यादव**
श्री दी०चं० शर्मा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंगलैंड की सरकार ने भारत को सुरक्षापूर्वक खाद्यान्न रखने के लिये एक ५०० टन की क्षमता का गुब्बारे नुमा बढ़ने वाला गोदाम देने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो पेशकश की क्या शर्तें हैं; और

(ग) योजना का उद्देश्य क्या है?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) जी, हां।

(ख) और (ग). गर्म जलवायु में माल जमा करने के लिये तकनीकी ज्ञान इकट्ठा करने की दृष्टि से यह पेशकश ऋण के आधार पर की गई है।

उर्वरक के रूप में गोबर

७९५. **श्री हेडा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का कृषि उत्पादन को बढ़ाने की दृष्टि से गोबर और मल को उर्वरकों के रूप में इस्तेमाल करने का प्रस्ताव है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): जी हां । १९५७-५८ से गोबर और मल को खाद के रूप में इस्तेमाल करने की योजनाएं राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा राज्य योजना की परियोजनाओं के रूप में क्रियान्वित की जा रही हैं ।

रेलवे के पुर्जों का निर्माण

७९३. **श्री राम हरख यादव :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रेलवे के पुर्जों के निर्माण के लिये कालका में एक नया उत्पादन यूनिट बनाना चाहती है ; और

(ख) परियोजना के ब्योरे क्या हैं और इस पर लगभग कितना खर्च आयेगा ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) कालका में वर्तमान कर्मशाला का उचित रूप से विस्तार करने का प्रस्ताव है जिससे कि रेलवे के कुछ विशेष पुर्जों का बड़ी मात्रा में निर्माण हो सके ।

(ख) ब्योरों की जांच हो रही है और परियोजना प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने के पश्चात् ही योजना की अनुमानित लागत का पता चल सकेगा ।

आसाम सरकार का ज्ञापन

७९७. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम सरकार ने उन के उस राज्य में हाल के दौरे के दौरान एक ज्ञापन प्रस्तुत किया ;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन में दी गई मुख्य मांगें क्या हैं ;

(ग) इन मांगों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, हां ।

(ख) ज्ञापन में निम्नलिखित मुख्य सुझाव दिये हैं :—

(१) बड़ी लाइन को बरास्ता रंगिया नोनगई गांव से गोहाटी तक बढ़ाना ;

(२) बरास्ता गोलपाड़ा पंचरतन घाट से गोहाटी तक एक रेलवे लाइन का बिछाया जाना ; दारनगिरी (गारो पहाड़ी) से दुधनै के समीप पंचरतन घाट—गोहाटी लाइन को मिलाने वाली दूसरी लाइन का बिछाया जाना ;

(३) गोहाटी और खासी जयन्तिया पहाड़ियों के बीच रेलवे लाइन, इसका सिलचर तक और फिर मनीपुर तक बढ़ाया जाना ;

(४) मिज़ो पहाड़ियों तक रेलवे सम्पर्क ;

(५) जोगी घोपा में नया रेल-एवं-सड़क पुल ;

(६) मोरनहट को डिबरूगढ़ से मिलाने वाली रेलवे लाइन ;

(७) आसाम और त्रिपुरा के बीच रेल संपर्क ; और

(८) गोहाटी और बरोनी / लखनऊ के बीच तेज चलने वाली गाड़ियों की व्यवस्था अथवा १ डाउन/२ अप अवध-त्रिहितु डाक गाड़ियों और ३ डाउन/४ अप आसाम डाक गाड़ियों की गति को तेज़ करना ।

(ग) तृतीय योजना काल में रेलवे के नई लाइनों के निर्माण के कार्यक्रम में ऊपर संख्या १—७ के आगे दी गई कोई भी नई लाइन शामिल नहीं की गई है । नई लाइनों के निर्माण के लिये उपबन्ध धन और संसाधन योजना आयोग की स्वीकृति से नई लाइनों के लिये किये गये वायदों पर खर्च हो जायेंगे । इसलिये चालू योजना के शेषकाल में ऊपर दी गई नई लाइनों का कोई भी प्रस्ताव पूरा नहीं किया जा सकता ।

तेज चलने वाली गाड़ियों के दो जोड़े अर्थात् १/२ ए० टी० डाक गाड़ियां और ३/४ आसाम डाक गाड़ियां एक ओर गोहाटी और दूसरी ओर बरौनी और लखनऊ के बीच पहले से ही यात्रा के लिये उपलब्ध हैं। अप्रैल, १९६४ से जो समय सारणी लागू होगी उस में यह व्यवस्था है कि गोहाटी–लखनऊ ए० टी०, लखनऊ गोहाटी और बरौनी आसाम डाक गाड़ियां और तेज चलने लगेंगी और क्रमश: ३५, ५० और २५ मिनट कम लिया करेंगी । अपेक्षित लाइन क्षमता और इंजनों के अभाव के कारण इस समय गोहाटी और बरौनी। लखनऊ के बीच और गाड़ियां चलाना सम्भव नहीं है । तथापि १७-२-६४ से एक ओर लखनऊ और दूसरी ओर सिलीगुड़ी के बीच २–४ सैनिक गाड़ियों के थोड़े-थोड़े समय पर चलने से इन स्थानों के बीच असैनिक यात्रियों को यात्रा में काफी आराम मिलेगा ।

अन्तर्राज्य परिवहन कर

७९८. श्री मान सिंह पृ० पटेल : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राज्य परिवहन से प्राप्त कर की आमदनी को बांटने के लिये एक अध्ययन दल की नियुक्ति की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसने क्या सिफारिशें की हैं ?

परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) अन्तर्राज्य परिवहन से प्राप्त कर की आमदनी को विभिन्न संबंधित राज्यों में बांटने के युक्तियुक्त आधार के लिये सिफारिश करने के लिये एक सरकारी अध्ययन दल स्थापित किया गया है।

(ख) दल ने अभी अपना काम पूरा नहीं किया है।

गाजियाबाद-दिल्ली मार्ग पर गाड़ियां

७९९. {श्री विश्वनाथ पांडेय :
श्री राम हरख यादव :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ८ फरवरी, १९६४ की सुबह को गाजियाबाद दिल्ली मार्ग पर गाड़ियों के चलने में बहुत बाधा पहुंची क्योंकि यात्रियों और विद्यार्थियों ने गाड़ियों के चलने में रुकावट डाली; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां।

(ख) ८-२-६४ को गाजियाबाद–शकूरबस्ती पाइलट गाड़ी के ७ बजकर २० मिनट पर गाजियाबद से चलने के पश्चात् कुछ यात्री इस गाड़ी की ब्रेक वैन में घुस गये। इन यात्रियों को उतारने के लिये गाड ने गाड़ी को रोका। पाइलट गाड़ी तत्काल ही नहीं चल सकी क्योंकि इसके ब्रेक ब्लाक्स सख्त हो गये। ब्रेक ब्लाकों को ढीला किया गया और गाड़ी दोबारा ७.४५ पर चली। इसके परिणामस्वरूप आई० आर० जी० जी० डाउन गाजियाबाद-रोहतक शटल गाजियाबाद से १६ मिनट देर से चली। रास्ते में इस गाड़ी की खतरे की जंजीर को यात्रियों ने बार बार खेंचा और इससे भी बाधा पड़ी।

मुर्गीपालन फार्म कार्यक्रम

८००. {श्री सुबोध हंसदा :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तथा कृषि संगठन का हमारे देश में मुर्गीपालन फार्म कार्यक्रम के लिये वित्त पोषण करने का प्रस्ताव था ;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष में कितनी सहायता देने का प्रस्ताव है ;

(ग) क्या फार्म स्थापित करने के लिये कोई योजना बनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो ये फार्म कहां स्थापित किये जायेंगे ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) से (घ). खाद्य तथा कृषि संगठन के अपने संसाधनों से वित्तीय सहायता की कोई पेशकश नहीं है। तथापि आस्ट्रेलिया की भूक से छुटकारा आंदोलन समिति, बाबुगढ़ में मुर्गीपालन विकास परियोजना के लिये १३०,००० डालर के मूल्य का एक 'फीड मिक्सिग प्लांट' देने के लिये राजी हो गई है। विश्व खाद्य कार्यक्रम ने भी उसी परियोजना के लिये २,००० मीट्रिक टन मकई, जिसका मूल्य १,७१,९०० डालर है, देने का वायदा किया है।

आशा है कि दाना बनाने का संयंत्र और मकई चालू वष में आ जायेंगे। बाबुगढ़ में मुर्गीपालन फार्म पहले से ही काम कर रहा है।

रेलों में सोने के लिये स्थान

८०१. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी रेल गाड़ियों के दूसरे दर्जे के डिब्बों में सोने के लिये स्थानों (स्लीपिंग बर्थस्) की व्यवस्था करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इस समय मामला किस अवस्था में है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) प्रयोग के रूप में दूसरे दर्जे के 'स्लीपर कोच' हाल ही में गाड़ियों के दो जोड़ों में चालू किये गये हैं —एक दिल्ली और लखनऊ के बीच और दूसरा मद्रास सेन्ट्रल और हावड़ा के बीच।

(ख) सुविधा की अन्य गाड़ियों में व्यवस्था के प्रश्न पर इन प्रयोगों के परिणाम देख कर ही विचार किया जा सकता है।

Licence for Cheap Radio Sets.

802. **Shri Bade :**
Shri Brij Raj Singh :

Will the Minister of **Posts and Telegraphs** be pleased to state :

(a) whether licence fee on cheap radios is not charged ;

(b) whether on account of this facility radios like Philips are reported as being sold at lower prices ;

(c) whether such complaints have been received from Nagpur ; and

(d) whether these cases have been challenged in law courts ?

The Deputy Minister in the Department of Posts and Telegraphs (Shri Bhagavati): (a) The normal licence fee is Rs. 15/- p.a. but concessional licence fee of Rs. 7·50 p.a. is charged for cheap radios *i.e.* radios costing upto Rs. 125/- inclusive of all taxes except Sales tax.

For toy radios or crystal sets which do not work from batteries or electric power, no licence fee is charged.

(b) Many manufacturers have brought out sets costing Rs. 125/- or less, in order to popularise the radios and allow the customer the benefit of a concessional licence.

(c) No such complaints have been received, but we do receive requests for extending the scope of the concession *i.e.* for changing the price ceiling of Rs. 125/- for defining cheap sets.

(d) No Sir, no such case has been challaned by the P.&T. Department.

मद्रास में 'कैरैवल' विमान को न उड़ाना

८०४. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरवरी, १९६४ के दूसरे सप्ताह में कुछ दिनों के लिये मद्रास में "कैरैवल" विमान को उड़ाया नहीं गया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं. और

(ग) इसको कितने समय तक नहीं उड़ाया गया था?

परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन): (क) और (ख). जी हां। "कैरैवल" विमान वी० टी०—डी० पी० एन० जिसको ६ फरवरी, १९६४ को बम्बई-मद्रास के बीच अपनी संख्या १०१ उड़ान करनी थी, को 'नोजव्हील एक्सल बेयरिंग' में खराबी के कारण नहीं उड़ाया गया था।

(ग) फ्रांस से आवश्यक पुर्जे आ जाने के बाद विमान को १४ फरवरी, १९६४ को उड़ने योग्य बनाया गया था।

रेलगाड़ियों में रेडियो लगाना

८०५. **डा० प० श्रीनिवासन :**
श्री परमशिवन :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यात्रा में नीरसता दूर करने के लिये दूर जाने वाली यात्री गाड़ियों में क्या रेडियो लगाने का कोई प्रस्ताव है?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : २-४-६० से प्रयोग के तौर पर हावड़ा–नई दिल्ली–मद्रास के बीच चलने वाली एयरकन्डीशन्ड गाड़ी के एक रेक मे आकाशवाणी के समाचार तथा संगीत के प्रसारण को लागू किया गया था।

अन्य एयरकन्डीशन्ड एक्सप्रेस गाड़ियों में आकाशवाणी के समाचार तथा संगीत के प्रसारण करने के प्रश्न पर विचार किया गया था तथा यह निर्णय किया गया था कि अभी अन्य किसी गाड़ी मे इसको लागू नहीं किया जाये।

दिल्ली से मद्रास को गाड़ियां

८०६. **डा० प० श्रीनिवासन :**
श्री परमशिवन :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से मद्रास तथा मद्रास से दिल्ली को भीड़भाड़ कम करने के लिये अतिरिक्त गाड़ियां चलाने का कोई विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख). ग्रान्ड ट्रंक रूट पर यात्री यातायात को पूरा करने के लिए सप्ताह में दो बार एयर कन्डीशन्ड एक्सप्रेस के समय पर ही अप्रैल, १९६४ से दो और एक्सप्रेस गाड़ियां चलाने का विचार है। गाड़ी मद्रास से रविवार तथा बुधवार को तथा नई दिल्ली से रविवार और गुरुवार को चलेगी।

नई रेलवे लाइनें

८०७. **डा० प० श्रीनिवासन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिरूनेलवेली से कन्याकुमारी तथा कन्याकुमारी से त्रिवेन्द्रम तक नई रेलवे लाइन बिछाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख) इस लाइन की आरंभिक इंजीनियरिंग तथा यातायात सर्वेक्षण के लिये स्वीकृति दे दी गयी है और कार्य हो रहा है। परन्तु प्रस्तावित लाइन तीसरी पंचवर्षीय योजना में रेलवे निर्माण कार्यक्रम शामिल नहीं की गई है।

अस्पृश्यता

८०८. **श्री नि० रं० लास्कर** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांवों में अस्पृश्यता की प्रथा का पता लगाने का काम पंचायत समितियों को सौंपा गया है ; और

(ख) इस संबंध में पंचायत समितियों को और क्या काम सौंपा गया है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) और (ख) राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि पंचायती राज संस्थाओं के विशेष आदेश दिए गए जिनमें अस्पृश्यता क्षेत्र के बारे में शिक्षा आदि के काम को स्पष्ट किया गया है तथा सुनिश्चित करे कि इस प्रकार की गड़बड़ी अनुसूचित जातियों पर लागू न हो।

पंजाब के डाकघरों का दरजा बढ़ाया जाना

८०९. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६४ में पंजाब में और कुछ उप-डाकघरों को मुख्य डाकघर और शाखा डाकघरों को उप-डाकघर बनाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ; तथा उनका कब दर्जा बढ़ाया जायगा ?

डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए एल० टी० संख्या २४४४/६४]**

प्रगतिशील किसानों की तालिका

८१०. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रगतिशील किसानों की सलाहकार तालिका बनाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उनके गठन तथा कार्यों के बारे में क्या विचार किया गया है, और

(ग) क्या अधिक उत्पादन करने के लिये किसानों को और कोई प्रोत्साहन दिये जाने का विचार है, और यदि हां, तो किस रूप में ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) खण्ड जिला और राज्य स्तरों पर प्रगतिशील किसानों की सलाहकार तालिकाएं बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) प्रस्ताव में यह विचार है कि तालिकाओं को चुनने का किसी राज्य स्तर पर राज्यों की सरकारों द्वारा, जिला स्तर पर जिला परिषद द्वारा, और खण्ड स्तर पंचायत समितियों द्वारा किया जाएगा। जिला और खण्ड स्तर की तालिकाओं में क्रमश: जिला और खण्ड के चुने हुए प्रगतिशील किसान होंगे, जिसको उनकी फसल की उपज, स्थानीय स्थितियों के अनुकूल वैज्ञानिक तरीकों और अन्य कसौटियों के उपयोग के आधार पर चुना जाएगा। तालिकाओं का उपयोग गवेषण संस्थाओं, बीज फार्मों, प्रदर्शनियों, कृषि कार्यक्रमों की आयोजना तथा क्रियान्विति के लिये विविध स्तरों पर अधिकारियों द्वारा सलाहकार की हैसियत में किया जाएगा।

(ग) किसानों को कुछ फसलों के गारंटी शुदा दामों, विविध कार्यों के लिये अर्थ सहायता उत्पादन कार्यों के लिये ऋणों, पारितोषकों तथा नकदी में पुरस्कारों के रूप में, उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं। किसानों को उपज बढ़ाने के लिये अपेक्षित उत्पादन में अधिक धन लगाने के लिये प्रोत्साहन देने के लिये और अधिक प्रोत्साहनों की व्यवस्था का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

Slaughter Houses

811. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(*a*) Whether it is a fact that due to unhygienic condition of slaughter houses in Delhi, Government propose to shift them from their present sites; and

(*b*) if so, when ?

The Minister of State in the Ministry of Food & Agriculture. (Shri A. M. Thomas) : (*a*) A proposal to shift the slaughter house from its present location in a congested residential area, is under the consideration with the Delhi Minicipal Corporation.

(*b*) No decision has yet been taken.

गुजरात में नलकूपों की खुदाई

८१२. **श्री मान सिंह प० पटेल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में गुजरात राज्य में सिंचाई के लिये नलकूप खोदने में कितनी प्रगति हुई है। और ;

(ख) क्या सरकार ने प्रगति को तेज करने के लिये कोई कदम उठाये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थोमस) : (क) गुजरात राज्य में तीसरी पंचवर्षीय योजना में खोदे गये ५३७ नलकूपों में से (पीछे के आगे लाये गये और नए) अब तक ८५ नल कूप खोदे गये हैं।

(ख) खुदाई कार्यक्रम को तेज करने के लिये कुछ में ५० नलकूपों की खुदाई का काम राज्य सरकार द्वारा खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के प्रयोगात्मक नलकूप संगठन को सौंप दिया गया हैं।

गाड़ी में लगी वस्तुओं की चोरी

८१३. **श्री हेम राज** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० से १९६३ के बीच वर्षवार तथा खण्ड वार गाड़ी में लगी वस्तुओं की कितनी चोरियां हुई हैं। और ;

(ख) उन की वर्षवार तथा खण्ड वार कितनी लागत थी ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) : अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० २४४५ / ६४]**

Over-Bridge at Bikaner Station

814. { **Shri P. L. Barupal:**
Shri Hem Raj:

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(*a*) Whether it is a fact that the bodies like Traders Association and Urban Improvement Trust have sent telegrams and letters opposing the proposal of the Ministry of Railways to construct an over-bridge at Bikaner on the Northern Railway ; and

(*b*) if so, the decision taken thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri S. V. Ramaswamy): (*a*) & (*b*) A telegram was received from the Secretary, Bikaner Vyapar Mandal to stop construction of Road overbridge near level crossing No. 2 pending furhter examination of alternative schemes being proposed by them in their detailed memorandum. The memorandum is awaited.

उपभोक्ता सहकारी भण्डार

८१५. **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६३–६४ में (३१ जनवरी १९६४ तक) देश में थोक उपभोक्ताओं सहकारी भण्डारों को कुल कितनी राशि की ऋण की सहायता दी गई ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : १९६३–६४ में ३ जनवरी ६४ तक थोक उपभोक्ता सहकारी आधारों पर देश में, केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजना के अधीन, १९२.८१ लाख रु० और १३.८२ लाख रुपये क्रमशः ऋण और अनुदान के रूप में दिये गये।

Neera

816. **Shri Onkar Lal Berwa:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that the demand for Neera has considerably increased :

(*b*) if so, the steps being taken by Government to increase its production ; and

(*c*) the names of the areas where it is produced in plenty ?

The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Shri A. M. Thomas): (*a*) to (*c*). The information is being collected and will be laid on the Table of the Lok Sabha.

मिलों को गन्ने का सम्भरण

८१७. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री बिशन चन्द्र सेठ ।
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार और पूर्व उत्तर प्रदेश के कुछ चीनी मिल, गन्ने के उत्पादन में कमी होने के कारण पूर्णतया काम नहीं कर सके ; और

(ख) उस क्षेत्र में गन्ने की फसल को बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी हां ।

(ख) इन दो क्षेत्रों में इस वर्ष से फैक्ट्री क्षेत्रों में गन्ने की खेती का सघन विकास करने की एक योजना मंजूर की गई है ।

बिना टिकट यात्रा

८१८. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे ने ८ फरवरी से १२ फरवरी' ६४ तक बिना टिकट यात्रा के विरुद्ध विशेष आन्दोलन किया था ; और

(ख) यदि हां, तो कितने बिना टिकट यात्री गिरफ्तार किये गये ; जुर्माने लिए गये और जेल भेजे गये ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनावज खां) : (क) जी, हां । दिल्ली क्षेत्र में ;

(ख) गिरफ्तार किये गये १३४ लोगों में से ११४ पर जुर्माने किये गये और २० को जुर्माना न देने के कारण जेल भेजा गया ।

Payment of Provident Fund

819. **Shri Kachhavaiya :**
Shri Gokaran Prasad :
Shri Y. S. Chaudhary :
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(*a*) the number of employees who died on duty since 1953 on North Eastern Railway ;

(*b*) the number of those out of them whose successors have not received the amount of their bonus and provident fund so far ;

(*c*) the reasons for non-payment of the said amount;

(*d*) whether it is a fact that there are some persons who died on North Eastern Railway in 1953 on duty and whose successors have not received their bonus and Provident Fund so far ; and

(*e*) if so, the reasons for delay in the Payment of these amounts ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Shah Nawaz Khan). (*a*) 142.

(*b*) 10.

(*c*) Non-receipt of legal documents 7
Non-receipt of clearance certificates 1
Under scrutiny in Accounts 2

(*d*) No.

(*e*) Does not arise.

पाकिस्तान को भेजे गये रेलवे वैगन

८२०. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१ से १९६३ के बीच कितने रेलवे वैगन सीमेंट से भरे हुए पाकिस्तान भेजे गये ;

(ख) इनमें से कितने स्वदेश लौट आये और कितने अभी तक वहां हैं ;

(ग) इन वैगनों द्वारा उपरोक्त अवधि में कितना सीमेंट भेजा गया ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) २८८४ वैगन। इन में २६८ वैगन, जो १९६१ में पाकिस्तान रेलवे पर के स्टेशनों के लिये बुक किये गये थे, अफगानिस्तान के लिये थे।

(ख) भारतीय और पाकिस्तान रेलों के बीच वैगन लेने देने की प्रक्रिया वही है जो भारतीय जोनल रेलों के बीच हैं, अर्थात्, सभी परस्पर बदले जा सकने वाले वैगन एक देश से दूसरे देश को भेजे जा सकते हैं, चाहे उनका मालिक कोई भी हो। स्वामित्व का महत्व केवल किराया लेने और समय समय पर 'ओवरहाल, करने के मामले में होता हैं। १९६१ से १९६३ तक २,६२,८३५ वैगन

(भरे हुए और खाली) पाकिस्तान रेलवे से भारतीय रेलों को भेजे गये थे और २,६३,१८५ वैगन भारतीय रेलवे से पाकिस्तान रेलवे को भेजे गये थे। हमारे देश में एक देश के वैगन ढूंढने का काम एक वर्ष छोड़कर अगले वर्ष वैगन गणना के द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य बातों के साथ इस बात का अभिलेख रखा जाता है जिसमें किसी देश के वैगन प्रत्येक मास के अन्तिम दिन हमारे देश में कितने हैं यह दर्शाया जाता है।

(ग) अनुमानत : ७०,१५९ मीट्रिक टन जिसमें अफगानिस्तान भेजा गया ५,८५२ मीट्रिक टन सम्मिलित है।

स्मृति टिकट

८२१. **श्री कपूर सिंह :**
श्री गुलशन :
श्री बूटा सिंह :

क्या **डाक और तार** मंत्री १८ फरवरी, १९६४ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या देश तथा राष्ट्र के प्रति सिख की सेवाओं या महत्व को मनाने के लिये कोई विशेष टिकट जारी किया गया है ?

डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : जी हां।

'कैरेवेल' सेवायें

८२२. **श्रीमती शारदा मुकर्जी** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कैरेवैल सेवाएं अनुमानित समय के अनुसार नहीं चल रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या कारण हैं ?

परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) और (ख) कैरेवैल सेवाएं १ फरवरी १९६४ से जारी की गई थीं। यातायात, भोजन प्रबंध, संचालन तथा इंजीनियरिंग के कारण इन सेवाओं को चलाने में विलम्ब हुआ है ; किन्तु इन को साधारण प्रारंभिक कठिनाईयां मानना चाहिये जो नवीन प्रकार का विमान चालू करने में हुआ करती हैं।

चीनी

८२३. **श्री शिवमूर्ति स्वामी**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितनी चीनी फैक्टरियों ने चीनी की कमी के बारे में सरकार को अभ्यावेदन दिया है ; और

(ख) क्या मैसूर राज्य के तुंगभद्रा क्षेत्र के गन्ना उत्पादकों से यह शिकायत आई है कि चीनी फैक्टरियों की कमी के कारण गन्ना बेकार पड़ा है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ ०ब० थामस) : (क) देश की प्राय: सभी फैक्टरियों को, विशेष कर गुड़ उत्पादक क्षेत्रों में, गन्ने की कमी अनुभव हो रही है।

(ख) जी नहीं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

श्री टैलबट की भारत यात्रा

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : मैं प्रधान मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और उन से अनुरोध करता हूं कि वह उस के बारे में एक वक्तव्य दें :—

"अमरीका और ब्रिटेन द्वारा पेश की गयी काश्मीर को स्वायत्र बनाने की कथित योजना"।

बिना विभाग के मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : यह ठीक है कि श्री टैलबट इस मास ६ तारीख को भारत आ रहे हैं, परन्तु जो कुछ समाचारपत्रों में छपा है वह केवल एक प्रैस की खबर है और एक कल्पना-मात्र ही है। हमारा काश्मीर के बारे में जो दृष्टिकोण है वह हमारी प्रतिनिधि द्वारा सुरक्षा परिषद में स्पष्ट कर दिया गया था, और हम उसमें कदापि परिवर्तन नहीं करेंगे।

कुछ माननीय सदस्य उठे —

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि इस समय इस बारे में कुछ अन्य प्रश्न पूछना अनुचित होगा। इस मामले को फिर उठाया जा सकता है।

सभा पटल पर रखा गया पत्र
PAPER LAID ON THE TABLE

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ के अन्तर्गत चावल (मद्रास) मूल्य नियंत्रण आदेश

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस) : मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत दिनांक २२ फरवरी, १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २६० में प्रकाशित चावल (मद्रास) मूल्य नियंत्रण (दूसरा संशोधन) आदेश, १९६४ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० २४३५/६४]

लोक लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

बीसवां प्रतिवेदन

श्री त्यागी (देहरादून) : मैं वैदेशिक-कार्य, खाद्य तथा कृषि, स्वास्थ्य, गृह-कार्य, सूचना और प्रसारण, श्रम और रोजगार और विधि मंत्रालयों सम्बन्धी विनियोग लेखे (असैनिक), १९६१–६२ और लेखा-परीक्षा (असैनिक), १९६३ के बारे में लोक लेखा समिति का बीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

सभापति तालिका
PANEL OF CHAIRMEN

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि मैं ने श्री सोनावने को सभापति-तालिका के वर्तमान सदस्यों के अतिरिक्त सभापति-तालिका का सदस्य मनोनीत किया है ।

दिल्ली राज्य केन्द्रीय सहकारी स्टोर द्वारा किये गये गुड़ के सौदे के बारे में वक्तव्य
STATEMENT RE : DELHI STATE CENTRAL CO-OPERATIVE STORES' DEALINGS IN GUR

विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : १८-११-१९६३ को गुड़ वहन नियंत्रण आदेश, १९६३ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश से ३०० टन गुड़ के आयात के लिये दिल्ली राज्य सहकारी स्टोर लिमिटेड को एक परमिट जारी किया गया । गुड़ के व्यापार के लिये लाईसेंस में एक ही स्थान उल्लिखित था, ८/४, डी० बी० गुप्त रोड, दिल्ली । २९-११-१९६३ की संस्था की सचिव, मिस सुलहन द्वारा खाद्य तथा असैनिक सम्भरण निदेशक को बताया गया कि गुड़ मेदागंज, फूटा रोड, नंगलोई, रीगल भवन एवं जगननाथ मार्केट नामक पांच डिपुओं में स्टोर किया जा रहा है । यह भी बताया गया है कि निदेशक ने इस के लिये जुबानी अनुमति दे दी थी । एसा प्रतीत होता है कि मेदागंज, फूटा रोड, नंगलोई और नजफगढ़ के डिपुओं में ५० क्विंटल से अधिक गुड़ रखा गया और उस की इतनी मात्रा में वहां पर बिक्री भी की गयी, जिससे दिल्ली खांडसारी तथा गुल व्यापारी लाईसेंसिंग आदेश के खण्ड (३) का उल्लंघन होता है । निदेशालय द्वारा इन स्थानों पर बिक्री के लिये अनुमति नहीं दी गयी थी । ५ दिसम्बर, १९६३ से पूर्व ८० से ८५ रुपये प्रति क्विंटल की दर से वहां गुड़ बेचा गया और बाद में थोक में ६६ रुपये से ६९ रुपये प्रति क्विंटल की दर से और फुटकर में ६९ से ७१ रुपये प्रति क्विंटल की दर से बचा गया । उस समय निदेशक द्वारा गुड़ की बिक्री के लिये कोई मूल्य निर्धारित नहीं किया गया था ।

६ दिसम्बर १९६३ को गुड़ की कीमत निदेशक द्वारा निम्न प्रकार निर्धारित की गयी :—

गुड़ की किस्म	क्विंटल में मात्रा	प्रति क्विंटल थोक के लिये दर
१. गुड़ पन्सेरा .	७२६.३०	६६.००
२. गुड़ चाकू	२४१.१९	६८.००
३. गुड़ खुरपा . .	६४९.४९	६९.००
४. गुड़ लड्डू	१९८.२५	६९.००

इस प्रकार मूल्य निर्धारण के पश्चात् स्टोर द्वारा इस से अधिक दरों पर गुड़ नहीं बेचा गया ।

[श्री अ० कु० सेन]

दिल्ली प्रशासन द्वारा सचिव, विधि मंत्रालय से राय पूछने पर बताया गया कि बिना लाईसेंस के स्थानों से गुड़ बचा गया इसलिये उस के बारे में उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध मुकद्दमा चलाया जा सकता है। परन्तु अधिक दरों के बारे में मुकद्दमा नहीं चलाया जा सकता क्योंकि मूल्य निर्धारण के पश्चात् निर्धारित मूल्यों से अधिक दर पर गुड़ नहीं बेचा गया। महा-अभ्यर्थी भी सचिव की राय से सहमत हुए।

तदनुसार, स्टोर के प्रबन्ध-निदेशक, श्री राम लाल, और सचिव, मिस सुलहन, के विरुद्ध दिल्ली के प्रथम श्रेणी के दण्डाधीश के समक्ष अत्यावश्यक पण्य अधिनियम की धारा ७ के अन्तर्गत मुकद्दमा चलाया गया है। आरोप यह है कि बिना लाईसेंस वाले स्थानों से ५० क्विंटल से अधिक गुड़ बेचा गया। मामला अभी लम्बित है।

Shri Prakash Vir Shastri: (Bijnaur) Whether it is a fact that ordinarily cases of this nature are not referred to the Law Ministry, and if so, whether this particular case was referred with a view to shield a political man?

श्री अ० कु० सेन : सभी तरह के महत्वपूर्ण मामले विधि मंत्रालय को निर्दिष्ट किये जाते हैं। यह बात गलत है कि किसी व्यक्ति विशेष को बचाने के लिये इस मामले में इस प्रकार की कार्यवाही की गयी।

Mr. Speaker: Only questions for clarifications can be asked on this Statement. I have allowed half-an-hour discussion tomorrrow and hon. Members may ask question tomorrow.

Shri Prakash Vir Shastri: But the Law Minister can tell us the names which are there in the police report.

श्री अ० कु० सेन चूंकि यह मामला विचाराधीन है इस लिये मैं ब्योरे में नहीं जाना चाहता। जिन लोगों पर गुड़ की बिक्री संबंधी आरोप हैं उन के नाम मैं बता सकता हूं।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : केन्द्रीय सहकारी स्टोर के चेयरमैन के विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

श्री नाथ पाई (राजापुर) : क्या यह सच है कि निदेशक के कहने के बावजूद भी गुड़ उच्च मूल्यों पर बेचा गया और क्या अपनी शिकायत में निदेशक ने उस बात की भी चर्चा की थी ?

श्री अ० कु० सेन : निदेश ने ६ दिसम्बर से पहले मूल्यों के निर्धारण के विषय में कुछ नहीं कहा।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad): Has the Law Ministry received any material from the Delhi Administration regarding misappropriation of accounts on the part of Shri Brahm Prakash, by selling Gur at excessive rates?

श्री अ० कु० सेन : यदि आप का प्रश्न यह है कि निर्धारित मूल्यों से अधिक दर पर गुड़ बेचने पर अत्यावश्यक पण्य अधिनियम का उल्लंघन होता है, तो पहले इस बात का सबूत चाहिए कि गुड़ निर्धारित मूल्यों से अधिक मूल्यों पर बेचा गया। परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं हुआ प्रतीत होता।

Dr. Ram Manohar Lohia : It is most unfair on the part of Government to evade my question. My simple question was whether the Government is seized of any evidence according to which there has been misappropriation of accounts under section 477, and a conspiracy against the Government under section 120.

श्री अ० कु० सेन : इस प्रकार की कोई शिकायत मंत्रालय के पास नहीं आई । यदि कोई शिकायत की गई तो हम निश्चय ही उस पर विचार करेंगे और अपनी निष्पक्ष राय देंगे ।

बोनस आयोग के प्रतिवेदन के बारे में वक्तव्य

STATEMENT re : REPORT OF BONUS COMMISSION

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : मैं श्री र० कि० मालवीय की ओर से बोनस आयोग के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० २४३६/६४]

यह प्रतिवेदन अभी सरकार के विचारारधीन है इसलिये इस समय यह कहना सम्भव नहीं है कि सरकार का निर्णय क्या होगा ।

श्री बाजी (इन्दौर) : क्या सरकार इसी सत्र के दौरान कोई निर्णय ले लेगी ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : यह महत्वपूर्ण विषय है। एक विमति टिप्पण भी इस प्रतिवेदन में है। मैं यही कह सकता हूं कि यथासम्भव शीघ्र इस बारे में निर्णय ले लिया जायगा ।

विनियोग (रेलवे) विधेयक, १९६४

APPROPRIATION (RAILWAYS) BILL, 1964

रेलवे मंत्री (श्री दासप्पा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९६४–६५ में रेलवे के निमित्त प्रयोग के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों के भुगतान और विनियोजन का प्राधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> 'कि वित्तीय वर्ष १९६४–६५ में रेलवे के निमित्त प्रयोग के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों के भुगतान और विनियोजन का प्राधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड १, २, ३, अनुसूची, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted

खण्ड १, २, ३, अनुसूची, अधिनियम, सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 1, 2, 3, the Schedule, the Enacting Formula and the long Title were added to the Bill :

श्री दासप्पा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाय ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया गया ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

दिल्ली राज्य केन्द्रीय सहकारी स्टोर द्वारा किये गये गुड के सौदे के बारे में वक्तव्य—जारी

STATEMENT *RE* : DELHI STATE CENTRAL CO-OPERATIVE STORES' DEALINGS IN GUR—*contd.*

विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : डा० लोहिया द्वारा पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर में मैं कुछ शुद्धि करना चाहता हूं । हिसाब-किताब में गड़बड़ करने संबंधी आरोप सभी द्वारा लगाये गये थे, चूंकि इस के साक्ष्य के रूप में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये, इसलिये इस बारे में कोई राय देना सम्भव नहीं है । **(अन्तर्बाधायें)।**

अध्यक्ष महोदय : इस का अर्थ यह हैं कि हिसाब-किताब में गड़बड़ संबंधी प्रश्न भी मंत्रालय की राय के लिये निर्दिष्ट किया गया था ।

श्री अ० कु० सेन : कोई दस्तावेज निर्दिष्ट नहीं किये गये **(अन्तर्बाधायें)**

श्री नाथ पाई: मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । आरोप ४७७-क, २०-ख और ३४ धाराओं से संबंधित थे । इन में से एक हिसाब-किताब में गड़बड़ संबंधी था । और यह प्रतिवेदन पुलिस द्वारा दिल्ली प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत किया गया था ।

श्री अ० कु० सेन : मैं जांच प्रतिवेदन के बारे में चर्चा नहीं करूंगा, चूंकि मैं जांच अधिकारी की ओर से वक्तव्य नहीं दे रहा हूं। (**अन्तर्बाधायें**) हमारे पास कोई ऐसे दस्तावेज नहीं भेजे गये जिनसे यह साबित हो सके कि लेखों में किसी प्रकार की गड़बड़ हुई।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : परन्तु मंत्रालय द्वारा ऐसे दस्तावेजों की मांग भी तो नहीं की गयी।

अध्यक्ष महोदय : पहले तो माननीय मंत्री ने कहा कि हिसाब किताब में गड़बड़ी संबंधी प्रश्न विधि मंत्रालय को निर्दिष्ट ही नहीं किया गया। अब उनका कहना है कि प्रश्न निर्दिष्ट किया गया परन्तु मंत्रालय इस निर्णय पर पहुंचा कि इस प्रकार का आरोप गलत है चूंकि कोई ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह आरोप साबित होता हो।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मंत्रालय द्वारा सम्बद्ध दस्तावेजों की मांग ही नहीं की गयी।

श्री रंगा (चित्तूर) : इस प्रश्न संबंधी दस्तावेजों की मांग करना मंत्रालय का कर्त्तव्य था।

अध्यक्ष महोदय : अब यह माननीय सदस्यों पर निर्भर है कि यदि वह चाहें तो किसी न किसी रूप में इस विषय पर चर्चा उठायें।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad): I will read out a portion that Delhi Police have written to the Law Minister.

"मुज्जफरनगर स्टेशन पर लदान संबंधी व्यय के रूप में स्टोर द्वारा ४००/- रुपये का दावा किया था जिसकी अनुमति निदेशालय द्वारा उपर्युक्त दरों का निर्धारण करते हुए दीं, अब उसके बारे में यह आरोप है कि वह रकम वास्तव में रेलवे स्टाफ को रिश्वत के तौर पर दी गयी।"

Shri Brahm Prakash himself admitted in this House that he had given that bribe. The hon. Law Minister is also aware of this. I can pass on this paper to you, Sir.

Mr. Speaker : The hon. Member knows that if he passes on this paper to the person in authority, some action can be taken. But it will be useless to pass on this paper to me.

Dr. Ram Manohar Lohia : I have faith in you only. In the Government I have no faith, so it won't be of any use if I pass on this paper to the hon. Minister.

सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा

GENERAL BUDGET—GENERAL DISCUSSION

श्री अ० क० गोपालन (कासरगोड़) : यह आयव्ययक बहुत खतरनाक है और इससे लोगों के मन में बहुत भ्रम पैदा हो सकता है। चोरबाजारी के धन को निकलवाने के लिये प्रयास करने की बजाय व्यय-कर लागू करना व्यर्थ है।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

विदेशी विनियोजन के लिये दरवाजे खुले रखे गये हैं। आम जनता की परोक्ष करों में कमी होने की आशायें मिट्टी में मिल गयी हैं। न करों का बोझा कम किया गया है और न मूल्य कम होने की आशा ही बंधती है। अनिवार्य जमा योजना को वापस लेने पर और ग्रामोफोन रिकार्डों आदि पर से परोक्ष कर हटाने से आम लोगों को राहत नहीं मिलती। भूमि-सुधार संबंधी वर्तमान नीति के होते हुए यह आशा नहीं की जा सकती कि उत्पादन बढ़ेगा।

सत्ताधारी दल लोकतंत्रात्मक समाजवाद का नारा केवल लोगों को धोखा देने के लिये लगा रहा है। वस्तुस्थिति उसके बिल्कुल विपरीत है। वित्त मंत्री को आयव्ययक से लोगों का भ्रम कम हुआ है और आशा है कि धीरे धीरे वह समझ जायेंगे कि सरकार के समाजवाद के नारे का सही अर्थ क्या है।

वित्त मंत्री ने अनिवार्य जमा योजना को वापस लिया है परन्तु लोगों को वर्ष १९६३-६४ के लिये इस योजना के अन्तर्गत धन जमा कराने के लिये बाध्य करना अनुचित है। इस से भी अधिक महत्व की बात यह है कि वित्त मंत्री ने निम्न आय वर्ग के लोगों को इस के अतिरिक्त कोई राहत नहीं पहुंचाई। आज मूल्य इतने बढ़ चुके हैं कि आम जनता दबी जा रही है। माननीय मंत्री द्वारा मूल्यों के बढ़ने सम्बन्धी जो आंकड़े उपस्थित किये गये वह भी वास्तविकता पर आधारित नहीं हैं। वर्ष १९५७ की तुलना में अब एक व्यक्ति को ४० प्रतिशत अधिक दाम देने पड़ते हैं और वर्ष १९५९ की तुलना में ३० प्रतिशत अधिक देने पड़ते हैं। इसलिये सरकार को ७ अथवा ८ प्रतिशत मूल्यों में वृद्धि की बात कह कर जनता को धोखा नहीं देना चाहिए।

इतने मूल्यों के इस कदर बढ़ जाने पर मंत्री महोदय ने आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिये केवल २ रुपये महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। आप अनुमान लगाइये कि २ रुपये से वह अपनी कौन-कौन सी आवश्यकतायें पूरी कर सकते हैं। स्वयं शास्त्री जी ने स्वीकार किया था कि यह रकम बहुत कम है। मेरा आपसे निवेदन है कि आज लोग यह नहीं चाहते कि आप उन्हें अधिक भत्ता दें और इस प्रकार उनसे सहानुभूति का प्रदर्शन करें। वह यह चाहते हैं कि आप अत्यावश्यक वस्तुयें उन के लिये उचित मूल्यों पर उपलब्ध करें। आप मूल्यों को बढ़ने से रोकें। इसी से उनकी समस्या का समाधान हो सकता है। मूल्यों का स्तर बना रह सकता है नियंत्रण द्वारा परन्तु मंत्री महोदय नियंत्रणों के विरुद्ध हैं। वह बड़े बड़े व्यापारियों का पक्ष लेकर खाद्यान्न में राज्य द्वारा व्यापार के लिए सहमत नहीं हैं। मूल्यों के बढ़ने में बैंकों द्वारा बहुत बड़ा योगदान दिया गया परन्तु बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के लिये मंत्री महोदय तैयार नहीं हैं। सरकार की नीति से यह स्पष्ट है कि वह गैर सरकारी उपक्रमों और बड़े बड़े व्यापारियों के हित की दृष्टि से नियंत्रण लागू करना नहीं चहती और इसके परिणामस्वरूप मूल्यों को कम करना भी नहीं चाहती।

कृषि उत्पादन पर देश की अर्थ-व्यवस्था निर्भर करती है। इसी के विकास से कच्चे माल की, उद्योगों की और पूंजीनिर्धारण की स्थिति सुधर सकती है। परन्तु सरकार इस क्षेत्र में भी असफल रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि भूमि सुधार संबंधी विधान पारित करने के बावजूद भी आज देश की २० प्रतिशत भूमि २० प्रतिशत जमींदारों के पास है और

स्वयं काम करने वाला किसान आज भी भूमिहीन है । यदि भूमि काश्तकार को न दी गयी तो कृषि उत्पादन कदापि बढ़ नहीं सकता, यह निश्चित बात है । आवश्यकता इस बात की है कि भूमि काश्तकार को देकर उसे बीज, उर्वरक, ऋण आदि संबंधी पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध कीं जायें और उसे मुनाफाखोरों और सट्टेबाजों के पंजों से छुड़ाया जाय। आज जो मूल्य उपभोक्ता देता है उससे कहीं कम उत्पादक को प्राप्त होता है । जो ऋण कृषकों के लिये नियत किया जाता है वह उन लोगों तक पहुंचता ही नहीं । इस लिये खाद्यान्नों का व्यापार राज्य द्वारा किया जाना अनिवार्य है ।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि जहां निम्न आय वर्ग के लोगों को बहुत कम राहत दी गयी है वहां बड़े बड़े व्यापारियों के हित में अधिलाभकर हटा दिया गया है। समवायों पर अधिकर लगाया गया है परन्तु साथ ही उनको छूट भी दी जा रही है । व्यय-कर लगाया गया है परन्तु चोर बाजारी की ३००० करोड़ की रकम को निकलवाने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ।

तीस से १७ वर्ष पूर्व समय था जब कि अपनी अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र बनाने के उद्देश्य से हम विदेशी पूंजी को समाप्त कर सकते थे, जमींदारी उन्मूलन कर सकते थे और एकाधिकार का अन्त कर सकते थे। उस अवसर का लाभ नहीं उठाया गया। और आज जब कि पूंजीवाद की नीति पर चल कर अल्पविकसित देश का पुनरुत्थान नहीं हो सकता, हम इसी नीति का अनुसरण कर रहे हैं। इसी कारण यह दुष्परिणाम हमारे सामने आये हैं।

अब मैं देश में की अर्थव्यवस्था मे एकाधिकार की चर्चा करूंगा । आज समवायों की कुल पूंजी के आधे भाग पर आधा प्रतिशत अंशधारियों का आधिपत्य है । कुल पूंजी जो २५०० करोड़ है उसमें से ६०० करोड़ रुपया केवल दो बड़े साथों के हाथ में है । देश की समूची प्रदत्त पूजी का ४५ प्रतिशत भाग १·३ प्रतिशत समवायों के हाथ में है । कुल ४,१७४ निदेश-पद हैं जिन में से २००० निदेश-पद ४४ व्यक्तियों के पास हैं और शेष २,१७४ निदेशक-पद ५०२ अन्य व्यक्तियों के हाथ में हैं । क्या इसका अर्थ यह नहीं है कि देश मे एकाधिकार बढ़ा है और नर-भक्ष उत्तरोत्तर सशक्त हो रहे हैं? इसके अतिरिक्त २० मुख्य बैंकों के १८८ निदेशक हैं जिनके पास १६४० निदेशक-पद हैं। पांच अन्य मुख्य बैंकों के ५५ निदेशक हैं जिन के पास ६७४ निदेशक-पद हैं। मैं समझता हूं कि यह स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक है । जब तक हम एकाधिकार संबंधी नीति में परिवर्तन नहीं लायेंगे और एकाधिकार को समाप्त नहीं करेंगे, हमारी अर्थ व्यवस्था में सुधार नहीं हो सकता ।

उन्हें हटाने की बात तो एक ओर रही वित्त मंत्री ने उन्हें प्रोत्साहन देने के नाम पर बहुत कुछ दे दिया है । और यह रियायत बहुत ही खतरनाक हद तक पहुंच गयी है । यह तो एकाधिकारियों को समर्थन देने की बात है, क्या यह सब समाजवाद अथवा आर्थिक समानता का निर्माण करेगी, । विवियन बोस जांच समिति, आय कर जांच समिति, समवाय विधि प्रशासन प्रतिवेदन । तमाम प्रतिवेदन भी सरकार के समक्ष आ चुके हैं । उन सब समितियों का काम यही देखना था कि धन एक जगह इकट्ठा न हो और राष्ट्रीय आय का समुचित वितरण हो ।

इस प्रकार की सरकार के वित्त मंत्री को जिसका उद्देश्य समाजवाद की स्थापना हो, यह आशा की जा सकती है कि वह एकाधिकारियों को समाप्त करने का यत्न करेंगे । परन्तु वह

[श्री अ० क० गोपालन]

तो कह रहे हैं कि इस समस्या पर विचार के लिए एक आयोग की स्थापना की जायगी। और इस का उद्देश्य केवल यह है कि इस मांग को टाल दिया जाय। इस समस्या को हल करने में वर्षों लग जायेंगे। यदि इसके लिए कोई प्रतिवेदन भी आया तो उसको कार्यान्वित कभी नहीं किया जायेगा। और इस बीच में एकाधिकारियों को अधिक से अधिक सुविधायें दे दी जायेंगी।

और फिर इस दिशा में सब से खतरनाक बात यह है कि इन एकाधिकारियों का विदेशी पूंजी से बड़ा निकट का सम्बन्ध हो रहा है। १९५० में विदेशी पूंजी ३०० करोड़ की थी। १९६२ में ८५० करोड़ हो गयी। १९५८ में १७ सहयोग करार थे, परन्तु १९६२ में यह १४४२ हो गये। और यह विदेशी पूंजी हमारी अर्थ व्यवस्था के प्रत्येक अंगों में है। यदि विदेशी सहायता बन्द हो जाय तो हमारी सारी अर्थ व्यवस्था के ही समाप्त हो जाने का डर पैदा हो जायेगा। उस समय सरकार को बड़ी भयावह परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। देश के लगभग सभी भागों की ओर से यह मांग हुई है कि एकाधिकारों को समाप्त किया जाय। परन्तु ऐसा नहीं किया गया। देश में काला बाजार और भ्रष्टाचार की निरन्तर वृद्धि हो रही है। इसी तरह बैंकों के राष्ट्रीय करण की मांग को भी ठुकराया जा रहा है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि देश में खतरे के संकेत मिल रहे हैं। निर्माण की भी खतरनाक सीमा आ गयी है। समाचारों के अनुसार सरकार तेल मशीन बनाने के उद्योग और कुछ अन्य बुनियादी उद्योगों को इस बात की अनुमति दे रही है कि वे विदेशी पूंजी ले ले। उन्हें विदेशी पूंजी लगाये जाने की सभी सुविधायें दी जा रही हैं। यह सिद्धांत दोनों सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्रों के उद्योगों पर लागू होगा। मेरा कहना है कि यह देश को गिरवी रखने वाली बात है, इसका सरकार को कोई अधिकार नहीं। सरकार विदेशी पूंजी और देश के एकाधिकारियों के पक्ष में हो रही है।

मेरा निवेदन यह है कि देश के विकास कार्यक्रम के लिए अर्थ व्यवस्था के साधन जुटाने की दृष्टि से यह जरूरी है कि विदेशी व्यापार, विदेशी पूंजी और बैंकों तथा कुछ उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाना चाहिये। खाद्यान्नों का राज्य व्यापार आरम्भ कर दिया जाना चाहिये। मेरा यह भी निवेदन है कि राजाधिदेय बन्द किये जायें। छिपाई हुई रकमों का पता लगाया जाना चाहिए। शराबबन्दी समाप्त कर देनी चाहिए। बजट प्रस्थापनाओं से सामान्य व्यक्ति को कोई लाभ नहीं पहुंच रहा है और यह बजट बड़ा चतुर अथवा खतरनाक बजट है।

श्री रवीन्द्र वर्मा (तिरूवल्ला) : मैं बजट प्रस्थापनाओं का स्वागत करता हूं। यह प्रस्थापनाएं बिलकुल व्यवहारिक तथा यथार्थवादी दृष्टिकोण पर आधारित हैं और इसमें समाजवाद की झलक है। आज देश के समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। देश की प्रतिरक्षा के लिए धन की आवश्यकता है। देश के सामने दोहरा काम है। एक ओर तो यह काम है कि देश की प्रतिरक्षा को मजबूत बनाया जाये और इसके साथ ही यह भी काम है कि आर्थिक विकास की गति तेज की जाय। इस कार्य के लिए आवश्यक धन जुटाना बहुत बड़ा काम है। वित्त मंत्री ने इस बात का प्रयास किया है कि राजस्व एकत्रित करने के ढंगों का आधार दृढ़ बनाया जाये। यह ठीक है कि देश का उत्पादन ३.३ प्रतिशत कम हो गया है। इस बारे में दो राय नहीं हो सकती कि खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए देश को

भरसक प्रयत्न करना चाहिए। फिर भी ऐसे मौके आये हैं जबकि मौसम की खराबी के कारण पैदावार कम हुई और देश को आयात पर निर्भर रहना पड़ा। रूस और चीन जैसे देशों में भी ऐसा हुआ है।

उद्योगों के सम्बन्ध में एक बात बड़े स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिये कि विनियोजन बढ़ाये बिना तेजी से आर्थिक प्रगति नहीं हो सकती। इस बात को ध्यान में रख कर पूंजी जुटानी होगी। वित्त मंत्री ने साफ कहा है कि हमें कराधान और आर्थिक कार्यवाही की अपनी सुगठित बनानी होगी ताकि सभी साधनों का प्रयोग कर सकें, विनियोजन की गति बढ़ा सकें, बुनियादी उद्योगों में विनियोजन की दिशा और रूप नियन्त्रित कर सकें और खेती के लिए आवश्यक उद्योग स्थापित कर सकें जिनसे उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में जो भी असन्तुलन हो उसे दूर कर के कमी दूर कर सकें। सरकार इस बात को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक पग उठाए कि सामान्य व्यापार व्यवसाय बनावटी कमी पैदा करने का साधन न बनें तथा कि मूल्य ऐसे स्तर पर कायम रखे जा सकें जिससे आय को निष्क्रय न बना दिया जाए जो कि एक विकासशील अर्थ-व्यवस्था में क्रय शक्ति के बांटे जाने के फल-स्वरूप प्राप्त होती है।

इसके अतिरिक्त मेरा अनुरोध यह है कि सदन को यह बताया जाए कि उपरोक्त करों के परिणाम स्वरूप अत्यावश्यक वस्तुओं के दाम कहां तक बढ़े हैं? जो कुछ आयव्ययक प्रस्ताव हैं उनसे तो यह स्पष्ट है कि इसमें विवेकपूर्ण ढंग से गरीबों को छूट भी दी गयी है और विनियोजन एवं उन्नति के लिये प्रोत्साहन सम्बन्धी उपबन्ध है। निम्न आय वालों को निश्चय ही आय कर में छूट दी गयी है। उपहार कर तथा सम्पदा शुल्क की दरों को बढ़ाने सम्बन्धी प्रस्ताव समाजवाद एवं विषमताओं को दूर करने की ओर एक कदम है। इस प्रस्ताव का समर्थन उन सभी लोगों द्वारा किया जाना चाहिए जो चाहते हैं कि विषमता की बुराई वंशों तक चलती न रहे।

यह बात भी बड़ी स्पष्ट है कि देश का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति विनियोजन के लिये प्रोत्साहन देने की बात का विरोध नहीं कर सकता। हमें इस मामले में केवल नियंत्रण होर रखना है ताकि यह निश्चित सीमा में ही रहे और हमारी नीतियों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जा सके। यह कहना कि विदेशी विनियोजकों की रियायतें देना देश की आजादी का त्याग करने के बराबर है गलत और भ्रमपूर्ण बात है। कर अपवंचन की समस्या का समाधान हमें प्रभावयुक्त ढंग से करना है। यह खेदजनक बात है कि आय कर के रूप में वसूल की जाने वाली ५६७ करोड़ रुपये की राशि केवल आधार भाग ही वसूल किया गया है। आय-कर अधिनियम में संशोधन संबंधी प्रस्ताव आवश्यक है। संसद् द्वारा जिसने राजस्व की मंजूरी दी गयी है उसे वसूल करना तब तक सम्भव नहीं है जब तक कर-अपवंच को दूर करने संबंधी प्रयास किये जायें।

शुल्क के रूप में लगाई गयी वास्तविक आय के बहुत बड़े अन्तर को कम करने के लिए प्रयास किये जाने चाहिएं। मैं बजट का समर्थन करता हूं।

श्री मी० रू० मसानी (राजकोट): वित्त मंत्री महोदय के बजट में कुछ ठोस प्रस्थापनायें भी हैं जिनका कोई भी ईमानदार आदमी स्वागत करेगा जैसे विकास का अन्तर्सम्बन्ध, कीमतें और अदायगियों का सन्तुलन, कीमतों का नियन्त्रण, सरकारी उपक्रमों का बहुत खेद-

[श्री मी० रू० मसानी]

जनक कार्य और इस बात की आवश्यकता कि उन्हें इससे अधिक लाभ कमाना चाहिए। सामान्यत: यह बड़े खेद की बात है कि ५६७ करोड़ रुपये आय कर के हैं परन्तु केवल ५० प्रतिशत तक ही वसूल किये गये हैं, २७१ करोड़ रुपये अभी बकाया है। १२० करोड़ रुपये पिछले तीन वर्षों में नहीं लिये गये हैं, इसे देखते हुए तो कहना पड़ेगा कि वित्त मंत्री का जो आयकर अधिनियम में प्रस्थापित संशोधन है वह ठीक ही हैं। परन्तु इस बारे में सक्रिय कदम उठाने ही होंगे। इस बारे में मेरा यह भी निवेदन है कि १५ से १७ प्रतिशत का जो आय में अन्तर है उसका भी कुछ सोचा जाना चाहिए। मेरा मतलब यह है कि बचत को प्रोत्साहन देना, विदेशी साम्य पूंजी का स्वागत। मेरे विचार में सरकार ने भी अपने विचारों को त्याग कर व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया है। इसी के लिए ही तो गत छः सात वर्षों से हम लड़ रहे थे। मेरे विचार उपचुनावों के परिणामों से सरकार ने कुछ सीखने का यत्न किया है।

आयव्ययक में ४० करोड़ रुपये के, अतिरिक्त प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की व्यवस्था का कोई औचित्य नहीं है। जनता पहले से ही अनुचित करों के भार से दबी हुई है। योजना आयोग की कसौटी के अनुसार भी अब नये कर लगाने की कोई गुंजायश नहीं रह गई है। माननीय वित्त मंत्री को ये अतिरिक्त कर न लगाकर असैनिक व्यय में कटौती करके आय व्ययक को संतुलित करना चाहिये था। असैनिक कार्यों पर इस अतिरिक्त व्यय से मुद्रास्फीति का खतरा है।

आय-व्ययक देश की साधारण जनता के हित को ध्यान में रख कर तैयार नहीं किया गया है। सरकार को बजट तैयार करते समय ग्रामीण जनता के हित का ध्यान रखना चाहिये था और मिट्टी तेल, वनस्पति, साबुन, दियासलाई आदि ग्रामीण लोगों की आवश्यक वस्तुओं पर से उत्पादन शुल्क हटाया जाना चाहिए था आयव्ययक में किसी प्रकार राहत देना तो दूर रहा, २५ करोड़ रुपये के और अतिरिक्त कर लगाकर उपभोक्ताओं के लिये तंगी पैदा कर दी है। उपभोक्ता का अधिकांश भाग निर्धन होता है।

आयव्ययक में १५ करोड़ रुपये की जो अतिरिक्त प्रत्यक्ष करों की व्यवस्था की गई है, वह बहुत ही जटिल है। मैं, इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के बाद, इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि इसे जांच पड़ताल के लिये संयुक्त समिति को सौंपा जाना चाहिये। सभा को मेरा सुझाव मान लेना चाहिये क्योंकि सभा के पास इसे पारित करने के लिये अभी पर्याप्त समय है।

प्रत्यक्ष करों को दो भागों में बांटा जा सकता है—एक व्यक्तियों पर कर और दूसरा निगम कर। जहां तक व्यक्तियों पर करों का संबंध है, आयकर प्रशुल्क का सरलीकरण तथा १,५००० रुपये से कम आय वालों को अनिवार्य जमा योजना से छूट सराहनीय है। इससे निम्न-मध्य वर्ग के लोगों को थोड़ा लाभ हुआ है। किन्तु दूसरी ओर इस आय-व्ययक में की गई वित्तीय व्यवस्था के अनुसार देश में मुद्रास्फीति होना अवश्यम्भावी है जिससे यह लाभ नहीं के बराबर हो जायेगा।

१५००० रुपये से अधिक आय वालों पर वार्षिकी जमा योजना लागू करने का कोई औचित्य नहीं है। माननीय वित्त मंत्री का यह कहना कि वार्षिकी के रूप में लोगों से लिया गया धन जमा करने वालों का है, लोगों को गुमराह करना है। पुरानी अनिवार्य योजना के अनुसार उस पर कर नहीं लगना था परन्तु वार्षिकी योजना के अन्तर्गत जमा की गई धन राशि और उस पर मिलने वाले ब्याज पर भी कर की व्यवस्था की गई है। इस धन राशि पर केवल कर ही नहीं देना पड़ेगा अपितु उस धन का लाभदायक प्रयोजनों के लिये प्रयोग करना संभव नहीं हो सकेगा।

धनकर की निम्नतम सीमा २ लाख रुपये से कम करके १ लाख कम करने, मृतकर तथा उपहार कर फिर से लगाने का कोई औचित्य नहीं है। इससे देश में पूंजी निर्माण को धक्का पहुंचेगा क्योंकि पूंजी-निर्माण में अधिकतर उन्हीं लोगों का सहयोग होता है जिन पर इन करों का प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार के कर रूस आदि देशों में भी नहीं हैं।

पूंजीगत लाभकर लगाना तीन प्रकार से अनुचित है। इसमें सिद्धान्त रूप में बुराई है। यह आय के अनुपात के अनुसार निर्धारित नहीं किया जाना चाहिये अपितु इसकी कोई उच्चतम सीमा होनी चाहिए जो अब हटा दी गई है। दीर्घकाल के लिये पूंजी लगाने वालों के लिये पूंजीगत लाभ कर से छूट होनी चाहिए जैसा कि अमेरिका आदि देशों में होता है। 'बोनस' के अंश पर लगने वाला लाभ-कर आपत्तिजनक है। मिलने वाले बोनस अंश पर कर लगाना उस लाभ पर कर लगाना है जो प्राप्त नहीं हुआ है। पूंजीगत लाभ कर और व्यय कर से धन को छिपाने के लिये प्रोत्साहन मिला है तथा करापवंचन में वृद्धि होगी।

जहां तक व्यक्तिगत आय का सम्बन्ध है, करों का प्रभाव वेतन पाने वाले तथा अन्य ईमानदार करदाताओं पर पड़ा है। माननीय मंत्री जी का यह अनुमान निराधार सा जान पड़ता है कि कर पद्धति में की गई व्यवस्था से करापवंचन नहीं हो सकेगा। इस से घूस-खोरी को बढ़ावा मिलेगा। लोग करों से बचने के लिये कोई न कोई मार्ग निकाल ही लेंगे।

माननीय वित्त मंत्री ने अधिलाभकर के स्थान पर अधिकर की व्यवस्था की है। वे वाद-विवाद का उत्तर देते समय पिछले वर्ष अधिलाभ कर से प्राप्त हुई वास्तविक आय और प्रस्तावित अधिकर से अगले बारह महीनों में होने वाली प्रत्याशित राशि के बारे में बतायें।

समवायों पर अधिकर की कोई सीमा निर्धारित होनी चाहिये थी। इसे आय के अनुपात से लगाने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि समवाय के एक न्यूनतम अंशधारी तथा एक उच्चतम अंशधारी को बराबर आयकर देना पड़ेगा। रिजर्व बैंक के सर्वेक्षण के अनुसार समवायों का लाभ बहुत कम हो गया है। इसलिये इन पर अधिकर लगाया जाना न्यायसंगत नहीं है।

इस वर्ष पहली बार सभी प्रकार के लाभांशों पर ७½ प्रतिशत कर लगाया गया है जो अनुचित बात है। मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा कि कुछ समवायों को करों में ५ प्रतिशत की छूट दी गई है, किन्तु वे इस अतिरिक्त छूट को वितरण नहीं कर सकेंगे। इसीलिये लाभांशों पर कर भी व्यवस्था की गई है। जिन समवायों को अधिलाभ कर से

[श्री म० रू० मसानी]

छूट नहीं दी गई है और न ही उन्हें उद्योगों की चुनी हुई सूची के अन्तर्गत किसी प्रकार की छूट दी गई है, उन पर यह लाभांश कर लगाने का कोई औचित्य नहीं है । इस प्रकार का कर लगाना अनैतिक और निकृष्ट बात है । इससे समवायों को शेयर जारी करने के स्थान पर बाजार से ऋण लेने के लिये बाध्य होना पड़ेगा । यह सामान्य पूंजी निर्माण के लिए निरुत्साहजनक बात है ।

समवायों को विकास छूट की ३ वर्ष की अवधि बहुत कम है । विकास छूट के बारे में वित्त मंत्री को स्पष्ट और निश्चित वक्तव्य देना चाहिए, नहीं तो उद्योग अनिश्चिता की स्थिति में रहेंगे जो उनके विकास में अत्यन्त हानिकर बात होगी ।

देश के सभी उद्योग महत्वपूर्ण हैं, सरकार द्वारा कुछ उद्योगों को करों में छूट देने के लिये चुन लेना उचित बात नहीं है । सरकार चुनाव में इस प्रकार भेदभाव का बर्ताव करके उद्योगों को निरूत्साहित करती है । स्वतंत्र समाज में उपभोक्ताओं की इच्छानुसार उत्पादन होना चाहिये । इसलिये उपभोक्ताओं को ही अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए उद्योगों के लिये पूर्वता निर्धारित करनी चाहिए । सारे उद्योगों के लिये कर निर्धारण करनी और छूट देने के लिए एक समान मापदंड होना चाहिये । यह अस्थायी भेदभाव आपत्तिजनक है ।

इस समय देश में बेरोजगारी की समस्या गंभीर है । इसलिये सरकार को उन्हीं उद्योगों को प्राथमिकता देनी चाहिये थी जिनमें अधिक से अधिक संख्या में लोग काम पर लगाये जा सकें किन्तु सरकार ने इसके बिल्कुल विपरीत उन उद्योगों को प्राथमिकता दी है जिनमें कम से कम कर्मचारियों की आवश्यकता होती है ।

मंत्री महोदय ने अपने भाषण के (क) में कहीं गई बातों का (ख) भाग में अनुसरण नहीं किया है । ऐसा लगता है भाषण का (ख) भाग राजनैतिक दबाव में तैयार किया गया है । इसमें प्रधान मंत्री के मार्क्सवादी विचारों की झलक जान पड़ती है ।

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : माननीय सदस्य को प्रधान मंत्री पर आक्षेप नहीं करना चाहिए । इसके लिये उत्तरदायी मैं हूं ।

श्री रंगा (चित्तूर) : क्या हम यह समझें कि प्रधान मंत्री किसी बात के लिये उत्तरदायी नहीं हैं ? बजट के लिये सरकार उत्तरदायी है । प्रधान मंत्री सरकार के एक अंग हैं ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : यह ठीक है । सरकार के बारे में कहिए ।

श्री मी० रू० मसानी : मुझे अपने विचार प्रकट करने का अधिकार है । वित्त मंत्री महोदय ने यह बजट अवश्य ही प्रधान मंत्री के दबाव में तैयार किया है ।

जहां तक विदेशी पूंजी का प्रश्न है, मैं इसकी आवश्यकता के बारे में सरकार की सजगता का स्वागत करता हूं किन्तु मंत्री महोदय ने विदेशी पूंजी की व्यवस्था का उल्लेख किया है वह देश की आवश्यकता को देखते हुए अपर्याप्त है ।

श्री जोकिम अल्वा (कनारा) : माननीय सदस्य ने प्रधान मंत्री के प्रति उचित बात नहीं कही है क्योंकि प्रधान मंत्री जी ने कई बार सभा में कहा है कि अभी मार्क्सवादी जीवित है ।

श्री मी० रू० मसानी : माननीय सदस्य ने प्रधान मंत्री के प्रति वफादारी का प्रदर्शन पहली बार ही नहीं किया है अपितु वह सभा के सामने ऐसा कई बार कर चुके हैं।

अल्प विकसित देशों में भारत ही एक ऐसा देश है जहां विदेशी अपनी पूंजी नहीं लगाना चाहते हैं। वित्त मंत्री का यह कहना उचित नहीं कि कुछ निहित स्वार्थ विदेशी पूंजी लगाये जाने के मार्ग में बाधक हैं। देश की आवश्यकता को देखते हुए सरकार को ऐसी परिस्थिति पैदा करनी चाहिये जिससे विदेशी पूंजी को प्रोत्साहन मिले।

मैं एकाधिपत्य तथा धन के केन्द्रीयकरण का विरोधी हूं। इसलिये मैं एकाधिकार तथा धन के केन्द्रित होने के बारे में जांच करने के लिये आयोग नियुक्त करने सम्बन्धी प्रस्ताव का स्वागत करता हूं। यह और भी अच्छी बात होगी यदि यहां भी अमेरिका, ब्रिटेन तथा पश्चिम जर्मनी के समान एकाधिकार विरोधी कानून लागू किया जाये। प्रतिस्पर्धा के युग में एकाधिपत्य अवांछनीय है। आयोग द्वारा पूरी तरह जांच की जानी चाहिए कि एकाधिपत्य एवं धन के केन्द्रित होने के क्या कारण हैं और उन कारणों को दूर करने के उपाय ढूंढ़ने चाहिएं। जांच आयोग में ऐसे व्यक्ति लिये जाने चाहिएं जिनका दृष्टिकोण व्यापक हो आयोग को सरकारी तथा गैर-सरकारी एकाधिपत्यों की जांच करने का पूरा अधिकार होना चाहिए उन पर किसी प्रकार का राजनीतिक दवाब नहीं होना चाहिये। राज्य व्यापार निगम तथा जीवन बीमा निगम, जो सरकारी क्षेत्र में हैं, उसके कार्य क्षेत्र में होने चाहियें। राज्य व्यापार निगम एकाधिकार का अनावश्यक लाभ उठा रहा है। आयात की गई वस्तुओं के यह मनमाने मूल्य लेता है। पिछले वर्ष निगम ने विदेशी राजदूतावासों की कारें खरीद कर, उन्हें ऊंचे मूल्यों में बेच कर काफी धन कमाया है। इस प्रकार के एकाधिपत्य को रोका जाना चाहिए। चाहे वह किसी क्षेत्र में हो।

गैर सरकारी क्षेत्रों को बहुत लांछित किया गया है जो उचित नहीं है। गैरसरकारी क्षेत्रों में भी बहुत से उपक्रम बड़ी ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं। वे सरकार को पूरे कर दे रहे हैं। वे लाभ कमाने के साथ साथ उपभोक्ताओं के हित का भी ध्यान रखते हैं। अभी पिछले साल टाटा ने सरकार की अनुमति प्राप्त हो जाने पर भी कास्टिक सोड़े के मूल्य नहीं बढ़ाये। इस प्रकार के अन्य कई गैर सरकारी उपक्रम हैं जिनका कार्य सुचारू रूप से चल रहा है।

साधारणत: बेईमानी वही उपक्रम करते हैं जिनके मित्र इस सभा में बैठे हैं और जिन्हें विश्वास है कि वे कानून की पकड़ में नहीं आते हैं। मैं इस बारे में विस्तार में न जा कर केवल श्री मालवीया और श्री सिराजुद्दीन वाले मामले की सभा को याद दिलाता हूं। इसी प्रकार इस आय व्ययक से भी भ्रष्टाचारी लोग बड़े आदमियों की आड़ ले कर फायदा उठायेंगे।

इस आय व्ययक से उद्योगों का विकास होने की आशा नहीं है। मूल्यों तथा भुगतान शेष स्थिति भी संतोषजनक नहीं रहेगी, कृषि उत्पादन में भी किसी प्रकार की वृद्धि होने की संभावना नहीं है। इस वर्ष मुद्रास्फीति बढ़ती रहेगी क्योंकि उत्पादन बढ़ाने में किसी प्रकार की सफलता नहीं मिली है और अधिक पूंजी लगाये गये उद्योगों की स्थिति ठीक नहीं है।

[श्री म० रू० मसानी]

अन्त में यह अनुरोध करता हूं कि अनावश्यक व्यय को कम करना चाहिए। अधिक उत्पादक उद्योगों में धन लगाया जाना चाहिये। निर्धनों की सहायता करने के लिये ऐसे उद्योगों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए जिसमें अधिक से अधिक लोगों को काम मिल सके।

श्री खाडिलकर (खेड) : उपाध्यक्ष महोदय, इस आय व्ययक पर बोलने वाले विभिन्न दलों के सदस्यों ने जो इसकी आलोचना की है, वह निराधार है। यह आय व्ययक बड़ी कुशलता से बनाया गया है जिससे प्रजातंत्र में समाज के सारे वर्गों को लाभ होगा।

इस आय व्ययक में कम तथा मध्य आय वाले वर्गों को करों में छूट दे कर थोड़ी सी राहत दी गई है। इसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है जिससे मुद्रास्फीति बढ़ने का खतरा पैदा हो। यह सब से अच्छी बात है कि इस आय व्यथक में कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे करदाता करापवंचन नहीं कर पायेंगे।

{डा० सरोजिनी महिषी पीठासीन हुईं
Dr. Sarojini Mahishi *in the Chair*}

संपदा शुल्क लगाने से दायागत संपदा में कमी होगी किन्तु इसका देश को सुदृढ़ उद्योगों पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। व्यय पर कर लगाने से लोगों में मितव्ययता बढ़ेगी। जिससे पूंजी निर्माण में सहायता मिल सकेगी।

भाषण के प्रथम भाग में जो प्रस्ताव रखे गये हैं वे बहुत जटिल हैं और हमें देखना है कि उनसे जीवन में परिवर्तन लाने और सामाजिक लक्ष्य की प्राप्ति में कहां तक सहायता मिलती है। यदि हमें लोकतन्त्रात्मक ढांचे को बनाये रखना है तो उसके लिए लोगों की मांगों की ओर ध्यान रखना चाहिये।

तीसरी योजना में यह स्वीकार किया गया था कि सामाजिक आर्थिक सम्बन्धों के बारे में ऐसी योजना बनानी चाहिये जिससे राष्ट्रीय आय और रोजगार में वृद्धि हो। भुवनेश्वर के संकल्प में यह स्वीकार किया गया था कि सरकारी उद्योग क्षेत्र का औद्योगिक प्रगति में प्रभाव बढ़ेगा और श्री कामराज ने यह कहा था कि भारत के समाज ने समाजवाद को तो स्वीकार कर ही लिया है अब तो केवल यह देखना है कि जो विधान तैयार किये जा रहे हैं उन से इस लक्ष्य की पूर्ति होती है या नहीं।

यदि भुवनेश्वर के संकल्प की भावना को सजीव रखना है तो हमें देखना है कि ऐसा करने में कहां त्रुटि रह गई है। कलकत्ता के "केपिटल" नामक पत्र ने लिखा है कि कामराज योजना के अनुसार मंत्रिमंडल का पुनर्गठन करने पर जब श्री टी० टी० कृष्णमाचारी को मंत्री बनाया गया तो शेयरों के भाव बढ़ गये थे। वास्तव में सरकार ने नीति को ऐसा मोड़ दिया है कि विदेशी सामान्य पूंजी के लिये दरवाजे खोल दिये हैं। मैं विदेशी पूंजी के विरुद्ध नहीं। वह आवश्यक है। किन्तु यदि आप वित्त मंत्री के भाषण को ध्यानपूर्वक पढ़ें तो आप देखेंगे कि सरकारी उद्योग, गैर-सरकारी उद्योग के अधीन हो जायगा। यह खतरनाक है। अंग्रेजों के शासन काल में हमारे देशी नरेश अंग्रेज व्यापारियों को नौकर रखा करते थे और उनसे शिष्टाचार के ढंग सीखा करते थे। वही हालत आज है और देश मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उन पर निर्भर करता है। मुझे विदेशी पूंजी पर तो

आपत्ति नहीं किन्तु हमें यह अवश्य देखना चाहिये कि देश के संसाधनों का पूरा लाभ उठाया जा चुका है या नहीं। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि गत वर्ष ६० करोड़ रुपये की कपास और १० करोड़ रुपये का धागा विदेश से मंगाया गया। आकाशवाणी में सार्वजनिक संचार की विधि सिखाने के लिये विदेश से एक तकनीकी व्यक्ति भी मंगाया गया है।इस से पता लगता है कि हम विदेश पर कितना निर्भर करने लगे हैं ; बजट में इसी दृष्टिकोण को अपनाया गया है जो अपनायी गयी नीतियों के प्रतिकूल है।

सरकारी उद्योग क्षेत्र आयोजित अनुमान से बहुत पिछड़ गया है। उसका कारण यह है कि प्रबंधकों का दृष्टिकोण समाजवादी नहीं है। एक प्रोफेसर ने इस स्थिति का अध्ययन किया है और उसका कहना है कि सरकारी उद्योग क्षेत्र के प्रबन्धक गैर सरकारी उद्योगों में अपनी किस्मत अजमाने की ताक में रहते हैं।

यदि मूल्यों पर नियंत्रण नहीं किया जाता तो आयोजित अर्थ-व्यवस्था अर्थहीन है क्योंकि तब सट्टेबाजी बढ़ती है। जन सामान्य की आवश्यकता की वस्तुएं मूल्यों की घटबढ़ से मुक्त होनी चाहिमें ।

कुछ लोग कहते हैं कि १००० करोड़ रुपया और कुछ के अनुसार ३००० करोड़ रुपये ऐसा है जिसकी कहीं गणना नहीं की गई। किन्तु यही धन हमारी अर्थ-व्यवस्था का संचालन करता है। अतः यदि कोई गंभीर कदम न उठाये गये तो आर्थिक अनुशासन और मुद्रा सम्बन्धी अनुशासन नष्ट हो जायेगा। इस धन का पता लगाना चाहिये और उसे हिसाब में लाना चाहिये।

मैं सभा से निवेदन करता हूं कि वे बजट की नीति के प्रभाव पर गम्भीरता से विचार करें और आशा है कि वित्त मंत्री इस स्थिति पर मनन करेंगें ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : मैं ने पहले पहल तो यह समझा था कि इस बजट का जन साधारण पर प्रभाव नहीं पड़ेगा किन्तु वित्त विधेयक इतना सरल नहीं है।

प्रतिरक्षा व्यय में इस बजट में वृद्धि सराहनीय है किन्तु गत वर्ष इसके लिए ७५६ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी जबकि वास्तविक व्यय ७२८ करोड़ रुपया हुआ। इसका तो यह अभिप्राय है कि इन आंकड़ों का कोई महत्व नहीं।

हममें से बहुत से लोगों को बजट का अध्ययन करने के लिये उपयुक्त समय नहीं मिलता। १९३१ के अधिनियम में संशोधन करना चाहिये। ताकि इसका अध्ययन करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।

हम सरकारी उद्योग क्षेत्र में इतना अधिक पैसा लगा कर वास्तव में जन साधारण का रक्त चूस रहेहैं। २७०० करोड़ रुपये की पूजी लगा कर आपको केवल १ प्रतिशत मुनाफा मिलता है जबकि गैर सरकारी उद्योगों में लगाय गये ९९२ करोड़ रुपये से प्रति १०० रुपये ०.२५ नये पैसे मिलते हैं।

जनता के धन को लगाकर बर्बाद किया जा रहा है। क्या समाजवाद का यही अर्थ होता है कि सारा धन किसी को भी बांट दिया जाये चाहे वह अपात्र ही क्यों न हो ? इस प्रकार मजदूरों और जनता का रक्त शोषण किया जा रहा है और कुछ बड़े बड़े लोगों की जेबों में धन डाला जा रहा है।

[श्री उ० मू० त्रिवेदी]

हमें सब लोग धन ऋण में देते हैं। इस कारण नहीं कि हम बड़े साहूकार हैं, परन्तु इस लिये कि हम उन से मांगते हैं, प्रो० महालनोबिस द्वारा बनाये गये कार्यक्रम को चलाने के लिये, जिसका कोई परिणाम नहीं निकलता।

हमने अनेक छोटे बड़े देशों से ऋण लिया है। हमें ऋण मांगते हुए शर्म क्यों नहीं आती ? फिर उसका दुरुपयोग करना और भी शर्म की बात है। इसकी जांच होनी चाहिये।

दिल्ली दुग्ध योजना और भारतीय स्वर्ण खानों को देखिये। इन पर बड़ा धन फिजूल खर्च होता है और कोलार स्वर्ण खानों से पर्याप्त स्वर्ण भी नहीं मिलता। फिर उस को क्यों चलाया जाता है ? वहां जो लोग काम करते हैं उनको नई रेलवे लाइन बनाने के काम पर लगा सकते हैं।

सरकारी दफ्तरों में यह हाल है कि कर्मचारी असंतुष्ट हैं। अहमदाबाद के मिल कर्मचारियों को जनवरी में ९६ रुपये महंगाई भत्ता मिला। क्या सरकार के तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को इतना भत्ता दिया जाता है ? यदि निर्वाह व्यय बढ़ गया है, तो जब हम पूंजीपतियों से कर्मचारियों को १०२ रुपये महंगाई भत्ता दिला सकते हैं, तो सरकार क्यों अपने कर्मचारियों को उतना भत्ता नहीं देती ?

सरकारी कर्मचारी कैसे कम वेतन में निर्वाह कर सकता है ? क्या हम उसे भ्रष्टाचार में पड़ने के लिये मजबूर नहीं कर रहे ? इस समय २, ५, और १० रुपये का महंगाई भत्ता उनके प्रति एक मजाक है। सरकार ने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया।

समस्त भारत सरकार देश भर में फैली हुई है। मैं संघीय ढंग की सरकार के पक्ष में हूं। परन्तु सरकार के वर्तमान ढांचे में फिजूल खर्ची बढ़ती है। हजारों सरकारी कर्मचारियों को स्थायी नहीं बनाया जाता, और स्थायी लोगों को कार्य-भारित (वर्क चार्जड) रखा जाता है, अतः उन को साधारण लाभों से वंचित रहना पड़ता है।

मेरे नगर में छोटी अफीम फैक्टरी है, जहां से बड़ी विदेशी मुद्रा कमाई जाती है, जहां के कर्मचारियों को न तो स्थायी बनाया गया है और न वे पेंशन के हकदार बने हैं। उनको वर्षों तक अस्थायी रहना पड़ता है। सरकार ने क्यों उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। सरकार ने अपनी आंखें नहीं खोली, परन्तु समाजवाद का नारा लगाती जा रही है।

डाक तथा तार के कर्मचारियों को लो। रेलवे अपने कर्मचारियों को यात्रा की रियायत देती है और मकान देती है। किन्तु डाक तथा तार कर्मचारियों को बहुत कम वेतन मिलता है। और २५–३० रुपये किराया देना पड़ता है क्योंकि उन को क्वार्टर नहीं मिलते। सरकार अपने कर्मचारियों के प्रति इतनी उदासीन क्यों है ? पिछली बार मंत्री जी ने कुछ करने का आश्वासन दिया था, परन्तु कुछ भी नहीं किया गया। हमें बेचारे कर्मचारियों की हालत को सुधारना चाहिये।

गृह मंत्रालय में भारी खर्च होता है और कोई नियंत्रण नहीं रखा जाता है। केन्द्रीय आरक्षित पुलिस का यह हाल है कि लोग वर्षों तक सेवा करते हैं, उन को पदोन्नत न करके किसी युवक को सीधे भरती करके उनके सिर पर बिठा दिया जाता है। जो मकान बनाये जाते हैं वे चूते रहते हैं।

धन दिया जाता है और ठेकेदार संतुष्ट रहते हैं। इन लोगों के कपड़ों पर भारी खर्च होता है। यह सोचने की बात है कि ६० रुपये वेतन वाला दर्जी कपड़ा कम करके बड़ी भारी इमारतें खड़ी कर लेता है। और कोई जांच उस की नहीं की जाती। यही स्थिति सर्वत्र है।

पहले अल्पसंख्यक मंत्रालय होता है, धीरे धीरे समाप्त हो गया है। जब हम काश्मीर के मामले में सुरक्षा परिषद् में जा सकते हैं, तो कोई कारण नहीं कि हम पूर्वी बंगाल में अल्पसंख्यकों पर हुए अत्याचारों की शिकायत संयुक्त राष्ट्र संघ में न करें। हमारा प्रचार सर्वथा असफल रहा है और फिजूल खर्ची कर रहा है। हजारों लोग मारे गये किन्तु हम सही आंकड़े भी नहीं दे सके।

एक रिपोर्ट के अनुसार अमरीकी नागरिक कादर नोव्स्क मारा गया, क्योंकि वह एक लड़की को उस पर किये जा रहे बलात्कार से बचा रहा था। इसकी भी सूचना संयुक्त राष्ट्र संघ को नहीं दी गई। यदि पाकिस्तान काश्मीर की आजादी की दुहाई दे सकता है, तो हम पूर्वी बंगाल की मुक्ति की दुहाई नहीं दे सकते? मुसलमानों को भी पूर्व पाकिस्तान में डराया जाता है। बंगाली मुसलमान वहां पाकिस्तान का उपनिवेश बनकर नहीं रहना चाहते। तो हम यह समस्त धन किस लिये खर्च कर रहे हैं?

यह शर्म की बात है कि इस बजट में कोई ऐसा उपाय नहीं किया गया जिस से हम देश को समृद्ध कर सकें। यह सर्वथा असफल है।

Shri Raghunath Singh (Varanasi): By the time this budget was presented in the house, 1 lakh 40 thousand refugees had entered Indian territory. But nothing has been provided for them in the budget. Where from the money will come for their rehabilitation. In Assam, Tripura and West Bengal people have come in huge number in one month. Besides, 1 lakh 20 thousand minority community people have requested that they want to come to India. Thus 2 lakh 60 thousands are ready to come to India.. It is a matter of concern that provision has not been made in the budget for them. The allocation for Dandakaranya scheme remaining unaltered.

उपाध्यक्ष-महोदय पीठासीन हुए

(**Mr. Deputy Speaker** in the chair)

If 93 lakhs of Hindus from Pakistan come to India, this budget and economy and plan can not work. After all, on humanitarian ground, and Nehru-Liakat Agreement, it is our duty to provide for these displaced persons.

It is said by same persons that muslims are treated badly in India. 3 lakhs of muslims left India and 9 lakh muslims came to India from Pakistan. Where is the cruelty? Atrocities are committed in East Pakistan and not in India Muslims feel safe in India. 88 lakh 97 thousand refugees have come to India from Pakistan from 1947 upto 1963. Many people have not yet been rehabilitated. If the remaining 93 lakhs come to India, the situation will be still worse. In eight years one and half lakh people come to India, and in one month one lakh forty thousand. This indicates a policy of Pakistan behind it.

The difference in population between West and East Pakistan is only twenty lakhs. Democracy is not established there, because their Government feels

[Shri Raghunath Singh]

that other people will come in power by adult franchise, and East Pakistan will rule over West Pakistan. So their policy is to kill, convert or compell the Minority to quit the country. They want to convert East Pakistan into minority, for that purpose they are compelling Hindus to quit East Pakistan. This is a problem of no single party, but of the Parliament and the entire nation, rather of humanity and the whole world.

Hitler also thought like wise and wanted to extinguish jews. Result is that Hitler and Nazis are no more. This is against humanity that people belonging to a particular religion are not allowed to live there. For what date the charter of Human rights in U. N. has been framed? U. N. interfere even in small matters in Congo and Kashmir, but they are silent on East Bengal situation. If U. N. wants to gain confidence of people they should come forward and fight for humanity alter. There is not a word in the budget about these refugees.

श्री कपूर सिंह : यह बुरा बजट है।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : यह अतः बजट बुरा है।

Shri Raghunath Singh : India, and Pakistan both are members of commonwealth. It was the duty of commonwealth to call leaders of Pakistan and ask them to stop committing of atrocities. Indian public wants some concrete things and not mere slogans.

We shall not retaliate. Muslims in India are our brethern, and we shall safeguard them.

Solution of the problem is that Hindus are not safe in Pakistan. So we should demand that a separate place should be provided for them in Pakistan.

In Jalpaigudi and Cooch Bihar there are 121 enclaves of India and 79 of. Pakistani muslims. But Indian citizens are not allowed to go there. But Pakistan rules over their enclaves. It is a question of prestige and honour. We should defend our enclaves and make arrangements there. If the Government cannot manage and administer them, they should hand over to Pakistan to facilitate movement of people. We do not treat them as refugees if they come to India. Still they are considered our kith and kin. Unless democracy is established in Pakistan and minority communities are given some rights, the problem is not likely to be solved. Two or three districts should be allotted for minorities in East Pakistan.

Shri Yajnik (Ahmadabad): I cannot support the policy underlined in the budget, because it is capitalist oriented. In the previous budget taxes of 245 crores were levied and excise duty of 116 crores was levied on almost all essential commodities. As a result whole prices increased to 8% and retail prices increased more. Throughout the length and breadth of the country there is discentment. We thought that our new finance minister realises the difficulties arising out of indirect taxes. But we see, that Compulsory deposit Scheme has been abolished. But gold control scheme is still with the Minister. That should also be scrapped and thrown in the Jamuna.

Old excise duty has been retained. If relief is given on soap, duty is increased on soda ash. The excise duty has been further raised by 25 crores.

The minister had in a lecture stated in Madras immediately before the general election that taxes should not be levied on essential commodities. Income tax on Direct taxation may be increased and that should be realised speedily.

When we find no change made in the Direct taxes, are disappointed. Corporation tax has been increased by 11 crores. Estate duty has been increased by 3 crores. But wealth tax should have been enhanced. Why more taxes cannot be levied on the property increasing year after year, when heavy taxes have been levied on Kerosene oil and other essential commodities?

Sant Vinoba Bhave urged upon the necessity of going ahead on fast speed towards socialism and checking capitalism. But during so many years no step has been taken. We are charged with the responsibility of defending the Country, and progress simultaneously.

Why can't we levy tax upto 5, 10, 15 or 20 percent on wealth tax? Wealth of capitalists has been increasing year after year.

Finance Minister talks much of equality and removal of economic inequalities, but steps are not taken for that purpose.

Direct taxes have been enhanced by 15 crores, and indirect taxes by 25 crores. I am sure prices are not likely to come down. By the present budget difficulties of an ordinary citizen will increase. Finance Minister has not given any solution of high prices. Control or no control is a different thing. He admits black money as the main cause of high prices. Shri Khadilkar has suggested that the present currency notes may be cancelled and new notes issued. I thought that minister would do it. But I am sorry to note that he has not done that. Speculation, high prices, and hoarding all these trouble the public, but no arrangement is made for Controlling black money.

The minister said that he has provided Rs. 10 crores for Govt. employees. They are utterly disappointed and they will certainly raise a movement. The minister, while referring to investment etc. for industrial development, fented to mention the workers. Some incentives are provided in the Railway budget, but in the general budget, there is no incentive. There is always clash between workers and employers of industries. Why does Govt. not provide additional facilities for them. Welfare of workers is the responsibility of the Govt. Thereby a feeling of confidence will be generated in them and they will be able to increase production.

When the Finance Minister had resigned he had said that a man-eater was after him. But in his budget speech he has tried that somehow then capitalists should invest their money in industries. With the help of capitalists, foreign capitalists are also coming in India, for whom a gate way has been opened by you. By the Combined action of these man-eaters the condition of the country will further deteriorate. In such a condition, the whole Govt. will be in a danger. So I say that the Govt. should seriously consider over these problems.

श्री अब्दुल वहीद (वेल्लोर) : मैं वित्त मंत्री को बधाई देता हूं इतने समाजवादी ढंग का बजट पेश करने के लिये, जिसमें कम आय वाले वर्गों को राहत दी गई है। सम्पत्ति, धन तथा व्यय करों सम्बन्धी प्रस्तावों के द्वारा आर्थिक सत्ता का संयम तोड़ने में सहायता मिलेगी।

[श्री अब्दुल वहीद]

विदेशी पूंजी विनियोजन की कुछ आलोचना की गई है। परन्तु देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए, उद्योगों का विकास करने के लिये इसकी जरूरत है फिर उसके द्वारा विदेशी तकनीकी ज्ञान भी भारत में आयेगा। छोटे उद्योगों को दी गई राहत उनके विकास में लाभदायक होगी।

गैर-सरकारी क्षेत्र की आलोचना की गई है। परन्तु वह क्षेत्र सरकारी क्षेत्र के ही समान है, क्योंकि विविध विधियों के द्वारा सरकार का उन पर नियंत्रण है, निगमित क्षेत्र में जीवन बीमा निगम तथा जनता की पूंजी अधिक है।

जो कर लगाये जाते हैं उनको प्रति मास जमा करना करदाताओं के लिये बहुत कठिन होता है, क्योंकि कई जगह ऐसी सुविधायें उपलब्ध नहीं होतीं। इसलिये मेरा सुझाव है कि अस्थायी रूप से लगाये गये करों को वर्ष के आधार पर एक बार जमा करने की सुविधा दी जाये।

यह संतोष का विषय है कि औद्योगिक उत्पादन में तथा निर्यात में १० प्रतिशत वृद्धि हुई है। साफ की गई खालों और चमड़े का निर्यात व्यापार बढ़ाने की ओर अधिक ध्यान दिया जाये और उनको रियायतें तथा प्रोत्साहन दिये जायें ताकि ये उद्योग पाकिस्तान के साथ मुकाबला करने में समर्थ हो सकें।

भारत के मुसलमान भारत को अपनी मातृभूमि समझते हैं और उनकी देश भक्ति की भावना पर सन्देह नहीं किया जा सकता। परन्तु पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार किये गये हैं, उनके कारण भारत के मुसलमानों की स्थिति खराब हो गई है। यदि पाकिस्तान सरकार मुसलमानों का भला चाहती है तो उसे चाहिये कि वह अल्पसंख्यकों के प्रति उचित व्यवहार करे, अत्याचार न करे। भारत के मुसलमानों की यही इच्छा और राय है कि काश्मीर भारत का अंग है और इसके साथ रहे। काश्मीर पर पाकिस्तान द्वारा किये जाने वाले सभी आक्रमणों के प्रयत्नों को हमें असफल बनाना चाहिये, जो हमारा कर्तव्य होता है। हम पाकिस्तान की कुत्सित इच्छाओं के आगे नहीं झुक सकते। हम ने कभी पाकिस्तान पर आक्रमण करने का विचार नहीं किया, परन्तु हम उनका आक्रमण बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। भारत में मुसलमान पूर्णरूपेण सुरक्षित हैं। मैं पाकिस्तान से अपील करूंगा कि वह अल्पसंख्यकों के साथ मानवोचित व्यवहार करे। भारत के कुछ मुसलमान तो यहां तक चाहते हैं कि पाकिस्तान भी भारत में मिल जाये। पाकिस्तान ने हिन्दुओं को वहां से निकाल कर बड़ा भारी अपराध किया है। मैं हिन्दुओं से भी अपील करूंगा कि वे मुसलमानों को सन्देह की दृष्टि से न देखें। पाकिस्तान हमारे विचारों को बदल नहीं सकता।

श्री राम नाथन चेट्टियार (करुर) : मैं बजट का स्वागत इसलिये करता हूं कि यह साहसपूर्ण एवं प्रगतिशील है। अतः मैं वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अनिवार्य बचत योजना को समाप्त कर दिया है। अब इसके स्थान पर वार्षिकी योजना है, जिस के लिये आय सीमा बढ़ा दी गई है।

एकाधिकारों सम्बन्धी जांच आयोग की नियुक्ति का प्रस्ताव सराहनीय है। यह कांग्रेस दल की नीति के बिल्कुल अनुकूल है।

आलोचना हुई है कि बजट भुवनेश्वर के समाजवाद सम्बन्धी संकल्प के अनुसार नहीं बनाया गया। यह निश्चय ही समाजवाद की ओर एक कदम है, परन्तु वह समाजवाद श्री गोपालन या श्री मसानी के दलों वाले समाजवाद से भिन्न है। हमारे समाजवाद का आधार प्रजातंत्र है। हमें धीरे-धीरे परिवर्तन लाना होगा।

वित्त मंत्री ने किसानों को अनाज के उचित दाम के मिलने के लिये कहा है। किसान दो तिहाई से अधिक हैं और अर्थ-व्यवस्था उन पर आधारित है। वित्त मंत्री ने कहा है कि वह मुख्य मंत्रियों को इस बात की ओर ध्यान देने के लिये प्रेरित करेंगे। किसान को भी जीवनोपयोगी वस्तुएं खरीदनी होती हैं। इन सब के कारण, उन के साथ न्याय होगा ऐसी मुझे आशा है।

करों के बारे में वित्त मंत्री का दृष्टिकोण बहुत उचित है।

वित्त मंत्री ने आय कमाने वाले किसी भी वर्ग के सम्बन्ध में भेदभाव नहीं दिखाया। श्री गोपालन और कुछ कांग्रेसी सदस्यों ने आलोचना की है वित्त मंत्री के दिल में पूंजीपतियों के लिए अधिक सहानुभूति है। किन्तु इस बजट ने आय कर देने वालों में बचत करने की प्रेरणा पैदा की है। यह प्रयत्न सराहनीय है।

मेरा उनसे निवदन है कि वित्त मंत्रालय और योजना आयोग को मूल्य के स्तर की निगरानी रखनी चाहिये नहीं तो किसी प्रकार के सुधार से भी कोई लाभ नहीं होगा।

मेरे राज्य में करूर तालुक की सिंचाई परियोजना बहुत समय से विचाराधीन पड़ी है। उससे बड़े भू-क्षेत्र में सिंचाई होगी और वित्त मंत्री को उसे कार्यान्वित करने के लिए प्रयत्न करना चाहिये।

इसी तरह यदि कांडनगर की परियोजना को कार्यान्वित किया जाये तो उससे कुलीलाई के विस्तृत भू-क्षेत्र की सिंचाई होगी। इस योजना को शीघ्र हाथ में लेना चाहिये।

सेतु समुन्द्रम की परियोजना को मंजूरी दी जा चुकी है। उसके लिए पर्याप्त धन देना चाहिये। कावेरी के क्षेत्र में तेल मिला है। उस सम्बन्ध में योजना आरम्भ करनी चाहिये।

Shri Parashar (Shivpuri): I wished I could welcome this budget but I find this budget has rung the death knell of the socialism. But still I hope that the socialism will not be allowed to be burried like this by the persons who pledged in Bhubneshwar and Avadi for bringing socialism to the country.

Today after 17 years of the advert of freedom the Government have not been able to arrange the supply of water to the people. Budget has made no mention this grave problem which is being faced by the rural population.

It is said in the budget speach that the prices are rising and those will be controlled. But the condition is this that price of wheat has gone upto Rs. 30 per maund.

The actual expenditure incurred on defence during the last year shows that there is a shortfal of rupees 76 lakhs as compared to the budget proposal. So even though the current budget proposals show an increase in this expenditure yet it appears to be jugglery of figures. Our jawans go to the front line with a spirit of sacrifice but it is disappointing to note that they are not supplied with the necessary equipment. Our lines of communication which passes

[Shri Parashar]

through the inaccessible regions are improtected. Those should be properly protected. No attention is paid to the schemes for the security of the country, which are submitted by us.

Unless and until our internal security is strengthened the enemies would be encouraged to commit aggression on us. The state of internal security is much disappointing.

These are several tracts of land in the country, for the development of which nothing is being spent. Tantia Tope laid his life for this land. Government should pay attention to these lands.

The Government has decreased taxes on motor vehicles, Gramophone records and soap. But what is the use of it to the common people.

A commission for Agricultural improvement has been set up but the Chairman of the commission would be a Government official. As a matter of fact a peasant should be appointed as chairman at such Commission. I have seen in U.S.S.R. and Czeckoslovakia that such works are entrusted to the peasants.

We are prepared for all sacrifices but we must live with respect. The Pakistanis attack our borders with impunity and abduct our soldiers. This is disgraceful.

Pakistan is sending refugees to our country in such a great number, and we are sending them protest notes. Now the time has come when we should tell Pakistan in clear terms that Pakistan should provide houses for these rufugees and they should give land to rehabilitate these shelterless people.

The Finance Minister should make radical changes in the budget so that we should be able to achieve the target of socialism.

Shri S. M. Bannerji (Kanpur): Because last year heavy taxes were levied, it was therefore hoped that there would be some relief in the current budget. The abolition of C.D.S. has provided a little relief to the people but we have to see whether the people heavily burdened by taxes have been given any relief.

The budget has not made mention at the unemployment and it is expected that by the end of third plan 120 lakhs of people would be unemployed.

I was hoping that this budget would lay the foundation of socialism but that hope has been shattered.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें ।

इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार ४ मार्च, १९६४/१४ फाल्गुन, १८८५ (शक) को ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, the 4th March 1964/Phalguna 14, 1885 (Saka)